

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963

UTTAR PRADESH MINOR MINERAL (CONCESSION) RULES, 1963



(यथा संशोधित पचासवां संशोधन
दिनांक-22.05.2020 तक)

(AS AMENDED UP TO 50TH AMENDMENT
DATED 22.05.2020)

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963
UTTAR PRADESH MINOR MINERAL (CONCESSION) RULES, 1963

विषय सूची
INDEX

नियम RULES	शीर्षक TITLE	पृष्ठ सं० PAGE NO.
अध्याय-1 प्रारंभिक CHAPTER-I PRELIMINARY		
1	संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार, प्रारम्भ और प्रयुक्ति Short title, extent, commencement and application	H- 1 E-1
2	परिभाषाये Definitions: In these rules, unless the context otherwise requires	H- 1 E-1
3	खनन संकियाये, खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा-पत्र के अधीन होगी Mining Operation to be under a mining lease or mining permit.	H- 2 E-2
अध्याय-2 खनन पट्टे का दिया जाना CHAPTER-II GRANT OF MINING LEASE		
4	खनन पट्टे के दिये जाने पर निर्बन्धन Restriction on the grant of mining lease.	H- 3 E-3
5	खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र Application for grant of mining lease	H- 3 E-3
6	खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र शुल्क और जमा Application fee and deposit for grant of lease.	H- 3 E-3
6-क 6-A	43वां संशोधन से विलोपित Application Fee etc for Renewal of Mining lease Omitted by 43rd Amendment	H- 4 E-4
7	जांच और प्रतिवेदन Enquiry and reports.	H- 4 E-4
8	प्रार्थना-पत्र का निस्तारण Disposal of application.	H- 4 E-4
9	कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकार preferential right of certain persons.	H- 5 E-5
9-क	42वां संशोधन से विलोपित Omitted by 42nd amendment.	H- 5 E-5
10	क्षेत्र का विस्तार जिसके लिये खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सकता है Extent of area for which a mining lease may be granted.	H- 5 E-5
11	पट्टे पर दिये जाने वाल क्षेत्र की लम्बाई और चौड़ाई Length and breadth of the area to be leased.	H- 6 E-6
12	खनन पट्टे की अवधि: Period of mining lease.	H-6 E-6

13	प्रतिभूति जमा Security deposit.	H- 6 E-6
14	पट्टा विलेख तीन मास के भीतर निष्पादित किया जायेगा Lease deed to be executed within three months.	H- 7 E-6
15	शुल्क की वापसी Refund of fee.	H- 8 E-8
16	पट्टे की समाप्ति पर निर्बन्धन Restriction on determination of mining lease.	H- 8 E-8
17	पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का सर्वेक्षण Survey of the area leased.	H-8 E-8
18	भूतल के नीचे की सीमाये Boundaries below the surface.	H-9 E-9
19	पट्टे का संक्रमण Transfer of lease.	H-9 E-9
20	रजिस्टर Registers	H-9 E-9
अध्याय-3 स्वामित्व (रायल्टी) और अपरिहार्य भाटक का भुगतान CHAPTER-III PAYMENT OF ROYALTY AND DEADRENT		
21	स्वामित्व (रायल्टी) Royalty.	H-10 E-9
22	अपरिहार्य भाटक Deed rent.	H-10 E-10
अध्याय-4 नीलाम-पट्टा CHAPTER-IV AUCTION LEASE		
23	ई-निविदा/ ई-नीलामी/ई-निविदा -सह ई-नीलामी पट्टा हेतु क्षेत्र की घोषणा Declaration of area for e-tender/ e-auction /e-tender -cum-e-auction lease	H-11 E-10
24	ई-नीलामी या ई-निविदा या ई-निविदा सह ई-नीलामी से क्षेत्र का वापस लिया जाना Withdrawal of area from e-auction or e-tender or e-auction-Cum-e-tender	H-13 E-12
25	ई-निविदा या ई-नीलामी या ई-निविदा सह ई-नीलामी पट्टा के लिए घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों का रजिस्टर Register of area or areas declared for for e-tender/ e-auction /e-tender -cum-e- auction lease	H-13 E-12
26	पट्टे देने का निर्बन्धन Restriction on grant of lease.	H-13 E-13

27	ई-निविदा/ई-नीलामी/ ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा पट्टा अनुमोदन/स्वीकृत प्रदान किये जाने की प्रक्रिया Procedure for approval/grant of Lease by E-tender/E-auction/E - tender-cum-E-auction	H-14 E-13
27-क	43वां संशोधन से विलोपित। Omitted by 43 rd amendment	H-15 E-14
27-ख	43वां संशोधन से विलोपित। Omitted by 43 rd amendment	H-15 E-14
27-ग	43वां संशोधन से विलोपित। Omitted by 43 rd amendment	H-15 E-14
28	पट्टे का दिया जाना Grant of lease.	H-15 E-14
29	पट्टा विलेख का निष्पादन Execution to lease deed.	H-15 E-14
29क	खनन पट्टा का अभ्यर्ण Surrender of Mining Lease:-	H-16 E-15
30	पट्टा का रजिस्टर Register of lease.	H-16 E-15
अध्याय-5 खनन पट्टे की शर्तें CHAPTER-V CONDITION OF A MINING LEASES		
31	इस अध्याय में उल्लिखित शर्तें सभी पट्टों में लागू होंगी Condition mentioned in this chapter to apply to all leases.	H-16 E-15
32	अन्य खनिजों की खोज Discovery of other mineral.	H-16 E-15
33	विदेशी राष्ट्रिक सेवायोजित नहीं किया जायेगा Foreign national not be employed.	H-16 E-15
34	खनन संक्रियार्यें छः मास के भीतर प्रारम्भ होंगी Mining Operations to commence within six months.	H-16 E-16
35	पट्टा क्षेत्र का सीमांकन, सीमा चिन्हों को परिनिर्मित करना, कोर्डिनेट्स का अवधारण व उनका अनुरक्षण Demarcation of leased area, erection of boundary marks, determination of coordinates and their maintenance	H-18 E-17
36	खनिजों का ठीक-ठीक लेखा रखना Maintenance of correct account of minerals.	H-18 E-18
37	खाईयों, गड्ढों आदि का अभिलेख रखना Maintenance of records of trenches, pits etc.	H-19 E-18
38	पट्टेदार द्वारा मजबूत करना, टेक आदि लगाना Lessee to strengthen, support etc.	H-19 E-18
39	अग्रक्रयाधिकार Right of pre-emption.	H-19 E-18
40	पट्टेदार की स्वतन्त्रताएं, शक्तियाँ और विशेषाधिकार Liberties, powers and privileges of the lease.	H-19 E-18
41	पट्टेदार की स्वतन्त्रताओं शक्तियों और विशेषाधिकारों के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्बन्धन एवं शर्तें Restriction and conditions as to exercise of the liberties, powers and privileges of lessee.	H-20 E-19

42	सभी दावों के विरुद्ध पट्टेदार सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा Lessee to indemnify Government against all claims.	H-21 E-20
43	पट्टेदार, गड्ढों, कूपकों आदि को सुरक्षित अच्छी दशा में रखेगा Lessee to secure and keep in good condition, pits, shafts, etc.	H-21 E-20
44	पट्टेदार, कार्यकारणों के निरीक्षण की अनुमति देगा Lessee to allow inspection of working.	H-21 E-21
45	पट्टेदार दुर्घटना का प्रतिवेदन देगा Lessee to report accident.	H-22 E-21
46	पट्टेदार तौलमशीन की व्यवस्था करेगा Lessee to provide weighing machine. (Omitted by 20th Amendemnt)	H-22 E-21
47	पट्टेदार तौलमशीन की जाँच करने की अनुमति देगा Lessee to allow test of weighing machine. (Omitted by 20th Amendemnt)	H-22 E-21
48	पट्टेदार कोई भी अतिरिक्त आवश्यक धनराशि जमा करेगा Lessee shall deposit any additional amount necessary.	H-22 E-21
49	सरकार द्वारा किये गये व्ययों की वसूली Recovery of expenses incurred by the Government.	H-22 E-21
50	प्रतिभूति जमा का वापस किया जाना Refund of security deposit.	H-22 E-21
अध्याय-6 खनन अनुज्ञा-पत्र CHAPTER-VI MINING PERMIT		
51	खनन अनुज्ञा-पत्र दिये जाने का निर्बंधन Restriction on grant of mining permit.	H-22 E-22
52	खनन अनुज्ञा-पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र Application for grant of mining permit	H-22 E-22
52-क	कृषि भूमि पर खनन अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया Procedure for grant of Mining Permit on Agricultural Land.	H-23 E-22
52-ख	भवन/विकास परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया में प्राप्त खनिज के लिए अनुज्ञा प्रदान करने की प्रक्रिया Procedure for grant of permit for mineral found in the process of construction of Building/Development Projects	H-23 E-23
53	प्रार्थना-पत्र का निस्तारण Disposal of application.	H-23 E-23
53-क	अनुज्ञा-पत्र दिये जाने के लिए कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकार Preferential right of certain persons for grant of permit-Omitted by 26th amendment	H-23 E-23
54	स्वामित्व का जमा किया जाना Deposit of royalty.	H-24 E-23
55	खनन अनुज्ञा-पत्र का जारी किया जाना Issue of mining permit.	H-24 E-23

56	खनन अनुज्ञा-पत्रों का रजिस्टर Register of mining permit.	H-24 E-23
अध्याय-7 उल्लंघन अपराध और शास्तियां CHAPTER-VII CONTRAVENTIONS ,OFFENCES AND PENALTIES		
57	अनाधिकृत खनन के लिए शास्ति Penalty for unauthorised mining.	H-24 E-24
58	स्वामित्व, भाटक या अन्य देयों का भुगतान न करने के परिणाम Consequences of non-payment of royalty, rent or other dues.	H-24 E-24
59	कतिपय शर्तों का उल्लंघन करने के परिणाम consequence of contravention of certain conditions.	H-24 E-24
60	सामान्यतः नियमों और पट्टे की शर्तों क उल्लंघन का परिणाम consequence of contravention of rules and conditions of lease generally.	H-25 E-25
अध्याय-8 विविध CHAPTER-VIII MISCELLANEOUS		
61	प्रत्यक्ष अशुद्धियों को ठीक करने का अधिकार Power of rectify apparent mistake.	H-25 E-25
62	रजिस्ट्रों का निरीक्षण करने दिया जायेगा Register to be open to inspection.	H-26 E-25
63	नाम, राष्ट्रिकता आदि में परिवर्तन की सूचना दी जायेगी Change of name, nationality, etc. to be intimated.	H-26 E-26
64	शुल्कों और जमा का भुगतान कैसे किया जायेगा Mode of payment of fees and deposit.	H-26 E-26
65	छात्रों के प्रशिक्षण के लिये सुविधायें Facilities for training of students.	H-26 E-26
66	निर्धारण करने, प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार Power of assessment, entry and inspection.	H-26 E-26
67	भूमि के स्वामी द्वारा खनन संक्रियाओं पर कोई निबंधन आदि आरोपित नहीं किया जायेगा No restriction etc to be imposed by owner of land on mining operations except demand of compensation.	H-27 E-27
68	विशेष मामलों में नियमों का शिथिल किया जाना Relaxation of rule in special cases.	H-27 E-27
68-क	खानों को आरक्षित करने की राज्य सरकार की शक्ति Power of State Government to reserve mines.	H-27 E-27
69	स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक ठेकेदार के माध्यम से वसूल किया जा सकता है Royalty or dead rent may be collected through contractor.	H-28 E-28
70	खनिज के परिवहन पर निर्बंधन Restriction on transport of minerals.	H-28 E-28
71	प्रतिनिधान Delegation.	H-29 E-29
72	पुनः स्वीकृति के लिये क्षेत्र की उपलब्धता का अधिसूचित किया जाना Availability of area for regrant on mining Lease to be notified.	H-29 E-29

73	विवरणियाँ (रिटनर्स) Returns.	H-29 E-30
74	अपराधों का संज्ञान Cognizance of offences.	H-29 E-30
75	अपराधों का शमन Compounding of offence.	H-29 E-30
76	पुलिस की सहायता Assistance of police	H-30 E-30
77	अपील Appeal.	H-30 E-30
78	पुनरीक्षण Revision.	H-30 E-30
79	शुल्क Fees	H-30 E-30
अध्याय—9 CHAPTER-9		
80—104	डायस्पोर, पायरोफिलाईट, फेल्सफार, कैल्साईट, सिलीका सैण्ड, चायना क्ले, क्वार्ट्ज इत्यादि के प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस, खनन पट्टा के नियम। Grant of prospecting license or mining lease for Diaspore, Pyrophyllite, Felspar, Calcite, Silica Sand China Clay, Quartz, etc.	H-30-37 E-30-37
प्रथम—अनुसूची First Schedule	रायल्टी की दरें Rate of Royalty	38
द्वितीय—अनुसूची Second Schedule	अपरिहार्य भाटक की दरें Rate of Dead Rent	40
तृतीय—अनुसूची Third Schedule	प्रपत्र एम0एम0-1 – खनन पट्टे के लिए प्रार्थना पत्र Form MM-1 - Application for Mining lease (Rule-6)	42
	प्रपत्र एमएम-1(क)—खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए लिए प्रार्थना पत्र Form MM-1-A - Application for renewal of mining lease (Rule-6A) (Omitted)	44
	प्रपत्र एम0एम0-2— खनन पट्टों के लिए प्रार्थना पत्र का रजिस्टर Form MM-2- Register for application of mining lease.(Rule-5)	45
	प्रपत्र एम0एम0-3 – खनन पट्टे का आदर्श प्रपत्र Form MM-3 - Model form of Mining lease (Rule-14)	46
	प्रपत्र एम0एम0-4 – खनन पट्टों का रजिस्टर Form MM-4 - Register of Mining leases (Rule-20)	51
	प्रपत्र एम0एम0-5 – नीलाम पट्टों के लिए विज्ञापित क्षेत्रों का रजिस्टर Form MM-5 - Register of areas advertised for auction lease (25)	52
	प्रपत्र एम0एम0-6 – खनन के लिए नीलाम पट्टे का आदर्श प्रपत्र Form MM-6 - Model form of auction lease (29)	53
	प्रपत्र एम0एम0 7—नीलाम/निविदा/निलाम एवं निविदा पट्टा का रजिस्टर Form MM-7 - Register of auction/tender/tender cum auction lease (Rule- 30)	57

	प्रपत्र एम0एम0-8 – खनन अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन पत्र Form MM-8 - Application of Mining permit (Rule-52)	58
	प्रपत्र एम0एम0-9—खनन अनुज्ञा पत्रों के लिए प्रार्थना पत्रों का रजिस्टर Form MM-9 - Register of Applications for mining permit (Rule 56)	60
	प्रपत्र एम0एम0-10 – खनन अनुज्ञा पत्र का आदर्श प्रपत्र Form MM-10 - Model form of Mining permit (Rule 55)	61
	प्रपत्र एम0एम0-11 – परिवहन प्रपत्र Form MM-11 - Model form of Transportation pass(Rule 70)	62
	प्रपत्र एम0एम0-12 – त्रैमासिक विवरणी Form MM-12 - Quaterly return (Rule 73)	63
	प्रपत्र एम0एम0-13 – अपील या पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना पत्र का आदर्श प्रपत्र Form MM-13 - Model application form for appeal or revision (Rule 77, 78, 79)	64
	प्रपत्र एम0एम0-14 – पारम्परिक रूप से बालू/मौरम/बजरी/बोल्डर के उत्खनन कार्य से जीविका का प्रमाण पत्र Form MM-14 - Certificate to the persons traditionally engaged in excavation of sand/morrum/bajri/boulder [Rule9 (2)]	64
	प्रपत्र एम0 एम0 15(FormMM-15)Application for prospecting License	65
	प्रपत्र एम0एम0 16 (Form MM-16)–Application for Mining lease	67
	प्रपत्र एम0एम0 16 ए(Form MM-16A)–Application for Renewal of mining lease	71
	प्रपत्र एम0एम0 17(Form MM-17)–Ragister of applications for mining lease	73
	प्रपत्र एम0एम0 18(Form MM-18) –Register of Mining leases	73
	प्रपत्र एम0एम0 19(Form MM-19) –Register of applications for prospecting Licenses	74
	प्रपत्र एम0एम0 20–Register of prospecting Licenses	74
चतुर्थ–अनुसूची Fourth Schedule	ई–निविदा/ई–नीलाम की धनराशि जमा की अनुसूची नदी तल में उपलब्ध उपखनिजों हेतु E-Tender/E-Auction amount deposited for River bed Mineral	75
पंचम–अनुसूची Fifth Schedule	ई–निविदा/ई–नीलाम की धनराशि जमा की अनुसूची शेष उपखनिजों हेतु E-Tender/E-Auction amount deposited for other mineral	76

उत्तर प्रदेश सरकार
उद्योग (च) विभाग
विज्ञप्ति

26 अगस्त, 1963 ई०

1575-एम/18-ख-माइन्स एण्ड मिनरल्स (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेन्ट) एक्ट, 1957 (एक्ट संख्या-67/1957) की धारा-15 की उपधारा-(1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्

उत्तर प्रदेश उप-खनिज (परिहार)
नियमावली, 1963,
अध्याय- 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार, प्रारम्भ और प्रयुक्ति-

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 [Uttar Pradesh Minor Mineral(Concession) Rules, 1963]

(2) इनका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) वे गज़ट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रचलित होंगे।

²⁰(4) यह राज्य में उपलब्ध समस्त उपखनिजों पर प्रवृत्त होगी।

⁴⁷2. परिभाषायें:- जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य माइन्स एण्ड मिनरल्स (डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट 1957(एक्ट संख्या-67 आफ 1957) से है।

(ख) "कैप्टिव माइन्स" का तात्पर्य ऐसे खनन पट्टे से होगा जहां पट्टा से उत्खनित खनिज के सम्पूर्ण मात्रा के 50 प्रतिशत से अधिक मात्रा का उपयोग, ऐसे उद्योग में किया जाता हो जिसका स्वामी स्वयं पट्टेदार है।

(ग) "समिति" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा सरकारी अधिसूचना संख्या-4343/ 18-20-90-601/ 87 दिनांक 29 अगस्त, 1990 द्वारा गठित समिति से है, जिसमें जिला अधिकारी अध्यक्ष और निदेशक के प्रतिनिधि तथा प्रभागीय वन अधिकारी सदस्य होंगे और जिसे राज्य सरकार ने नियम 71 के अधीन आरक्षित वन क्षेत्रों के संबंध में अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर दी हो।

(घ) "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश से है।

(ड.) " जिला अधिकारी" से तात्पर्य उस जिले के कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर से है, जिसमें भूमि स्थित है।

20वाँ संशोधन दिनांक- 27.08.1994

47वाँ संशोधन दिनांक- 13.08.2019

- (च) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली की तृतीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्र से है।
- (छ) "स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप" का तात्पर्य चट्टानों के रूप में पाये जाने वाले खनिज से है और जो अपनी उत्पत्ति के स्थान से विस्थापित न हुआ हो।
- (ज) "खनन" और "स्वामी" के वही अर्थ होंगे जो माइन्स एक्ट 1952 (एक्ट, संख्या 35, 1952) में दिये गये हैं।
- (झ) "खनन संक्रियाओं" का तात्पर्य किसी उप खनिज को लब्ध करने के प्रयोजन के लिये की गयी संक्रियाओं (Operation) से है।
- (ञ) "खनन अनुज्ञा-पत्र" का तात्पर्य उस अनुज्ञा-पत्र (परमिट) से है जो इन नियमों के अधीन अनुज्ञा-पत्र में नियत अवधि के भीतर उप-खनिज की निर्दिष्ट मात्रा को निकालने के लिये दिया गया हो।
- (ट) "उप-खनिजों" का तात्पर्य इमारती पत्थर, बजरी (gravel), मामूली मृदा (clay), नियत प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू (Sand) से भिन्न मामूली बालू अथवा किसी ऐसे खनिज से है जिसे केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर घोषित किया है या जिसके उप-खनिज होने के बारे में माइन्स एण्ड मिनरल्स (डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 (1957 की एक्ट संख्या 67) की धारा 3 के खण्ड (इ) के अधीन सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषित करें।
- (ठ) "खनिमुख मूल्य" का तात्पर्य खनिमुख पर या उत्पादन के बिन्दु पर उपखनिज के विक्रय मूल्य से है।
- (ड) "रेलवे" और "रेलवे प्रशासन" के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके लिये इण्डियन रेलवेज एक्ट, 1890 (एक्ट संख्या 9, सन् 1890) में दिये गये हैं।
- (ढ) "अनुसूची" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है।
- (ण) "राज्य" और "राज्य सरकार" का तात्पर्य क्रमशः उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश सरकार से है।

3. **खनन संक्रियाये, खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा-पत्र के अधीन होगी—(1)** कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में किसी ऐसे उप-खनिज की, जिस पर यह नियमावली प्रयोज्य हो, इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा-पत्र की शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन और उनके अनुसार के अतिरिक्त कोई खनन संक्रियायें न कर सकेगा। प्रतिबन्ध यह कि किसी बात का प्रभाव इस नियमावली में प्रारम्भ होने के पूर्व यथाविधि दिये गये खनन पट्टा या अनुज्ञा-पत्र की शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अनुरूप की गई खनन संक्रियाओं पर न पड़ेगा।

³⁷**स्पष्टीकरण:** इस नियमावली के प्रयोजनार्थ ईट एवं मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु हस्तचालन से खुदायी द्वारा अथवा हस्ताचालन से साधारण मृदा, सामान्य मिट्टी को निकालने की क्रिया खनन संक्रियाओं के अन्तर्गत नहीं आयेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी खुदाई अथवा खनन के फलस्वरूप उत्पन्न गड्ढों की गहराई 02 मीटर से अधिक नहीं होगी।

(2) कोई खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा-पत्र इस नियमावली के उपबन्धों से भिन्न प्रकार न दिया जायेगा।

अध्याय-2
खनन पट्टे का दिया जाना

4. **खनन पट्टे के दिये जाने पर निर्बन्धन :-** खनन पट्टा किसी ऐसे व्यक्ति को न दिया जायेगा जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति भारतीय राष्ट्रिक समझा जायेगा :-

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 में यथा परिभाषित "public company" (सार्वजनिक कम्पनी) की दशा में, केवल उस स्थिति में जब कम्पनी के अधिकांश निदेशक भारत के नागरिक हों और उसकी अंशपूर्जी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत ऐसे व्यक्ति धारण करते हों, जो या तो भारत के नागरिक हो या कम्पनीज एक्ट, 1956 में यथा परिभाषित "Companies" (कम्पनियाँ) हों।

(ख) कम्पनीज एक्ट 1956 में यथा परिभाषित "Private Company" (निजी कम्पनी) की दशा में केवल उस स्थिति में जब कम्पनी के सभी सदस्य भारत के नागरिक हों, और

(ग) फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ (other association of individuals) की दशा में, केवल उस स्थिति में जब फर्म के सभी सदस्य भारत के नागरिक हों।

(घ) किसी व्यक्ति विशेष की दशा में, केवल उस स्थिति में जब वह भारत का नागरिक हों।

- 435 खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र-** (1) खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम0एम0-1 में राज्य सरकार को सम्बोधित किया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रार्थना-पत्र जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसा अधिकारी सभी चारों प्रतियों में प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति, उसकी प्राप्ति का स्थान, समय और दिनांक प्रविष्ट करके पृष्ठांकित करेगा। उसकी एक प्रति, प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को तुरन्त लौटा दी जायेगी।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रार्थना-पत्र प्रपत्र एम0एम0-2 में खनन पट्टा प्रार्थना पत्र रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

- 236. खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र शुल्क और जमा-** (1) खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रत्येक प्रार्थना-पत्र के साथ निम्नलिखित होगा :-

³³(क) पाँच हजार रुपये का अप्रतिदेय शुल्क

³³(ख) नियम-17 में विनिर्दिष्ट व्ययों से भिन्न अन्य प्रारम्भिक व्ययों को पूरा करने के लिये दस हजार रुपये की अप्रतिदेय जमा, और

(ग) भू-कर सर्वेक्षण मानचित्र (कैडेस्ट्रल सर्वे मैप) की चार प्रतियां, जिसमें वह क्षेत्र, जिसके लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया है, स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो और भू-कर सर्वेक्षण के अन्तर्गत न आने वाले ऐसे क्षेत्र की स्थिति में धरातल सर्वेक्षण मानचित्र (टोपोग्राफिकल सर्वे मैप) ऐसे पैमाने पर, जिसमें कम से कम 4" = 1 मील हो, की चार प्रतियां जिसमें वह क्षेत्र जिसके लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया हो ठीक-ठीक चिन्हांकित हो।

(घ) जिला अधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा जो जिला अधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि प्रार्थी के विरुद्ध कोई खनन देय राशि बकाया नहीं है :

प्रतिबंध यह है कि जहां प्रार्थी ने यह कथन करते हुये कि राज्य क्षेत्र के भीतर वह कोई खनन पट्टा या कोई अन्य खनिज परिहार धारित नहीं करता है या धारित नहीं किया था, राज्य सरकार के सन्तोषानुसार शपथ-पत्र दे दिया है, वहाँ ऐसे प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(ङ) जहाँ प्रार्थना-पत्र बालू अथवा मोरम अथवा बजरी अथवा बोल्टर अथवा इनमें से कोई भी मिली-जुली अवस्था में उपलब्ध हो, वहाँ आवेदक की जाति और निवास का प्रमाण पत्र।

(च) उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जहाँ आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हो।

²⁹(छ) यदि आवेदित क्षेत्र की यथोस्थिति वार्षिक पट्टा धनराशि अथवा अपरिहार्य भाटक रूपया दो लाख अथवा उससे अधिक हो तो प्रार्थी निम्नलिखित प्राधिकारियों के अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

(एक) आय कर विभाग के प्राधिकृत अधिकारी,

(दो) व्यापार कर विभाग का प्राधिकृत अधिकारी,

(तीन) उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट जहाँ प्रार्थी स्थायी रूप से निवास करता हों,

(चार) उस जिले का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक जहाँ प्रार्थी स्थायी रूप से निवास करता हो।

(2) यदि प्रार्थना-पत्र किसी प्रकार से पूरा नहीं है या उसके साथ उप-नियम (1) में उल्लिखित शुल्क, जमा या अभिलेख नहीं है, तो जिलाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी पन्द्रह दिन की नोटिस द्वारा प्रार्थी से, ऐसे समय के भीतर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रार्थना-पत्र को सभी प्रकार से पूरा करने या शुल्क जमा करने या अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा करेगा और यदि प्रार्थी ऐसे विनिर्दिष्ट समय के अन्दर ऐसा करने में विफल रहता है, तब आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

⁴³6क

43वां संशोधन से विलोपित

⁴³ 7

जांच और प्रतिवेदन- जिलाधिकारी जब तक कि वह खनन पट्टा देने के लिये प्राधिकृत न हो सभी सुसंगत मामलों की जांच करायेगा और खनन पट्टे का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के दिनांक से दो माह के भीतर प्रार्थना पत्र की दो प्रतियां अपने प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार या ऐसे अन्य प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे।

⁴³ 8

प्रार्थना पत्र का निस्तारण-(1) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकारी, इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये और ऐसी अग्रतर जांच जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात आवेदित क्षेत्र के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग के लिये और ऐसी अवधि के लिये जैसी वह उचित समझे खनन पट्टा देने के प्रार्थना-पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है :

प्रतिबंध यह है कि जहाँ खनन-पट्टा देने का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है या क्षेत्र में कमी की जाती है, तो उसके कारण अभिलिखित किये जायेंगे और आवेदक को संसूचित किए जायेंगे।

379 कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकार —(1) जहां क्षेत्र/क्षेत्रों को खनन पट्टा स्वीकृत करने हेतु उनकी उपलब्धता नियम-72 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिला अधिकारी द्वारा घोषित की गयी है, वहाँ उस घोषणा में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान प्राप्त सभी प्रार्थना पत्र एक ही दिन में प्राप्त समझे जायेंगे और उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट बातों पर विचार करने के पश्चात् सभी प्रार्थना पत्रों पर एक साथ विचार किया जायेगा और ऐसे प्रार्थियों में से किसी ऐसे प्रार्थी के पक्ष में, जो उनके द्वारा उचित समझा जाये, खनन पट्टा स्वीकृत किया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट बातें :-

(क) प्रार्थी का खनन संक्रियाओं में विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव;

(ख) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन;

(ग) प्रार्थी द्वारा सेवायोजित या सेवायोजित किये जाने वाले प्राविधिक कर्मचारी वर्ग (स्टाफ) की प्रकृति और गुणवत्ता;

(घ) किसी पूर्व पट्टे या अनुज्ञा पत्र के आधार पर खनन संक्रियाओं को कार्यान्वित करने में और ऐसे पट्टे या अनुज्ञा पत्र की शर्तों या उसके संबंध में किसी विधि के उपबंधों का पालन करने में प्रार्थी का आचरण; और

(ड.) ऐसी अन्य बातें जो राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझी जायें;

(3) उपनियम (1) एवं (2) में किसी बात के होते हुये भी नक्सल प्रभावित ग्रामों जिसे राज्य सरकार द्वारा सामान्य आदेश के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, में स्थित एक तिहाई खनन क्षेत्रों के लिये पट्टा ऐसे स्वयं सहायता समूहों को जिसके सदस्य उसी ग्राम के निवासी हों, जिसमें ऐसा पट्टा स्थित है, को प्रदान किया जायेगा और ऐसे एक तिहाई क्षेत्रों का निर्धारण उस जिले के जिलाधिकारी के द्वारा सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा;

प्रतिबन्ध यह है कि उपनियम (3) के अन्तर्गत अधिमान प्राप्त करने हेतु ऐसे स्वयं सहायता समूह ही पात्र होंगे जिसके कम से कम एक तिहाई सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हों, और ऐसी जातियों के सदस्य, जैसे मल्लाह केवट आदि जो पारम्परिक रूप से बालू के उत्खनन में लगे हो एवं उसी ग्राम के निवासी हो जिसमें वह पट्टा क्षेत्र स्थित है।

⁴² 9क

42वां संशोधन से विलोपित

⁴⁷

10 क्षेत्र का विस्तार जिसके लिये खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सकता है—

(1) बालू या मौरम या बजरी या बोल्टर या इनमें से कोई भी जो मिली-जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के खनन पट्टे की स्वीकृति हेतु न्यूनतम क्षेत्र साधारणतया पाँच हेक्टेयर एवं चट्टानों के रूप में पाये जाने वाले ऐसे खनिज जो अपनी उत्पत्ति के स्थान से विस्थापित न हुआ हो तथा अन्य उप खनिज के खनन पट्टे की स्वीकृति हेतु न्यूनतम क्षेत्र एक हेक्टेयर होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्तानुसार विस्तार वाले क्षेत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में यह उपनियम लागू नहीं होगा।

37वाँ संशोधन दिनांक— 22.10.2014

42वाँ संशोधन दिनांक— 18.05.2017

47वाँ संशोधन दिनांक— 13.08.2019

(2) ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में जो संहत तथा सन्निकट हो अथवा वैज्ञानिक विकास के लिए उपयुक्त न हो, कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

प्रतिबंध यह है कि छोटे निक्षेप के संबंध में जो विखण्डित ढेरों के कारण वैज्ञानिक ढंग से खनन हेतु उपर्युक्त नहीं है, बिना किसी विभाजन के ऐसे निक्षेप के समूह के लिये खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सकता है।

(3) कोई व्यक्ति किसी उप खनिज के संबंध में सिवाय बालू या मौरम या बजरी या बोल्टर के या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, तीन खनन पट्टों से अधिक अर्जित नहीं करेगा जिसमें 25 हेक्टेयर से अधिक का कुल क्षेत्र आच्छादित हो।

प्रतिबंध यह है कि बालू या मौरम या बजरी या बोल्टर या इनमें से कोई भी जो मिली-जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के संबंध में दो से अधिक खनन पट्टे या कुल 50 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश राज्य में किसी व्यक्ति के पक्ष में स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह, उन कारणों में से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी व्यक्ति को एक या एक से अधिक पट्टे, जिसके अन्तर्गत ऊपर उल्लिखित सीमा से अधिक का क्षेत्रफल आच्छादित हो, अर्जित करने की अनुमति दे सकती है।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनों के लिये यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा या दूसरे व्यक्ति के नाम से ऐसा खनन पट्टा अर्जित करे जो स्वयं उसके ही लिये अभिप्रेत हो, तो यह समझा जायेगा कि वह उसे स्वयं अपने लिये अर्जित कर रहा है।

11. पट्टे पर दिये जाने वाले क्षेत्र की लम्बाई और चौड़ाई—

खनन पट्टे के अधीन किसी क्षेत्र की लम्बाई साधारणतया उसकी चौड़ाई के चार गुने से अधिक न हो।

⁴³12. खनन पट्टे की अवधि:

(1) उपनियम (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय बालू या मौरम या बजरी या बोल्टर या इनमें से भी मिली जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, पांच वर्ष की नियत अवधि के लिये एवं अन्य उप खनिजों के संदर्भ में पांच वर्ष की अवधि से कम तथा दस वर्ष से अधिक अवधि के लिये खनन पट्टा नहीं दिया जायेगा।

(2) नदी तल में अनन्य रूप से पाये जाने वाले उपखनिजों से भिन्न उपखनिजों के लिये यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह उन कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी अवधि के लिये खनन पट्टे दे सकती है, जो 10 वर्ष से अधिक हो किन्तु 15 वर्ष से अधिक न हो।

³³13. **प्रतिभूति जमा :-** नियम 14 में अभिदिष्ट विलेख के निष्पादन के पूर्व खनन पट्टे का प्रार्थी पट्टे के निबन्धनों और शर्तों के उचित पालन के लिये 10000/- रुपये (दस हजार रुपये) की निम्नतम सीमा के अधीन वार्षिक अपरिहार्य भाटक (डेड रेन्ट) या पट्टाकृत क्षेत्र की वार्षिक पट्टा धनराशि के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि प्रतिभूति के रूप में, उस प्रकार जमा करेगा, जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे। ऐसी प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज देय न होगा।

21 14. पट्टा विलेख तीन मास के भीतर निष्पादित किया जायेगा—

(1) यदि बालू, मौरम, बजरी और बोल्डर के लिये खनन पट्टा से भिन्न, खनन पट्टा दिये जाने की अनुमति दे दी गई हो तो प्रपत्र एम0एम0-3 में या लगभग उसके समान प्रपत्र में जैसा कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों से अपेक्षित हो, उक्त आज्ञा की सूचना के दिनांक से तीन मास के भीतर, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसकी राज्य सरकार तदर्थ अनुमति दे, पट्टा विलेख निष्पादित किया जायेगा और यदि प्रार्थी की ओर से किसी चूक के कारण उपयुक्त अवधि के भीतर ऐसा पट्टा विलेख निष्पादित न किया जाय तो राज्य सरकार पट्टा देने की अनुमति को रद्द कर सकती है और उस दशा में प्रार्थना पत्र शुल्क और प्रतिभूति धनराशि राज्य सरकार के प्रति जब्त हो जायेगी।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट खनन पट्टे के प्रारम्भ होने का दिनांक वह दिनांक होगा जब उक्त उप नियम के अधीन विलेख निष्पादित किया जाय।

(3) यदि बालू या मौरंग या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो, के लिये खनन पट्टा दिये जाने का आदेश दे दिया गया हो, वहां वार्षिक पट्टा धनराशि का पच्चीस प्रतिशत, आदेश के दिनांक से सात दिन के भीतर या सात दिन से अनधिक ऐसी अग्रतर अवधि के भीतर जैसी जिला अधिकारी अनुमति करे, जमा कर दी जायेगी और प्रपत्र एम0एम0-3 में या लगभग उसके समान प्रपत्र में, जैसा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हों, एक पट्टा विलेख, उक्त आदेश के संसूचना के दिनांक से एक माह के भीतर या ऐसी अग्रतर अवधि के भीतर, जैसी राज्य सरकार तदर्थ अनुमति करें, निष्पादित कर दिया जायेगा। बालू एवं मौरम के संबंध में वार्षिक पट्टा धनराशि उस क्षेत्र से विगत तीन वर्षों में प्राप्त धनराशि के औसत के आधार पर या ऐसे क्षेत्र से पूर्ववर्ती वर्ष में प्राप्त धनराशि जो भी उच्चतर हो निर्धारित की जायेगी और बालू, बजरी और बोल्डर या इनमें से जो भी मिली-जुली अवस्था में हो, उन क्षेत्रों में पूर्ववर्ती तीन वर्षों में प्राप्त अधिकतम आय के आधार पर निर्धारित की जायेगी। यदि प्रार्थी की ओर से किसी चूक के कारण उपर्युक्त अवधि में पट्टा धनराशि जमा नहीं की जाती है या पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार पट्टा देने वाले आदेश को प्रतिसंहृत (रद्द) कर सकती है और उस दशा में प्रार्थना पत्र शुल्क प्रतिभूति धनराशि राज्य सरकार के प्रति जब्त हो जायेगा।

(4) उप नियम(3) में विनिर्दिष्ट खनन पट्टे के प्रारम्भ होने का दिनांक उक्त उप नियम के अधीन विलेख निष्पादित किये जाने का दिनांक या वास्तविक रूप से खनन संक्रिया प्रारम्भ किये जाने का दिनांक, इनमें से जो भी पहले हो, होगा।

(5) उप नियम (3) में निर्दिष्ट नीचे अनुसूची के स्तम्भ-1 में उल्लिखित एक वर्ष की अवधि के भीतर स्वीकृत पट्टे की स्थिति में वार्षिक पट्टा धनराशि पट्टे की अवधि के प्रथम तथा अनुवर्ती वर्षों के लिये वार्षिक पट्टा धनराशि के ऐसे प्रतिशत की किशतों में और ऐसे दिनांक के पूर्व, जो उसके सम्बन्धित स्तम्भ में प्रत्येक के सामने उल्लिखित है, जमा की जायेगी, अर्थात:-

जमा की अनुसूची						
अवधि जिसमें पट्टा दिया	उपनियम (3) के अधीन जमा पट्टा धनराशि का प्रतिशत	प्रथम वर्ष की किशतें			अनुवर्ती वर्षों की किशतें	
I	II	III			IV	
		प्रथम Ist	द्वितीय I Ind	तृतीय I I Ird	प्रथम Ist	द्वितीय I Ind
जनवरी से मार्च	25%	25% 1 जुलाई	25% 1 अक्टूबर	25% 1 जनवरी	50% 1 अप्रैल	25% 1 अक्टूबर
अप्रैल से जून	25%	25% 1 अक्टूबर	50% 1 जनवरी	---	25% 1 अक्टूबर	25% 1 जनवरी
जुलाई से सितम्बर	25%	25% 1 जनवरी	50% 1 अप्रैल	----	25% 1 अक्टूबर	25% 1 जनवरी
अक्टूबर से दिसम्बर	25%	50% 1 अप्रैल	25% 1 जुलाई	----	25% 1 अक्टूबर	25% 1 जनवरी

20 15

शुल्क की वापसी—(1) यदि खनन पट्टा दिये जाने के लिये अथवा उसके नवीकरण के लिये प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया जाये तो नियम 6 के उपनियम (1) के अधीन प्रार्थी द्वारा दिया गया शुल्क उसको वापस कर दिया जायेगा।

(2) यदि नियम 6 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन जमा की गई धनराशि या अंशतः उक्त खण्ड में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये व्यय न की गई हो तो वह प्रार्थी को वापस कर दी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये व्यय की जाने वाली धनराशि उसके अधीन जमा की गई धनराशि से अधिक हो, तो प्रार्थी को ऐसी अतिरिक्त धनराशि जमा करनी पड़ेगी जो राज्य सरकार निश्चित करे।

(3) यदि राज्य सरकार किसी विशेष मामले के तथ्यों को ध्यान में रखकर अन्यथा आदेश न दे, प्रार्थना-पत्र शुल्क, प्रार्थना पत्र के वापस लिये जाने पर, वापस न किया जायेगा।

(4) उपनियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुये भी, यदि खनन पट्टा दिये जाने के लिये **या उसके नवीकरण के लिये** प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से किसी चूक के कारण अस्वीकार कर दिया जाये तो प्रार्थना-पत्र शुल्क और प्रारम्भिक व्यय वापस नहीं किया जायेगा और राज्य सरकार के प्रति जब्त हो जायेगा।

20 16.

पट्टे की समाप्ति पर निर्वन्धन— कोई भी पट्टेदार राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देने के पश्चात् ही खनन पट्टा समाप्त करेगा।

47 17.

पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का सर्वेक्षण :-

(1) जब खनन पट्टा दिया जाये तो निदेशक द्वारा पट्टे पर दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन का प्रबन्ध किया जायेगा जिसके लिये पट्टेदार से निम्नलिखित दर से प्रभार लिया जायेगा :-

(क) मैदानी क्षेत्र में :-

(एक) 10 हैक्टेयर तक के क्षेत्र के लिये 5000.00 रूपये।

(दो) 10 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिये 500.00 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से किन्तु कम से कम 6000.00 रूपये।

(ख) पर्वतीय क्षेत्र में :-

(एक) 10 हैक्टेयर तक के क्षेत्र के लिये 8000.00 रूपये।

(दो) 10 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिये 800.00 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से किन्तु कम से कम 10,000.00 रूपये।

(2) पट्टेदार, उसे पट्टा दिये जाने के पश्चात् ट्रेजरी चालान द्वारा सीमांकन प्रभार देगा और पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का जिला अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक मानचित्र, संबंधित खान अधिकारी को या ऐसे अधिकारी को, जिसे निदेशक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, प्रस्तुत करेगा। खान अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी प्रमाणित मानचित्र प्राप्त होने पर और इस बात से **संतुष्ट होने पर कि सीमांकन प्रभार जमा कर दिये गये हैं, ऐसी प्राप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर मानचित्र पर कम से कम दो नियत बिन्दुओं से सन्दर्भ लेकर और सीमांकित पट्टा क्षेत्र के समस्त सीमास्तम्भों के जियो-कोआर्डिनेट्स का उल्लेख कर क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन करेगा।**

(3) खान अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी, क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के प्रयोजनार्थ जिले के राजस्व और वन विभाग के ऐसे अधिकारी की सहायता ले सकता है जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(4) यदि क्षेत्र के सीमांकन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मामला निदेशक को अभिदिष्ट कर दिया जायेगा, जो पक्षकारों की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् मामले का विनिश्चय करेगा।

(5) उपनियम(1) के अधीन निदेशक का विनिश्चय अन्तिम होगा।

18. भूतल के नीचे की सीमायें – खनन पट्टे के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की सीमायें भूतल के नीचे पृथ्वी के केन्द्र की ओर अधोदिशा (vertically) में होगी।

²³19. पट्टे का संकमण— (1) पट्टेदार

(क) किसी खनन पट्टे को या उसमें किसी अधिकार, स्वत्व या हित को न तो अभ्यर्पित करेगा, न शिकमी पर देगा, न बंधक रखेगा और न किसी अन्य रीति से उसका संकमण करेगा, या

(ख) न तो कोई प्रबंध, संविदा या समझौता करेगा, जिसके द्वारा पट्टेदार पर्याप्त मात्रा में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा वित्त पोषित किया जा सकता है या जिसमें खनन संक्रियायें किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय द्वारा पर्याप्त रूप से नियंत्रित की जा सकती हैं।

प्रतिबंध यह है कि पट्टेदार राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जैसा राज्य सरकार द्वारा आरोपित की जाय, खनन पट्टे या उसमें किसी अधिकार, स्वत्व या हित को राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी वित्त निगम अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा (2) के खण्ड (क) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या बैंकिंग कम्पनीय (उपक्रमों या अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की प्रथम अनुसूची के स्तम्भ – 2 में विनिर्दिष्ट किसी बैंक को बंधक कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को अभ्यर्पित कर सकता है।

(2) यदि राज्य सरकार की राय में पट्टेदार ने खनन पट्टे को या उसमें किसी अधिकार, स्वत्व या हित को अभ्यर्पण, शिकमी, बंधक द्वारा या किसी अन्य रीति से किसी को संकमित कर दिया है या राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई प्रबंध, संविदा या समझौता करा लिया है या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट किसी शर्त या निर्बंधन का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय किसी पट्टे को समाप्त कर सकती है।

प्रतिबंध यह भी है कि ऐसा कोई आदेश, पट्टेदार को अपना मामला बताने के लिये युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना, पारित नहीं किया जायेगा।

²⁰20. रजिस्टर— जिला अधिकारी के कार्यालय में निम्नलिखित रजिस्टर रखे जायेंगे :—

(क) प्रपत्र एम0एम0-2 में खनन पट्टों के लिये प्रार्थना-पत्रों का रजिस्टर, और

(ख) प्रपत्र एम0एम0-4 में खनन पट्टों का रजिस्टर।

स्वामित्व (रायल्टी) और अपरिहार्यभाटक का भुगतान

⁴⁸21.

स्वामित्व (रायल्टी)

(1) इस नियमावली के लागू होने के दिनांक को या उसके पश्चात दिये गये खनन पट्टे का धारक, किसी ऐसे खनिज के संबंध में जिसे उसने पट्टे पर दिये गये क्षेत्र से निकाला हो, इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दरों पर स्वामित्व का भुगतान करेगा।

1 (1-क) नियम-3 में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी सम्बन्धित ईट भट्टा मालिकों अथवा साधारण मृदा या साधारण मिट्टी के उपयोगकर्ता को इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित दरों पर स्वामित्व का भुगतान करना होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार ईट भट्टा मालिकों से श्रेणीकृत जिलों के निमित्त, पायों के आधार पर समय-समय पर यथा अधिसूचित दरों पर ऐसा शुल्क ग्रहण करेगी जिसे विनियमन शुल्क के रूप में जाना जायेगा।

(2) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा किसी खनिज के स्वामित्व (Royalty) की दर को ऐसे दिनांक से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, सम्मिलित करने या अपवर्जित करने अथवा बढ़ाने या घटाने के लिये प्रथम अनुसूची को संशोधित कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी खनिज के संबंध में स्वामित्व की दर को तीन वर्ष की किसी अवधि में एक बार से अधिक नहीं बढ़ायेगी और स्वामित्व की दर को खनिमुख मूल्य (Pits mouth value) के 20 प्रतिशत से अधिक दर पर नियत नहीं करेगा।

(3) यदि खनिज के खनिमुख मूल्य पर स्वामित्व लिया जाने वाला हो तो राज्य सरकार ऐसे मूल्य का निर्धारण पट्टा देते समय कर सकती है और स्वामित्व की दर पट्टा विलेख में उल्लिखित की जायेगी। राज्य सरकार वर्ष में अधिक से अधिक एक बार खनिमुख मूल्य का पुनः निर्धारण कर सकेगी, यदि वह इसका बढ़ाया जाना आवश्यक समझें

(4) राज्य के अन्दर अन्य राज्यों से आने वाले खनिजों पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनियमन शुल्क अवधारित किया जा सकेगा।

²²22.

अपरिहार्य भाटक— खनन पट्टे का धारक पट्टे की अवधि में पट्टे के प्रत्येक वर्ष के लिये अपरिहार्य भाटक के रूप में, ऐसी धनराशि का किस्तों में अग्रिम रूप से भुगतान करेगा, जैसी इस नियमावली की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दरों पर राज्य सरकार द्वारा पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट की जायें, और यदि पट्टे की शर्तें उसी क्षेत्र में एक से अधिक खनिज निकालने की अनुमति देती हैं तो ऐसे प्रत्येक खनिज के लिये उक्त अपरिहार्य भाटक का भुगतान पृथक-पृथक रूप से किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि पट्टेदार प्रत्येक खनिज के संबंध में अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व (रायल्टी) की धनराशि का, जो भी अधिक हो, देनदार होगा किन्तु दोनों का नहीं।

अध्याय-4
नीलाम पट्टा

5023. ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा-सह-ई-नीलामी पट्टा हेतु क्षेत्र की घोषणा -

(1) राज्य सरकार सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा **जियो कोआर्डिनेट्स के साथ** ऐसे किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों को, जिसे या जिन्हें ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा पट्टे पर दिया जा सकता है, की घोषणा कर सकती है -

(2) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये-

(क) बालू या मौरम या बजरी या बोल्टर या इनमे से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के संदर्भ में खनन पट्टों के लिये क्षेत्र या क्षेत्रों के पट्टे, एक बार में नियत पांच वर्ष की अवधि के लिये केवल ई-निविदा या ई-नीलामी या ई निविदा सह ई नीलामी के माध्यम से स्वीकृत किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी कारण से दीर्घकाल के लिए नदी तल के खनन क्षेत्रों का व्यवस्थापन किया जाना सम्भव न हो तो उक्त क्षेत्रों का व्यवस्थापन अल्पकालीन खनन अनुज्ञा पत्र के माध्यम से किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित निबन्धन और शर्तों के अधीन अल्पकालीन अनुज्ञा पत्र ई-निविदा/ ई-नीलामी के द्वारा अधिकतम 06 माह की अवधि के लिये स्वीकृत किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह और है कि खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने की दशा में अनुज्ञा पत्र धारक को समस्त देय धनराशियों का संदाय अग्रिम रूप में करना होगा।

(ख) प्राकृतिक चट्टान किस्म के ईमारती पत्थरों के नए क्षेत्र तथा पूर्व में पट्टे पर धृत क्षेत्र जो पट्टे की अवधि की समाप्ति के उपरान्त रिक्त माना जायेगा/माने जायेंगे एवं उसका/उनका नवीनीकरण नहीं किया जायेगा, को अधिकतम बीस वर्ष की अवधि के लिये ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई नीलामी के माध्यम से पट्टाकृत किया जायेगा :-

प्रतिबन्ध यह है कि आशय पत्र जारी किये जाने से पूर्व संबंधित पट्टा क्षेत्र के पूर्ववर्ती पट्टाधारक, जिसका पट्टा हाल ही में समाप्त हुआ हो, को ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त एक कार्य दिवस के भीतर संबंधित पट्टा क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो, प्रस्तुत करने का एक अवसर निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राप्त होगा -

(एक) पूर्ववर्ती पट्टाधारक का आचरण अच्छा रहा है;

(दो) उसने सम्पूर्ण पट्टा अवधि में पट्टा शर्तों का पालन निष्पक्ष रूप से किया है;

(तीन) उसके पास खनिज/ खनन के सम्बन्ध में कोई धनराशि बकाया नहीं है;

(चार) उसका नाम अन्य बातों के साथ- साथ कालीसूची में उल्लिखित नहीं है;

(पाँच) वह संबंधित क्षेत्र अथवा क्षेत्र से अधिक भाग का पट्टाधारक रहा हो तथा तत्सम्बन्ध में प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो;

(छः) ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी से संबंधित अपेक्षित समुचित दस्तावेज/दस्तावेजों के साथ ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से विहित प्रक्रिया/प्रक्रियाओं के अनुसार भाग लिया है।

प्रतिबन्ध यह है कि 02 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक के पट्टाधारक को, पट्टा विलेख निष्पादित किये जाने से 02 वर्ष के भीतर स्टोन क्वेशर स्थापित करना होगा।

(ग) प्राकृतिक रूप से उपलब्ध चट्टान किस्म के ऐसे खनन निक्षेप, जो पूर्व में मुख्य खनिज के रूप में परिभाषित थे तथा जिसे भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0-423 दिनांक 10.02.2015 द्वारा उपखनिज घोषित किया गया है, और अन्तर्निहित ग्रेनाईट से उक्त नये खनन क्षेत्रों को एक बार में अधिकतम 32 वर्षों की अवधि तक के लिये ई-निविदा/ई-नीलामी/ ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से पूर्ववेक्षण अनुज्ञप्ति-सह खनन पट्टा स्वरूप पट्टाकृत किये जायेंगे, तथापि ऊपर उल्लिखित 32 वर्ष की अवधि में से दो वर्ष की अवधि पूर्ववेक्षण कार्यों हेतु तथा पूर्ववेक्षण कार्यों में खनिज की उपलब्धता सिद्ध हो जाने पर खनन पट्टे की अधिकतम अवधि 30 वर्ष होगी।

यदि कोई क्षेत्र, पूर्व में पट्टे पर रहा हो अथवा संबंधित क्षेत्र के भीतर खनिज की उपलब्धता पहले ही स्वीकृत है, तब ऐसे मामलों में खनन पट्टा सीधे अधिकतम तीस वर्ष की अवधि के लिये किये जायेंगे।

50वां संशोधन दिनांक-22.05.2020

प्रतिबन्ध यह है कि आशय पत्र जारी किये जाने के पूर्व संबंधित पट्टा क्षेत्र के पूर्ववर्ती पट्टाधारक, जिसका पट्टा हाल ही में समाप्त हुआ हो, को ई-निविदा / ई-नीलामी / ई-निविदा सह ई-नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त एक कार्य दिवस के भीतर, संबंधित पट्टा क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो, प्रस्तुत करने का एक अवसर निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राप्त होगा:-

(एक) पूर्ववर्ती पट्टाधारक का आचरण अच्छा रहा है;

(दो) उसने सम्पूर्ण पट्टा अवधि में पट्टा शर्तों का पालन निष्पक्ष रूप से किया है;

(तीन) उसके पास खनिज / खनन के सम्बन्ध में कोई धनराशि बकाया नहीं है;

(चार) उसका नाम अन्य बातों के साथ-साथ कालीसूची में उल्लिखित नहीं है;

(पाँच) संबंधित क्षेत्र अथवा क्षेत्र से अधिक भाग का पट्टाधारक रहा हो तथा तत्सम्बन्ध में प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत किया हो;

(छ:) ई-निविदा / ई-नीलामी / ई-निविदा सह ई-नीलामी से संबंधित अपेक्षित समुचित दस्तावेज / दस्तावेजों के साथ ई-निविदा / ई-नीलामी / ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से विहित प्रक्रिया / प्रक्रियाओं के अनुसार भाग लिया है।

(घ) प्राकृतिक रूप से उपलब्ध स्वस्थाने चट्टान किस्म के निजी भूमि के खनिज क्षेत्र, जो न्यूनतम 01 हे० हों, अधिकतम दस वर्ष की अवधि के लिये ई-निविदा / ई-नीलामी / ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से पट्टा पर दिये जायेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित खनन क्षेत्र में, जिलाधिकारी खनिज की उपलब्धता, क्षेत्र की उपयुक्तता, भूस्वामित्व के प्रमाण पत्र, भूस्वामियों की सहमति के शपथ पत्र, की पुष्टि करने के पश्चात् मात्रा एवं अवधि अनधिक 10 वर्ष का निर्धारण करते हुए ई-निविदा / ई-नीलामी / ई-निविदा सह ई-नीलामी की कार्यवाही करेगा। भूस्वामी / स्वामियों द्वारा क्षेत्र की ई-नीलामी पूर्ण होने पर इसके उच्चतम बोली को संज्ञान में लेकर सात कार्य दिवस के भीतर सम्बन्धित क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो, प्रस्तुत करने का उसे / उन्हे एक अवसर प्राप्त होगा। यदि भू स्वामी / स्वामियों द्वारा प्रथम इनकार के इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उच्चतम बिडकर्ता के पक्ष में पट्टा स्वीकृत किया जायेगा तथा भू स्वामी / स्वामियों को प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जा सकेगी, देय होगी, जो राज्य सरकार को संदेय धनराशि के अतिरिक्त होगी। भूस्वामी / स्वामियों को भुगतान प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ किया जाना अनिवार्य होगा।

(ङ) नदी तल में स्थित निजी भूमि के क्षेत्र, जो न्यूनतम 01 हे० हो, जिसमें बालू या मौरम या बजरी या बोल्टर या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में उपलब्ध हों, अधिकतम 06 माह की अवधि के लिये ई-निविदा / ई-नीलामी / ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से पट्टा पर स्वीकृत किये जायेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित खनन क्षेत्र में जिलाधिकारी, खनिज की उपलब्धता, क्षेत्र की उपयुक्तता, भूस्वामित्व के प्रमाण पत्र, भूस्वामियों की सहमति के शपथ पत्र, की पुष्टि करने के पश्चात् मात्रा एवं अवधि अनधिक 06 माह का निर्धारण करते हुए ई-निविदा / ई-नीलामी / ई-निविदा सह ई-नीलामी की कार्यवाही करेगा। भूस्वामी / स्वामियों द्वारा क्षेत्र की ई-नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसके उच्चतम बोली को संज्ञान में लेकर सात कार्य दिवस के भीतर सम्बन्धित पट्टा क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो प्रस्तुत करने का उसे / उन्हे एक अवसर प्राप्त होगा। यदि भू स्वामी / स्वामियों द्वारा प्रथम इनकार के इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उच्चतम बिडकर्ता के पक्ष में पट्टा स्वीकृत किया जायेगा तथा भू स्वामी / स्वामियों को प्रतिकर के रूप में

ऐसी धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जा सकेगी, देय होगी, जो राज्य सरकार को संदेय धनराशि के अतिरिक्त होगी। भूस्वामी / स्वामियों को भुगतान, प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ किया जाना अनिवार्य होगा।

- (3) उपनियम(1) के अधीन क्षेत्र की घोषणा किये जाने पर अध्याय-2, 3, 6 और 9 के उपबन्ध, सिवाय नियम-10, 12, 17 एवं 93 के उस क्षेत्र अथवा क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे जिसके या जिनके संबंध में घोषणा जारी कर दी गयी है। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को इस अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पट्टे पर दिया जा सकता है।
- (4) जिलाधिकारी, उपनियम(1) के अधीन घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ई-निविदा / ई-नीलामी / ई-निविदा सह ई-नीलामी के लिये निर्धारित दिनांक के पूर्व न्यूनतम बोली या प्रस्ताव के निर्धारण के लिये खनिज की गुणवत्ता और मात्रा का मूल्यांकन करायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जिलाधिकारी वर्ष में एक बार शासन द्वारा गठित प्राविधिक समिति के माध्यम से मानसून सत्र समाप्ति पर नदी तल में उपलब्ध उपखनिज की मात्रा का निर्धारण आवश्यकतानुसार करायेगा। पक्षकारों के मध्य असहमति की दशा में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म मामले का विनिश्चय करेगा और ऐसा विनिश्चय अन्तिम होगा।

- ⁴³24. ई-नीलामी या ई-निविदा या ई-निविदा सह ई-नीलामी से क्षेत्र का वापस लिया जाना – राज्य सरकार घोषणा द्वारा नियम 23 के उपनियम (1) के अधीन घोषित किसी क्षेत्र या क्षेत्रों या उसके किसी भाग को उसमें निर्दिष्ट किसी पट्टा प्रथा से वापस ले सकती है और घोषणा में विनिर्दिष्ट वापसी के दिनांक से, जो इस अध्याय के अधीन दिये गये पट्टे की साधारण अवधि के दौरान वापसी का दिनांक न होगा, इस नियमावली के अध्याय 2,3 और 6 के उपबन्ध ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों पर लागू होंगे।
- ⁴³25. ई-निविदा या ई-नीलामी या ई-निविदा सह ई-नीलामी पट्टा के लिए घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों का रजिस्टर— जिला अधिकारी नियम 23 के उपनियम (1) के अधीन घोषित क्षेत्रों का एक रजिस्टर प्रपत्र एम0एम0 5 रखवायेगा।
- ⁴⁷26. पट्टे देने का निर्बन्धन—किसी व्यक्ति को पट्टा हेतु ई-निविदा/ई-नीलामी/ ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने की निम्नलिखित दशा में अनुमति नहीं दी जायेगी –
- (क) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है;
- (ख) जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाये हैं;
- (ग) जिसने जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है, से सम्बन्धित पुलिस सत्यापन के आधार पर जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है;
- (घ) जिसने अपना आधार कार्ड प्रस्तुत न किया हो;
- (ङ) जिसका नाम काली सूची में उल्लिखित हो;
- (च) फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैन सं0 तथा जी0एस0टी0 रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो ;
- (छ) जिसने ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र या ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र के साथ बैंक प्रत्याभूति, जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो, प्रस्तुत न की हो।

- 47 27 ई-निविदा / ई-नीलामी / ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा पट्टा अनुमोदन / स्वीकृति प्रदान किये जाने की प्रक्रिया—
- (1) जहां ई-निविदा / ई-नीलामी / ई-निविदा सह ई-नीलामी स्वीकृत किया जाना समीचीन है, वहां यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट या समिति ई-निविदा / ई-नीलामी / ई-निविदा सह ई-नीलामी के लिये राज्य सरकार द्वारा अवधारित दिनांक, समय और वेब पोर्टल निर्धारित करेगी, जिसकी प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा की राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।
- (2) ई-निविदा / ई-नीलामी / ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से निम्नानुसार पट्टा दिया जायेगा :-
- (क) जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत समिति, सम्बन्धित ई-निविदा / ई-नीलामी / ई-निविदा सह ई-नीलामी से कम से कम तीस दिन पूर्व सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगी, जिसमें ऐसी ई-निविदा / ई-नीलामी / ई-निविदा सह ई-नीलामी के लिये राज्य सरकार द्वारा अवधारित अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक, समय एवं वेब पोर्टल उल्लिखित होगा।
- प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी भी कारण से ई-निविदा / ई-नीलामी / ई-निविदा सह ई-नीलामी पूरी न हुई हो वहां अन्यून सात दिन की अल्प कालिक सूचना देने के पश्चात ऐसी ई-निविदा / ई-नीलामी / ई-निविदा सह ई-नीलामी पुनः पूरी की जा सकती है।
- (ख) ई-निविदा / ई-नीलामी / ई-निविदा सह ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना नीचे दी गयी रीति से प्रकाशित की जायेगी -
- (एक) सूचना की प्रतियां, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित / चरपा की जायेगी।
- (दो) सूचना की एक प्रति राज्य सरकार द्वारा अवधारित वेब पोर्टल या वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी।
- (तीन) जन साधारण की सूचना के लिये सूचना जिले में परिचालित कम से कम दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी, और
- (चार) किसी ऐसी अन्य रीति से, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निदेशित की जाय।
- (ग) जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से नीचे का न हो, को ई-निविदा / ई-नीलामी / ई-निविदा सह ई-नीलामी के प्रयोजन के लिये पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर सकता है।
- (घ) ई-निविदा / ई-नीलामी / ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु क्षेत्र या क्षेत्रों का ब्यौरा तथा पट्टे की निर्बन्धन और शर्तें जारी की जाने वाली सूचना में उल्लिखित की जायेगी।
- (ङ) कोई व्यक्ति, जो ई-निविदा / ई-नीलामी / ई-निविदा सह ई-नीलामी से संबंधित कार्यवाहियों में भाग लेने के लिये इच्छुक हो, पन्द्रह हजार रुपया शुल्क के रूप में जमा करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित और उपबन्धित रूप में अप्रतिदेय होगा।
- (च) ई-निविदा / ई-नीलामी / ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक प्रत्येक बोली लगाने वाले / निविदाकर्ता को ऐसी धनराशि, अग्रिम धनराशि के रूप में जमा करना होगा, जैसा कि सूचना में विहित किया जाये।
- (छ) सफल बोली लगाने वाले / निविदाकर्ता को छोड़कर बोली लगाने वाले / निविदाकर्ताओं द्वारा जमा अग्रिम धन उन्हें वापस कर दी जायेगी।
- (3) पट्टा देने के पश्चात नदी तल उपखनिजों यथा बालू, मौरम, बजरी-बोल्डर के पट्टाधारक, पंचम अनुसूची में यथा उल्लिखित धनराशि का संदाय करेगा और अन्य खनिजों का पट्टाधारक, चतुर्थ अनुसूची में यथा उल्लिखित धनराशि का संदाय करेगा।

⁴³27 क. 43वां संशोधन से विलोपित।

⁴³27 ख. 43वां संशोधन से विलोपित।

⁴³27 ग. 43वां संशोधन से विलोपित।

⁴⁷28. पट्टे का दिया जाना—

- (1) यथास्थिति, जिला अधिकारी या समिति ई—निविदा के मामले में सबसे ऊँचा प्रस्ताव स्वीकार करेगा/करेगी, ई—नीलामी के मामले में उच्चतम बोली, और ई—नीलामी सह ई—निविदा के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को स्वीकार करेगा/करेगी जो सबसे ऊँचा हो।
- (2) जिला मजिस्ट्रेट सम्बन्धित ई—निविदा /ई—नीलामी/ ई—निविदा सह ई—नीलामी के उच्चतम बोली/प्रस्ताव की घोषणा करेगा और एक आशय पत्र उस व्यक्ति को जारी किया जायेगा, जिसकी बोली या प्रस्ताव स्वीकृत हो गया हो, जिसमें निम्न विवरण सम्मिलित होंगे :—

(एक) सफल बोली लगाने वाले को पट्टा विलेख के निष्पादन तथा पट्टे के निबन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिये प्रतिभूति के रूप में बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की प्रथम किश्त के रूप में उतनी ही धनराशि दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करना होगा। अग्रिम धनराशि प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।

(दो) **प्रथम वर्ष के लिए देय धनराशि का निर्धारण, पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण—पत्र में उल्लिखित खनिज की मात्रा** को ई—निविदा/ई—नीलामी में प्राप्त धनराशि की दर से गुणा कर किया जायेगा।

(तीन) अनुवर्ती वर्षों के लिए संदेय धनराशि में पूर्ववर्ती वर्ष की संदेय धनराशि के आधार पर 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जायेगी।

(चार) ई—निविदा/ई—नीलामी की धनराशि का अवधारण नदी तल खनिज, यथा—बालू, मौरम, बजरी, बोल्टर हेतु पंचम अनुसूची के अनुसार और अन्य खनिज हेतु चतुर्थ अनुसूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(पांच) पट्टा के अधीन स्वीकृत किसी क्षेत्र का सीमांकन नियम-17 के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा और सीमास्तम्भ नियम-35 के अनुसार लगाये जायेंगे तथा उनका अनुरक्षण उक्त नियम के अनुसार किया जायेगा।

(छः) पट्टा शर्तों का उल्लेख किया जायेगा।

- (3) यदि जिला मजिस्ट्रेट की राय में ई—निविदा/ई—नीलामी/ई—निविदा सह ई—नीलामी में कोई बोली या प्रस्ताव संतोषजनक न हो, तो वह ई निविदाओं/ई नीलामियों में सभी बोलियों या प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है और नये ई—नीलामी या ई निविदा या ई निविदा सह ई नीलामी के लिए उसके कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् आदेश दे सकता है।

⁴³29 पट्टा विलेख का निष्पादन —

- (1) सम्बन्धित ई—निविदा/ई—नीलामी/ ई—निविदा सह ई—नीलामी का आशय पत्र प्राप्त करने के पश्चात् सफल बोली लगाने वाला/निविदाकर्ता नियमानुसार विहित अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा तथा तत् संबंध में पट्टा विलेख का निष्पादन प्रपत्र एम0एम0 6 या उसके समान प्रपत्र में किया जायेगा। उक्त निष्पादित पट्टा विलेख का रजिस्ट्रीकरण तीन मास की अवधि के भीतर किया जायेगा। पट्टा अवधि की गणना सम्बन्धित पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से की जायेगी। यदि पट्टाधारक की चूक के कारण तीन माह के भीतर उक्त निष्पादित पट्टा विलेख का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाता है तो उक्त पट्टा विलेख निरस्त माना जायेगा तथा प्रतिभूति की धनराशि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
- (2) 43वां संशोधन से विलोपित।
- (3) यथास्थिति, जिला अधिकारी या समिति द्वारा क्षेत्र के मानचित्र सहित पट्टा विलेख की एक प्रतिलिपि उसके निष्पादन के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जायेगी।

खनन पट्टे का अभ्यर्पण –

पट्टाधारक, अभ्यर्पण की आशयित दिनांक को प्रतिभूति जमा धनराशि और उस वर्ष की वार्षिक किस्त की 25 प्रतिशत के बराबर की धनराशि जमा कर, निम्न दस्तावेजों के साथ अभ्यर्पण के लिए आवेदन करेगा :

(क) राज्य सरकार या अनुवर्ती प्रस्तावक के पक्ष में सम्बन्धित पट्टा क्षेत्र के लिये प्राप्त पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अन्तरण हेतु अनापत्ति।

(ख) पर्यावरण अनापत्ति में उल्लिखित मात्रा तथा खनन की गयी मात्रा के मध्य अन्तर के लिये जमा की गयी धनराशि का प्रमाण-पत्र अथवा अन्तर न होने की स्थिति में खान अधिकारी/खान निरीक्षक द्वारा जारी सम्बन्धित पट्टा अदेयता प्रमाण पत्र।

उपरोक्त के अनुसार पट्टाधारक को पट्टा अभ्यर्पण हेतु आवेदन के दिनांक से खनन क्रियाकलाप करने से प्रतिषिद्ध कर दिया जायेगा तथा उक्त क्षेत्र को रिक्त किया हुआ माना जायेगा।

17³⁰.

पट्टा का रजिस्टर—खनन पट्टों का एक रजिस्टर जिला अधिकारी के कार्यालय में प्रपत्र एम0एम0 7 में रखा जायेगा और उसकी एक प्रतिलिपि जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश को भेजी जायेगी।

अध्याय-5**खनन पट्टे की शर्तें**43³¹.

इस अध्याय में उल्लिखित शर्तें सभी पट्टों में लागू होंगी— (1) प्रत्येक खनन पट्टा, इस अध्याय में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा, जिन्हें इस नियमावली के अधीन दिये गये प्रत्येक खनन पट्टे में समाविष्ट किया गया समझा जायेगा।

32.

अन्य खनिजों की खोज—

(1) पट्टेदार, पट्टे पर दिये गये क्षेत्र में किसी ऐसे खनिज की सूचना, जो पट्टे में निर्दिष्ट न हो, राज्य सरकार को उक्त खोज के दिनांक से तीस दिन के भीतर देगा।

(2) यदि पट्टे पर दिये गये क्षेत्र में किसी ऐसे खनिज का पता चल जाये, जो पट्टे में निर्दिष्ट न हो तो, पट्टेदार ऐसे खनिज को तब तक लब्ध (win) और उसका निस्तारण न करेगा जब तक कि उसके लिये पृथक पट्टा न ले लिया जाये।

33.

विदेशी राष्ट्रिक सेवायोजित नहीं किया जायेगा—राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना पट्टेदार खनन संक्रियाओं के संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति को सेवायुक्त नहीं करेगा जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।

47³⁴.**खनन संक्रियायें छः मास के भीतर प्रारम्भ होगी –**

(1) इस नियमावली के अध्याय-दो, चार एवं नौ के उपबन्धों के अधीन खनन पट्टा विलेख का निष्पादन किये जाने से पूर्व या अध्याय-छः के अधीन खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व 'चयनित आवेदक', निदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो निम्नलिखित अर्हता एवं अनुभव धारित करता हो, से खनन योजना तैयार करायेगा, अर्थात् :-

(एक) केन्द्रीय अधिनियम या प्रान्तीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालय, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा-4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त कोई भी संस्था सम्मिलित है, से प्रदान किये गये खनन अभियंत्रण में डिग्री या भू-विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, और

(दो) उपाधि प्राप्त करने के पश्चात खनन क्षेत्र में पर्यवेक्षीय हैसियत से कार्य करने का 05 वर्ष का व्यवसायिक अनुभव।

(2) **चयनित आवेदक, आशय पत्र जारी किये जाने के एक माह के भीतर** राज्य सरकार की इस निमित्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को खनन योजना अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा, जो खनन योजना की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों के भीतर उसे आवश्यक रूप से अनुमोदित, उपान्तरित अथवा अस्वीकृत कर सकता है। **परियोजना प्रस्तावक को खनन योजना अनुमोदित किये जाने के एक माह के भीतर पर्यावरण अनापत्ति की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।**

(3) एक बार अनुमोदित किये जाने पर खनन योजना, खनन पट्टा / अनुज्ञा पत्र की सम्पूर्ण अवधि अथवा पाँच वर्ष जो पहले हो, के लिए विधिमन्थ्य होगा। यदि पट्टे की अवधि पाँच वर्ष से अधिक हो तो उस स्थिति में पट्टाधारक पुनः खनन योजना इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(4) सभी उपखनिजों के संबंध में खनन संक्रियायें खनन योजना के अनुसार जिसमें वार्षिक विकास योजनाएं, खनिज क्षेत्रों के भूमि उद्धार एवं पुनर्वासन के पहलू एवं इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत अधिकारी सम्यक् रूप से अनुमोदित खान बंदी की उत्तरोत्तर योजना का ब्यौरा होगा, की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि पट्टेदार, खनन संक्रियायें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2006 समय-समय पर यथा संशोधित, के उपबन्धों के अधीन यदि अपेक्षित हो पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रारम्भ करेगा। पर्यावरण अनापत्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान प्रस्तावक अपेक्षित समयावधि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का समाधान करने की समस्त वांछित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये बाध्य होगा।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि सभी मामलों में पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र, यथास्थिति परियोजना प्रस्तावक अथवा अंततोगत्वा उपयोक्ता अभिकरण द्वारा और समय-समय पर यथासंशोधित पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रस्तर-6 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) खनन पट्टा-विलेख का निष्पादन, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से खनन योजना अनुमोदित किये जाने के उपरान्त और प्रस्तावक के पक्ष में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर किया जायेगा। खनन संक्रिया नदी तल खनिज के पट्टेदार हेतु तत्काल एवं अन्य खनिजों के पट्टेदार द्वारा पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से 03 (तीन) माह के भीतर प्रारम्भ की जायेगी और पट्टेदार तत्पश्चात जानबूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन, उचित और दक्षतापूर्ण रीति से तथा कुशल कारीगर की भाँति करेगा।

(6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा वित्तीय आश्वासन दिया जायेगा। वित्तीय आश्वासन की रकम स्वस्थाने चट्टान किस्म की खान के लिये पच्चीस हजार रुपये एवं बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में, खनन और सहबद्ध क्रियाकलापों के लिये प्रयोग में लाये गये खनन पट्टा क्षेत्र के प्रति एकड़ खान में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के लिये पन्द्रह हजार रुपये होगी। तथापि उपनियम(7) में विनिर्दिष्ट प्रारूपों में से किसी में दी गयी वित्तीय आश्वासन की न्यूनतम रकम प्रत्येक श्रेणी की खानों या संबंधित क्षेत्र के लिये दो लाख रुपये होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी पट्टाधारक से खनन और सहबद्ध क्रियाकलापों के क्षेत्र में वृद्धि के साथ वित्तीय आश्वासन की रकम बढ़ाये जाने की अपेक्षा की जायेगी:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ पट्टाधारक खान पर उत्तरोत्तर बंद करने के भाग के रूप में भूमि उद्धार और पुनर्वासन उपाय को हाथ में लेता है, वहाँ इस प्रकार खर्च की गयी रकम की गणना पट्टाधारक द्वारा पहले से ही खर्च की गयी वित्तीय आश्वासन की राशि के रूप में की जायेगी और पट्टेदार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय आश्वासन की कुल रकम उस सीमा तक घटा दी जायेगी।

(7) वित्तीय आश्वासन या उसका कोई संशोधन निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में पट्टा विलेख निष्पादन के पूर्व पट्टेदार द्वारा यथास्थिति, जिलाधिकारी अथवा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा:-

(क) किसी अनुसूचित बैंक से प्रत्यय-पत्र,

(ख) अनुपालन या प्रतिभूति बंध-पत्र,

(ग) प्रतिभूति का कोई अन्य प्रारूप या सक्षम अधिकारी को स्वीकार्य कोई अन्य गारन्टी।

- (8) वित्तीय आश्वासन की निर्मुक्ति पट्टेदार द्वारा खान बंद करने की योजना में अन्तर्विष्ट उपबंधों के समाधानप्रद अनुमान के लिये दी गई यथास्थिति जिलाधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित अधिसूचना पर प्रभावी होगी।
- (9) यदि जिलाधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने के युक्ति-युक्त आधार है कि अनुमोदित "खान बंद करने की योजना" से जिसके संबंध में वित्तीय आश्वासन दिया गया था, परिकल्पित रूप में संरक्षा, भूमि उद्धार और पुनर्वासन उपाय "खान बंद करने की योजना" के अनुसार पूर्णतः या भागतः कार्यान्वित नहीं किये गये हैं या नहीं किये जायेंगे तो जिलाधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पट्टेदार को आश्वासन दी गयी राशि को प्रत्याहृत करने के लिये आदेश जारी करने के आशय की लिखित सूचना आदेश जारी किये जाने के दिनांक के कम से कम तीस दिन पूर्व देगा।
- (10) उपनियम (9) में विनिर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर यदि पट्टेदार से कोई लिखित समाधानप्रद उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो यथास्थिति जिलाधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूति रकम प्रत्याहृत करने के लिये आदेश पारित करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति राज्य सरकार को पृष्ठांकित की जायेगी।
- (11) जिलाधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश जारी किये जाने पर संबंधित राज्य सरकार, संरक्षा भूमि उद्धार और पुनर्वासन के प्रयोजन के लिये वित्तीय आश्वासन के रूप में उपबंधित या अभिप्राप्त किये गये किसी प्रत्यय पत्र या बंध पत्र या किसी अन्य प्रतिभूति गारन्टी को वसूल कर सकेगी।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनार्थ खनन संकियाओं में खानों की कार्यप्रणाली से संबंधित मशीनों का लगाना, ट्राम्बे बिछाना या सड़क निर्माण सम्मिलित है।

⁴³35. पट्टा क्षेत्र का सीमांकन सीमा चिन्हों को परिनिर्मित करना, कोर्डिनेट्स का अवधारण व उनका अनुरक्षण:—

- (1) पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र के सीमांकन मानिचत्र पर कोर्डिनेट्स चिन्हांकित किये जायेंगे तथा पट्टा विलेख निष्पादित करने के पूर्व पट्टेदार अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमाचिन्ह को और खम्भे को परिनिर्मित करेगा और सदैव अनुरक्षित करेगा और अच्छी स्थिति में रखेगा, जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिये आवश्यक हो।
- (2) खनन पट्टाधारक जिसका खनन पट्टा क्षेत्र 05 हेक्टेयर से अधिक है, परिवहन के निगरानी के लिये, स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित एक चैक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चैक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0 डी0 स्कैनर भी रखेगा जिससे सम्बन्धित खनन पट्टाकृत क्षेत्र के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बारकोड का डाटा पढने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टा धारक उक्त सभी सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिन तक रखेगा और नियम-66 के उपबन्धों के अधीन यथा उपबन्धित प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उक्त रिकार्डिंग उपलब्ध करायेगा।

36. **खनिजों का ठीक-ठीक लेखा रखना**—पट्टेदार ठीक-ठीक लेखा रखेगा, जिसमें वह खान (mine) से प्राप्त तथा भेजे गये सभी खनिजों की मात्रा तथा अन्य विवरण देगा और साथ ही परिवहन की प्रणाली, वाहन की निबन्ध (रजिस्ट्रेशन) संख्या, वाहन या पशु का प्रभारी व्यक्ति तथा ढोये गये खनिज का प्रकार और मात्रा, खनिज की सभी बिक्री के मूल्य तथा समस्त अन्य विवरण, उसमें सेवा-युक्त व्यक्तियों की संख्या और राष्ट्रीयता तथा खान के पूरे नक्शे देगा, और केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी समय उसके (पट्टेदार) द्वारा रखे गये किन्हीं लेखों, नक्शों और अभिलेखों का परीक्षण करने की अनुमति देगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार को ऐसी समस्त सूचना तथा विवरणियाँ देगा जो केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा उनमें से किसी के द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी अपेक्षा करें।

37. **खाइयों, गड्ढों आदि का अभिलेख रखना**— पट्टेदार, पट्टे के अधीन अपने द्वारा की गई खनन संक्रियाओं के दौरान में अपने द्वारा खोदी गई खाइयों, गड्ढों और बरमा से बनाये गये सूराखों (Drilling) का ठीक-ठीक अभिलेख रखेगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उसका निरीक्षण करने की अनुमति देगा। ऐसे अभिलेखों में निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात्
- (क) वह अधोभूमि (Sub Soil) और भूगर्भ स्तर (strata) जिससे होकर ऐसी खाइयां गड्ढें खोदे जायें या बरमों से सूराख किये जायें।
- (ख) कोई खनिज जो प्राप्त हो।
- (ग) ऐसे अन्य विवरण जिनकी केन्द्रीय या राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करें।
38. **पट्टेदार द्वारा मजबूत करना, टेक आदि लगाना**—पट्टेदार यथास्थिति संबद्ध रेलवे प्रशासन या राज्य सरकार के संतोषानुसार, खान के किसी ऐसे भाग को मजबूत करेगा और उसमें टेक लगायेगा (strengthen & support) जिसे ऐसे प्रशासन या सरकार की राय में किसी रेल, जलाशय (reservoir) नहर, सड़क या किसी अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य या भवनों की सुरक्षा के लिये इस प्रकार मजबूत करना या उसमें टेक लगाना आवश्यक हो।
39. **अग्रक्रयाधिकार (हकशक)**—
- (1) राज्य सरकार को सदा ऐसी भूमि से, जिसके सम्बन्ध में पट्टा दिया गया हो, लब्ध खनिजों या खनिजों के उत्पादन का अग्रक्रयाधिकार (right of pre-emption) होगा, जिस मूल्य का भुगतान किया जायेगा वह अग्रक्रयाधिकार के समय प्रचलित उचित बाजार मूल्य होगा।
- (2) उक्त मूल्य निकालने में सहायता देने के लिये पट्टेदार, यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाये तो राज्य सरकार को उसकी गोपनीय सूचना के लिये अन्य ग्राहकों को बेचे गये ऐसे खनिजों या उनके उत्पादनों तथा उन्हे ढोने के लिये अधिकार-पत्रों का विवरण और मूल्य प्रस्तुत करेगा।
- ⁴⁷40. **पट्टेदार की स्वतन्त्रताएं, शक्तियाँ और विशेषाधिकार**—
- नियम-41में उल्लिखित निर्बन्धन और शर्तों और भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अधीन इस नियमावली के अधीन खनन पट्टा धारण करने वाले व्यक्ति के पास निम्नलिखित स्वतन्त्रता, शक्ति और विशेषाधिकार होंगे :-
- (क) पट्टे में उल्लिखित भूमि पर प्रवेश करना और खान की खोज करना, उस खनिज का जिसके लिये पट्टा हो, वेधन करना (bore) उसे खोदना, उनमें बरमों द्वारा सूराख करना (drill) या उसे लब्ध करना, उसकी प्रक्रिया करना, उसे बदलना, उसे ले जाना और उसका निस्तारण करना।
- (ख) उक्त भूमि में कोई गड्ढा खोदना, कूपक (Shafts), ढाल (inclines), पशु मार्ग (drifts), समतल, जलमार्ग (Water Ways) बनाना या अन्य निर्माण कार्य करना।
- (ग) पट्टेदार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट शर्त के अनुसार नदी की जल धारा को छोड़कर मशीन की सहायता से खनन कर सकता है और लोडिंग तथा अनलोडिंग के लिये भी मशीन का प्रयोग कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमोदन से पट्टेदार भूमि पर किसी मशीनरी, संयंत्र, प्रसाधन, फर्श, भट्टियां, ईट भट्टों, कार्यशाला, मालगोदाम और समान प्रकार के अन्य भवनों का परिनिर्माण तथा निर्माण कर सकता है।
- (घ) उक्त भूमि पर सड़क तथा अन्य रास्ते बनाना और उनका उपयोग करना और उन पर आवागमन करना।
- (ङ) पत्थर खोदना (to quarry) और पत्थर की बजरी (stone gravel) तथा अन्य भवन और सड़क संबंधी सामान तथा मृदा तैयार करना और उसका उपयोग करना और ऐसे ईंटों या खपरैल (tiles) निर्मित करना और ऐसी मृदा से ईंटों या खपरैलों का प्रयोग करना, किन्तु ऐसे सामान, ईट या खपरैलों को न बेचना।

- (च) उक्त भूमि की सतह के पर्याप्त भाग का खानों के लिये किसी उत्पादन या किये गये कार्यों और औजारों (tools), सज्जा (equipment), गिट्टी तथा सामानों और खोदे गये या निकाले गये पदार्थों का संग्रहण या जमा करने के प्रयोजन के लिये उपयोग करना, और
- (छ) अन्य व्यक्तियों के वर्तमान अधिकारों के अधीन रहते हुये और नियम 41 के खण्ड (घ) में की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये झाड़ियों (under growth) और घनी झाड़ी (brushwood) को साफ करना तथा उक्त भूमि पर खड़े या पाये गये वृक्षों या इमारती लकड़ी के वृक्षों को गिराना और इसका उपयोग करना। बशर्ते कि जिला अधिकारी पट्टेदार को उसके (पट्टेदार) द्वारा गिराये और उपयोग में लाये गये किन्हीं वृक्षों या इमारती लकड़ियों का उन दरों पर भुगतान करने के लिये कह सकता है जो जिला अधिकारी द्वारा उनके बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुये निर्धारित की जाय।
- (ज) किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण पट्टा क्षेत्र में खनन संक्रिया के बाधित होने की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आगामी किस्त के सापेक्ष बाधित अवधि के दौरान संदेय किस्त के समतुल्य धनराशि का समायोजन संदेय देयों से आनलाईन करेगा।
- 47 41. पट्टेदार की स्वतन्त्रताओं शक्तियों और विशेषाधिकारों के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्बन्धन एवं शर्तें—** पट्टाधारक नियम 40 में उल्लिखित स्वतन्त्रताओं, शक्तियों और विशेषाधिकारों का प्रयोग निम्नलिखित निर्बन्धनों एवं शर्तों के अधीन रहते हुये करेगा :-
- (क) निम्नलिखित स्थानों पर न कोई चीज खड़ी या स्थापित की जायेगी और न कोई सतह संक्रियायें की जायेगी :-
- (1) किसी सार्वजनिक विनोद स्थल, शमशान अथवा कब्रिस्तान या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र माना जाने वाला कोई स्थान या मकान अथवा ग्राम-स्थल, सार्वजनिक सड़क या कोई अन्य स्थान, जो जिला अधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्थान घोषित किया जाये, और
 - (2) ऐसी रीति से (न तो कोई चीज खड़ी या स्थापित की जायेगी और न कोई सतह संक्रियायें की जायेगी) जिससे किसी भवन, निर्माण कार्य, सम्पत्ति या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को क्षति पहुँचे अथवा उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (ख) पट्टे में असम्मिलित निर्माण कार्यों या प्रयोजनों के निमित्त कोई ऐसी भूमि, सतह संक्रियाओं के लिये प्रयुक्त न की जायेगी, जो राज्य सरकार से भिन्न व्यक्तियों के दखल में पहले से ही हो।
- (ग) किसी भी मार्ग, कुआं या तालाब का उपयोग करने के अधिकार पर हस्तक्षेप न किया जायेगा।
- (घ) प्रभागीय वन अधिकारी (Divisional Forest Officer) की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना न तो किसी आरक्षित (reserved), सुरक्षित (Protected) या निहित (Vested) वन में प्रवेश किया जायेगा और न उक्त अधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त किये बिना और न ऐसी शर्तों के विपरीत, जो राज्य सरकार तदर्थ आरोपित करे, किसी इमारती लकड़ी या वृक्षों को गिराया, काटा या उनका उपयोग किया जायेगा।
- (ङ.) सम्बद्ध रेलवे प्रशासन की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी रेलवे लाइन से जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, किसी जलाशय (reservoir) नहर या अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य—जैसे सार्वजनिक सड़कों और भवनों या निवसित स्थल (inhabited site) से और ऐसे अनुदेशों तथा शर्तों के विपरीत चाहे, वे सामान्य या विशेष हों, जो ऐसी अनुमति में दी जाये, 50 मीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान (Point) पर या किसी स्थल तक कोई खनन संक्रियायें न की जायेंगी। रेलवे, जलाशय, नहर या सड़क की दशा में 50 मीटर की उक्त दूरी, यथास्थिति, किनारे (bank) के बाहरी जिहवांग (toe) या कटाई (cutting) के बाहरी कोर (edge) से क्षैतिज रूप से (horizontally) और भवन की दशा में उसकी कुर्सी (Plinth) से क्षैतिज रूप से मापी जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम सड़क की दशा में यह कटाई के बाहरी कोर से 10 मीटर होगी और
- स्पष्टीकरण—** इस उप नियम के प्रयोजनों के लिये पद "सार्वजनिक सड़क" का तात्पर्य ऐसी सड़क से होगा जो कृत्रिम रूप से समतल किये जाने के पश्चात बनाई गयी हो और जो निरन्तर प्रयोग के परिणामस्वरूप बने पथ (track) से भिन्न हो और ग्राम-सड़क के अन्तर्गत कोई ऐसा पथ होगा, जो राजस्व अभिलेख में ग्राम-सड़क के रूप में किया गया हो।

- (च) किसी ऐसी भूमि के संबंध में, जो पट्टेदार द्वारा धृत भूमि में समाविष्ट हो या उससे आसन्न हो या उसमें अभिगम्य हो, सरकारी पट्टे या अनुज्ञा-पत्र के वर्तमान या भावी धारकों को वहाँ आने-जाने की समुचित सुविधायें दी जायेंगी। यदि इस स्वतन्त्रता का प्रयोग करने के कारण ऐसे पट्टाधारियों या अनुज्ञा पत्र धारियों द्वारा कोई हानि या क्षति पहुँचाई जाये तो ऐसे पट्टेदारों या अनुज्ञापत्रधारी द्वारा पट्टेदार को उसके लिये उचित प्रतिकर (जो परस्पर सहमति द्वारा तय हो या असहमति होने की दशा में, जो राज्य सरकार द्वारा निर्णित किया जाये) देय होगा।
- (छ) पट्टेदार खनन संक्रियाओं के सम्बन्ध में पट्टा क्षेत्र और समीपस्थ क्षेत्रों के पर्यावरण को प्रदूषित न होने देने के लिये सतर्कता बरतने तथा क्षेत्र की पारिस्थितिकी का संतुलन बनाये रखने हेतु बाध्य होगा यदि किसी समय यह पाया गया कि खनन संक्रियायें पर्यावरण को प्रदूषित अथवा पारिस्थितिकी को असंतुलित करती हैं तब सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त पट्टे को समय पूर्व निरस्त किया जा सकेगा।
- (ज) (1) पट्टेदार नदी तल में तीन मीटर की गहराई अथवा जलस्तर जो भी कम हो, के परे कोई खनन संक्रियायें नहीं करेगा और कोई खनन, जिलाधिकारी द्वारा ऐसे परीक्षण किये गये सुरक्षा क्षेत्र में नहीं किया जायेगा,
प्रतिबन्ध यह है कि कोई खनन, जल धारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि की सहायता से नहीं किया जायेगा।
(2) जहाँ ई एम0एम0-11/एम0एम0-11 जारी किया हो, वहाँ पट्टेदार/अनुज्ञा पत्र धारक, विक्रय मूल्य की दर को प्रदर्शित करेगा,
प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की राय में अधिकतम विक्रय मूल्य की दर नियत की जानी हो तो परिहारधारकों को निदेशित किया जा सकता है।
- (झ) पट्टेदार भारत सरकार द्वारा निर्धारित सन्नियमों के अनुसार अपने अनुमोदित पट्टा क्षेत्र में खनिजों की लोडिंग का दायित्व ग्रहण करने हेतु बाध्य होगा।
- 42. सभी दावों के विरुद्ध पट्टेदार सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा—** पट्टेदार सभी हानि, क्षति या विक्षोभ (disturbance) के लिये, जो पट्टे द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करने में उसके द्वारा की गई हो, भुगतान करने की प्रत्याभूति (guarantee) देगा और ऐसे समुचित प्रतिकर का भुगतान करेगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाये और उन सभी दावों, वादों तथा माँगों से और उनके प्रति जो किसी ऐसी हानि, क्षति या विक्षोभ के संबंध में किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा की जायेगी या लायी जायें और उनके संबंध में सभी परिव्ययों की राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा पूर्णतया क्षतिपूर्ति करता रहेगा।
- 43. पट्टेदार गडढो, कूपकों आदि को सुरक्षित और अच्छी दशा में रखेगा**—पट्टेदार, पट्टे की अवधि में ऐसे सभी गडढो, कूपकों (shafts) और कार्यकारणों (workings) को, जो भूमि में बनाये जाये या प्रयुक्त किये जाये, इमारती लकड़ी या अन्य स्थाई उपायों से पर्याप्त रूप से सुरक्षित और खुला रखेगा और राज्य सरकार के संतोषानुसार प्रत्येक ऐसे गडढे, कूपक या कार्यकरण के चारों ओर, चाहे वह परित्यक्त कर दिया गया हो या नहीं पर्याप्त रूप से बाड़े लगायेगा और उनका अनुरक्षण करेगा और उसी अवधि में, भूमि पर के सभी कार्यकारणों को सिवाय उनके, जो परित्यक्त किये जाये, प्रवेश्य और यथासंभव जल एवं दूषित वायु से मुक्त रखेगा।
- 44. पट्टेदार, कार्यकारणों के निरीक्षण की अनुमति देगा—** पट्टेदार, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ, प्राधिकृत किसी अधिकारी को भू-गृहादि में जिसके अर्न्तगत पट्टे में समाविष्ट कोई भवन, उत्खनन या भूमि भी है, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करने और उसके नक्शे (plans) बनाने, न्यायदर्शन (sampling) और कोई आधार सामग्री एकत्र करने के प्रयोजन के लिये प्रवेश करने की अनुमति देगा और पट्टेदार ऐसे उपयुक्त व्यक्ति के साथ, जो पट्टेदार द्वारा सेवायोजित किया गया हो तथा जो खानों और खनिकर्म से परिचित हो, उक्त अधिकारी, अभिकर्ताओं, सेवकों और कर्मचारी (workmen) को प्रत्येक ऐसे निरीक्षण करने में प्रभावपूर्ण रूप से सहायता देगा और उन्हें खानों का कार्यप्रणाली (working) से संबद्ध सभी सुविधायें व सूचना देगा, जिनकी वे उचित रूप में अपेक्षा करें और ऐसी सभी आज्ञाओं तथा विनियमों के अनुसार कार्य भी करेगा और उनका पालन करेगा, जिन्हे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, ऐसे निरीक्षण के फलस्वरूप या अन्य प्रकार से समय-समय पर देना या बनाना उचित समझे।

45. **पट्टेदार, दुर्घटना का प्रतिवेदन देगा**— पट्टेदार अविलम्ब जिला अधिकारी को प्रत्येक ऐसी दुर्घटना का प्रतिवेदन भेजेगा जो पट्टे के अधीन किन्हीं संक्रियाओं के दौरान में हो जाये और जिसके कारण मृत्यु हो जाये या गंभीर शारीरिक चोट पहुंचे या सम्पत्ति को गम्भीर क्षति पहुंचे, या जिससे जीवन या संपत्ति पर गंभीर प्रभाव पड़े, या वह संकट में पड़ जाये।
46. **पट्टेदार तौलमशीन की व्यवस्था करेगा**— (20वां संशोधन द्वारा निकाल दिया गया)
47. **पट्टेदार तौलमशीन की जाँच करने की अनुमति देगा**— (20वां संशोधन द्वारा निकाल दिया गया)
48. **पट्टेदार कोई भी अतिरिक्त आवश्यक धनराशि जमा करेगा**—जब कभी प्रतिभूति जमा या उसका कोई भाग या उसकी पूर्ति (replenishment) में राज्य सरकार के पास जमा की गई कोई अतिरिक्त धनराशि इस नियमावली द्वारा दिये गये अधिकार के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जब्त कर ली जाये या प्रयुक्त की जाये, तो पट्टेदार राज्य सरकार के पास ऐसी और धनराशि जमा करेगा जो ऐसी जब्ती या प्रयुक्ति के कारण हुई कमी को पूरा करने के लिये आवश्यक हो।
49. **सरकार द्वारा किये गये व्ययों की वसूली**— यदि कोई निर्माण का या विषय, जो इस नियमावली के अनुसार पट्टेदार द्वारा कार्यान्वित या संपादित किये जाने वाले हो, तदर्थ निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्यान्वित या संपादित करा सकती है और पट्टेदार मांगने पर राज्य सरकार को उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा किये गये सभी व्ययों का भुगतान करेगा। ऐसे व्ययों के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।
50. **प्रतिभूति जमा का वापस किया जाना**— खनन पट्टे की समाप्ति के पश्चात् राज्य सरकार के पास जमा पड़ी हुई प्रतिभूति धनराशि, जो इस नियमावली में उल्लिखित किन्हीं भी प्रयोजनों में प्रयुक्त किये जाने के लिये अपेक्षित न हो, साधारणतया पट्टे की समाप्ति के दिनांक से छः मास की अवधि के भीतर पट्टेदार को वापस कर दी जायेगी।

अध्याय-6

खनन अनुज्ञा पत्र

51. **खनन अनुज्ञा- पत्र दिये जाने पर निर्बन्धन**— कोई खनन अनुज्ञा-पत्र ऐसे व्यक्ति को न दिया जायेगा जो भारतीय राष्ट्रिक न हो, या छः मास से अधिक अवधि के लिये न दिया जायेगा।
52. **खनन अनुज्ञा-पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र**— खनन अनुज्ञा पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम0एम0 8 में, तीन प्रतियों में, जिलाधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा जो ऐसा अनुज्ञा-पत्र देने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाये। इसके साथ निम्नलिखित होंगे :-

³³(एक) 2000 रूपये का शुल्क और

(दो) भू-कर सर्वेक्षण मानचित्र की दो प्रतियां या ऐसे सर्वेक्षण के अर्न्तगत न आने वाले क्षेत्र की स्थिति में धरातल मानचित्र ऐसे पैमाने पर जिसमें कम से कम "4इंच बराबर एक मील" के हो, दो ऐसी प्रतियाँ जिसमें वह क्षेत्र, जिसके लिये प्रार्थना -पत्र दिया गया है, स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो।

³³(तीन) उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट जिसमें आवेदक स्थायी रूप से निवास करता है के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र।

³³(चार) खनन हेतु प्रस्तावित उप खनिज की मात्रा पर इस नियमावली के द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से देयस्वामित्व का दस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि अर्नेस्ट मनी के रूप में बैंक ड्राफ्ट जो सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी के पक्ष में देय होगा।

परन्तु यह कि खनिज अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत होने की दशा में अर्नेस्टमनी की धनराशि देय रायल्टी में समायोजित कर ली जायेगी एवं अनुज्ञा-पत्र अस्वीकार किये जाने का दशा में अर्नेस्टमनी की धनराशि आवेदक को तदनुक्रम लौटा दी जायेगी। परन्तु यह और कि यदि दी गयी अवधि के भीतर आवेदक रायल्टी की धनराशि जमा करने में असफल हो जाता है अथवा खनन परमिट निष्पादित करने में असफल रहता है तब अर्नेस्टमनी के मद में जमा धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

कृषि भूमि पर खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया:-

- (1) नियम-72 में किसी बात के होते हुए कृषि भूमि का भूमिधर अपनी कृषि भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिलीजुली अवस्था में हो, को हटाने के लिये खनन अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति हेतु प्रपत्र एम0एम0-8 पर तीन प्रतियों में रू0-2000/- (रूपये दो हजार) मात्र की फीस एवं भू-कर सर्वेक्षण मानचित्र की दो प्रतियां, जिसमें आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो, में आवेदन जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
- (2) जिलाधिकारी यदि आवश्यक समझे तब सम्बन्धित तहसीलदार और खान अधिकारी / खान निरीक्षक के द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर जाँच कर सकता है -
 - (क) क्या बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो, आवेदित भूमि पर बाढ़ के कारण जमा हुए हैं,
 - (ख) क्या आवेदक/आवेदकों का/के नाम आवेदित क्षेत्र में भूमिधर के रूप में अभिलिखित है/हैं;
 - (ग) क्या बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हों के जमाव के कारण आवेदक / आवेदकगण आवेदित क्षेत्र के उपयोग न किये जाने पर क्षति वहन कर रहा/रहे हैं;
 - (घ) क्या ऐसी भूमि विगत 05 वर्षों में कृषि कार्य हेतु उपयोग की जा रही थी
 - (ङ) क्या आवेदक द्वारा उपखनिज की आवेदित मात्रा आवेदित क्षेत्र में उपलब्ध है
 - (च) क्या खनन अनुज्ञा पत्र का आवेदित क्षेत्र खनन हेतु उपयुक्त है?
- (3) ऊपर उल्लिखित तहसीलदार/ खान अधिकारी या खान निरीक्षक जैसा कि अभिप्रेत हो, कि बिन्दुवार आख्या के प्रकाश में जिलाधिकारी, एक फसली वर्ष में तीन माह से अनाधिक अवधि के लिये भूमिधर के पक्ष में, स्वामित्व की दो गुनी धनराशि को अग्रिम रूप में जमा कराकर, खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत कर सकता है।
- (4) सिवाय उपरिलिखित उपबन्धों के इस नियमावली के अन्य उपबन्ध, इस नियम के अधीन स्वीकृत खनन अनुज्ञा पत्र पर आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

भवन/विकास परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया में प्राप्त खनिज के लिए अनुज्ञा पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया :-

- (1) इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी भवन या किसी विकास परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया में पाया गया कोई खनिज ऐसी परियोजना के निष्पादन की प्रक्रिया में निकाला जाना हो, वहाँ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र के आधार पर उसका निस्तारण या उपभोग किया जायेगा।
- (2) आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जिला खान अधिकारी/खान निरीक्षक द्वारा स्थलीय निरीक्षण और उपलब्ध खनिज की मात्रा का निर्धारण करने के पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट एक माह के भीतर आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
- (3) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 की अनुसूची-एक में यथा विहित प्रयोज्य रॉयल्टी के भुगतान के आधार पर उक्त अनुज्ञा पत्र प्रदान जा सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि गैर वाणिज्यिक निजी आवासीय भवन उक्त से छूट प्राप्त होंगे:

अग्रतर प्रतिबन्ध है कि यदि उक्त अवधि के भीतर आवेदन का निस्तारण नहीं किया जाता है तो निर्धारित मात्रा की रॉयल्टी की धनराशि के भुगतान पर अनुज्ञा पत्र जारी किया गया समझा जायेगा।

प्रार्थना पत्र का निस्तारण - अनुज्ञा पत्र देने के लिये प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाय, अनुज्ञा पत्र देने से इन्कार कर सकता है या उसकी किसी आज्ञा द्वारा ऐसी शर्तें और निबन्धनों के अधीन जो उक्त अधिकारी आवश्यक समझे, प्रार्थित क्षेत्र के कुल या कुछ भाग के लिये दे सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे क्षेत्र के लिये, जो पट्टे या खनन अनुज्ञा पत्र के अधीन पहले से धृत है, अनुज्ञा पत्र दिये जाने के लिये कोई प्रार्थना पत्र समय पूर्व समझा जायेगा और उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा और यदि कोई प्रार्थना पत्र शुल्क दिया गया है, तो उसे वापस कर दिया जायेगा।

अनुज्ञा पत्र दिये जाने के लिये कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकार-(26वाँ संशोधन द्वारा निकाल दिया गया)

21वाँ संशोधन दिनांक- 02.02.1995

26वाँ संशोधन दिनांक- 22.06.2004

47वाँ संशोधन दिनांक- 13.08.2019

49वाँ संशोधन दिनांक- 18.03.2020

- ²⁰54. **स्वामित्व का जमा किया जाना**— (1) जब नियम 53 के अधीन खनन अनुज्ञा पत्र दिये जाने का आदेश दे दिया जाय, तब प्रार्थी आदेश की संसूचना दिये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन की भीतर, उक्त आदेश में अनुज्ञात खनिज की कुल मात्रा के लिये इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्काल विनिर्दिष्ट दर पर स्वामित्व जमा करेगा। यदि अनुज्ञा पत्र धारक किसी कारण से जो उसके द्वारा हुआ माना जाय अनुज्ञात समय के भीतर खनिज को नहीं हटा लेता तो स्वामित्व के रूप में जमा कोई धनराशि वापस नहीं की जायेगी।
(2) यदि प्रार्थी उप नियम (1) में उल्लिखित अवधि के भीतर या ऐसी अग्रेतर अवधि के भीतर, जैसी अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा दी जाये स्वामित्व जमा करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने वाला आदेश प्रतिसंहृत (रद्द) हो जायेगा और नियम 52 के खण्ड (एक) में उल्लिखित फीस राज्य सरकार के प्रति जब्त हो जायेगी।
- ²⁰55. **खनन अनुज्ञा-पत्र का जारी किया जाना**— प्रार्थी को खनन अनुज्ञा पत्र प्रपत्र एम0एम0 10 ऐसे अतिरिक्त निबंधनों और शर्तों के साथ, जिनके अधीन नियम 53 में आदेश दिये जाय, नियम 54 के उपनियम (1) में स्वामित्व जमा करने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर जारी कर दिया जायेगा और इस प्रकार जारी अनुज्ञापत्र, में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक तक या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाय, इसमें से जो भी पहले हो, वैध रहेगा।
56. **खनन अनुज्ञा-पत्रों का रजिस्टर**—खनन अनुज्ञा पत्रों के सभी प्रार्थना-पत्रों का एक रजिस्टर जारी किये गये अनुज्ञा-पत्रों के ब्यौरों के साथ प्रपत्र एम0एम0 9 में जिला अधिकारी अथवा खनन अनुज्ञा पत्र देने के लिये प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में रखा जायेगा।

अध्याय-7

उल्लंघन अपराध और शास्तियां

- ⁴²57. **अनधिकृत खनन के लिए शास्ति**— जो कोई भी नियम 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करे वह दोष सिद्ध हो जाने पर दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डनीय होगा, जो पाँच वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अन्यून दो लाख रुपये एवं अधिकतम पांच लाख रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों दण्डों से दण्डनीय होगा।
- ⁴⁷58. **स्वामित्व, भाटक या अन्य देयों का भुगतान न करने के परिणाम**—
(1) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, पट्टेदार पर इस बात की सूचना तामील करने के पश्चात् कि वह सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वामित्व (रायल्टी) सहित पट्टे के अधीन देय कोई धनराशि या अपरिहार्य भाटक का भुगतान करें, यदि उस भुगतान के लिये निश्चित दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उसका भुगतान न किया गया हो, तो खनन पट्टा समाप्त कर सकता है। यह अधिकार पट्टेदार से ऐसे देयों को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करने के राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त होगा और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(2) इस नियमावली के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उप नियम (1) के अधीन सूचना की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार के प्रति देय किसी भाटक स्वामित्व, सीमांकन शुल्क और किन्हीं अन्य देयों पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जा सकता है।
प्रतिबन्ध यह है कि जिला मजिस्ट्रेट कुल देय धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि का समायोजन करने के पश्चात् अवशेष धनराशि की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करेगा।
- ⁴⁷59. **कतिपय शर्तों का उल्लंघन करने के परिणाम**—
(1) प्रस्तावक, जो आशय पत्र प्राप्त किया हो, तथापि नियम-34 में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार नियत की गयी एक माह की अवधि के भीतर खनन योजना प्रस्तुत नहीं किया हो या पर्यावरण अनापत्ति स्वीकृति हेतु आवेदन नहीं किया हो, रू0 दस हजार प्रतिदिन की शास्ति के लिये दायी होगा। शास्ति की धनराशि, जमा करने में विफल होने पर उस धनराशि को, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित पट्टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती की जायेगी। यदि प्रस्तावक पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन करने में विफल हो जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट आशय पत्र निरस्त करने के पश्चात् प्रस्तावक द्वारा जमा की गयी प्रथम किस्त और प्रतिभूति धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर लेगा।
(2) नियम-34 के अधीन उपबन्धित उपबन्धों के अनुसार जारी अनुमोदित खनन योजना और पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित निबन्धन एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुये जो पट्टेदार खनन कार्य करता है तो वह चूक के प्रति अवसर के अनुसार पचास हजार रुपये की दर से ऐसी शास्ति के लिये दायी होगा, जिसकी वसूली जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।

20वाँ संशोधन दिनांक— 27.08.1994

42वाँ संशोधन दिनांक— 18.05.2017

47वाँ संशोधन दिनांक— 13.08.2019

- (3) यदि पट्टाधारक, नियम 35 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो प्रत्येक चूक के लिये प्रतिदिन पच्चीस हजार रुपये की दर से शास्ति, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उद्गृहीत की जायेगी। ऐसी उद्गृहीत शास्ति को जमा करने पर चूक की दशा में उक्त धनराशि की कटौती संबंधित जिला मजिस्ट्रेट उक्त खनन पट्टा के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति की धनराशि से करेगा।
- (4) नियम 41 (ज) के अधीन उपबन्धित उपबन्धों के अनुसार जल धारा में सक्शन मशीन/लिफ्टर के माध्यम से खनन कार्य निषिद्ध होगा। यदि कोई पट्टाधारक उक्त नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो प्रत्येक अवसर पर पाँच लाख रुपये की दर से शास्ति के लिये दायी होगा, जो जिला मजिस्ट्रेट या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के आदेश पर वसूला जायेगा। शास्ति की उपरोक्त उल्लिखित धनराशि को जमा करने में विफल होने पर उस धनराशि को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित पट्टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती की जायेगी।
- (5) खनन पट्टाधारण करने वाला कोई पट्टेदार, जो नियम-44 में उपबन्धित की गयी किसी शर्त को भंग करे, पचास हजार रुपये की शास्ति/उद्ग्रहण के लिये दायी होगा। शास्ति की उक्त धनराशि को जमा करने में विफल होने पर उक्त धनराशि की जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित पट्टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती कर ली जायेगी।
- (6) जहाँ पट्टाधारक विहित लोडिंग सन्नियमों की पुष्टि करने में विफल हो जाय, वहाँ ऐसे प्रत्येक चूक की दशा में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रू0-25,000.00 की शास्ति अधिरोपित की जायेगी। उक्त शास्ति को जमा करने में विफल रहने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित पट्टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती कर ली जायेगी।
- (7) जहाँ प्रस्तावक निर्धारित समयावधि में सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने की सम्पूर्ण वांछित प्रक्रियाओं को पूरा करने में विफल हो जायेगा, वहाँ जिला मजिस्ट्रेट उसके पक्ष में जारी आशयपत्र को निरस्त कर सकता है।

⁴⁷ 60. सामान्यतः नियमों और पट्टे की शर्तों के उल्लंघन के परिणाम

- (1) पट्टेदार द्वारा इन नियमों या पट्टे में दी गई या दी गई समझी जाने वाली शर्तों और प्रसंविदाओं के, सिवाय उनके, जो स्वामित्व, भाटक या राज्य सरकार को देय अन्य धनराशियों के भुगतान से संबंधित हों, भंग या उल्लंघन किये जाने की दशा में राज्य सरकार पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात पट्टा समाप्त कर सकती है। यह अधिकार नियम 59 के उपबन्धों के अतिरिक्त होगा और इसका उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (2) यदि उप नियम (1) अथवा नियम-58 के अधीन पट्टा समाप्त कर दिया जाता है तो पट्टेदार का नाम जिला अधिकारी द्वारा दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा कि वह उचित समझे काली सूची में डाल दिया जायेगा, जो विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी और ऐसी अवधि के दौरान उसको इस नियमावली के अधीन कोई खनिज परिहार अनुमन्य नहीं होगा। इस संबंध में, यथास्थिति, खनन पट्टे के रजिस्टर में या नीलाम रजिस्टर के अभ्युक्ति वाले स्तम्भ में एक प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी।
- (3) खनन पट्टाधारक को छोड़कर अन्य व्यक्ति अथवा इकाई, जिस पर अवैध खनन/परिवहन का आरोप सिद्ध पाया जाता है तो शास्ति/दण्ड के अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति या इकाई का नाम राज्य सरकार द्वारा काली सूची में डाला जायेगा जो विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी और ऐसी अवधि में उक्त व्यक्ति या इकाई के पक्ष में इस नियमावली के अधीन कोई खनिज पट्टा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

अध्याय-8

विविध

61. प्रत्यक्ष अशुद्धियों को ठीक करने का अधिकार—राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा इस नियमावली के अधीन दी गई किसी आज्ञा में कोई लिपिक या अंकीय अशुद्धि यथास्थिति राज्य सरकार, प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा ठीक की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी आज्ञा, जो किसी व्यक्ति के लिये हानिकर हो, तब तक न दी जायेगी जब तक कि उसे अपना मामला बताने के लिये समुचित अवसर न दे दिया गया हो।

²³62. रजिस्ट्रों का निरीक्षण करने दिया जायेगा—

- (1) इस नियमावली द्वारा रखे जाने वाले नियुक्त सभी रजिस्ट्रों को प्रत्येक प्रविष्टि के लिये बीस रुपये का शुल्क भुगतान करने पर निरीक्षण करने दिया जायेगा।
- (2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट रजिस्ट्रों की प्रविष्टि और किसी प्रार्थना पत्र पर जिला अधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि निम्नलिखित शुल्क को भुगतान करने पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है—
 - (क) सात दिन के भीतर प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये 100.00 रुपये और
 - (ख) चौबीस घण्टे के भीतर प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये 200.00 रुपये

स्पष्टीकरण—(1)—“प्रविष्टि” का तात्पर्य यथास्थिति, एक अनुज्ञा पत्र या एक खनन पट्टा या एक नीलामी पट्टा के संबंध में समस्त प्रविष्टियों से है।

स्पष्टीकरण—(2)—शुल्क का भुगतान नियम 64 में निहित रीति से किया जायेगा और यथास्थिति निरीक्षण के लिये प्रार्थना पत्र या प्रमाणित प्रतिलिपि के लिये प्रार्थना पत्र के साथ ट्रेजरी चालान लगा होगा।

⁴⁷63. नाम, राष्ट्रिकता आदि में परिवर्तन :-

- (1) खनन पट्टे का आवेदक या उसका धारक राज्य सरकार को साठ दिन के भीतर प्रत्येक ऐसे परिवर्तन की सूचना देगा जो उसके नाम, राष्ट्रिकता या संगत प्रपत्रों में उल्लिखित अन्य विवरणों में किया जाये।
- (2) आवेदक/पट्टाधारक की मृत्यु की दशा में खनन पट्टा का आवेदन पत्र/ निष्पादित खनन पट्टा उसके विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में माना जायेगा। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा परीक्षणोपरान्त आदेश जारी किया जायेगा।

64. शुल्कों और जमा का भुगतान कैसे किया जायेगा— इस नियमावली के अधीन देय किसी धनराशि का भुगतान ऐसी रीति से किया जायेगा, जो राज्य सरकार तदर्थ निर्दिष्ट करे।

65. छात्रों के प्रशिक्षण के लिये सुविधायें —

- (1) खनन का प्रत्येक स्वामी अभिकर्ता या प्रबन्धक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित खनिकर्म एवं भूतत्व संबंधी संस्थाओं के छात्रों को उनके द्वारा चलायी जाने वाली खानों और संयंत्रों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति देगा और ऐसे छात्रों के प्रशिक्षण के लिये अपेक्षित सभी आवश्यक सुविधायें देगा।
- (2) खनिकर्म या भूतत्व शास्त्र की शिक्षा देने वाली संस्थाओं के छात्रों के प्रशिक्षण के लिये प्रार्थनापत्र खान के स्वामी, अभिकर्ता प्रबन्धक को उक्त संस्थाओं के आचार्य (principals) या प्रधान के माध्यम से भेजे जाने चाहिये। खान के किसी स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक द्वारा व्यावहारिक, प्रशिक्षण के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने से इनकार करने के मामले भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशक, उत्तर प्रदेश के अभिविष्ट किये जाने चाहिये।

⁸66. निर्धारण करने, प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार—

- (1) किसी खान या परित्यक्त खान के रायल्टी का निर्धारण करने और उसकी वास्तविक या भावी कार्य की स्थिति की जांच करने के लिये या इस नियमावली से संबद्ध किसी प्रयोजन के लिये जिला अधिकारी या भू-विज्ञान तथा खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिकारी जो निदेशक के द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियुक्त खान निरीक्षक के पद से नीचे के पद के न हों या राज्य सरकार की सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी :
 - (क) किसी खान में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है।
 - (ख) किसी ऐसी खान का सर्वेक्षण कर सकता है और माप सकता है।
 - (ग) किसी खान में पड़ें हुये खनिज स्टॉक को तौल सकता है, उसे माप सकता है या उसकी नाप ले सकता है।
 - (घ) किसी ऐसे लेख, बही, रजिस्टर या अभिलेख का परीक्षण कर सकता है जो किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे या अधिकार में हो, जिसका किसी खान पर नियंत्रण हो या जो उससे

संबद्ध हो और उस पर पहचान के चिन्ह लगा सकता है और ऐसे लेख्य, बही, रजिस्टर या अभिलेख से उद्धरण ले सकता है या उसकी प्रतियां तैयार कर सकता है।

(ड.) खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी ऐसे लेख, बही, प्रदेश के अभिविष्ट किये जाने चाहिये। रजिस्टर या अभिलेख को समन कर सकता है या उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकता है।

(च) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका किसी खान पर नियंत्रण हो या जो उससे संबद्ध हो, समन कर सकता है या उसका निरीक्षण कर सकता है, और

(छ) ऐसी सूचना या विवरण मांग सकता है जो आवश्यक समझी जाये।

(2) उप नियम (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा और प्रत्येक व्यक्ति से जो उक्त उप नियम के खण्ड (ड) या खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के आधार पर कोई आज्ञा या समन जारी किया जाय, यथास्थिति, ऐसी आज्ञा या समन का अनुपालन करने के लिये विधितः बाध्य होगा।

²⁰67. भूमि के स्वामी द्वारा खनन संक्रियाये पर कोई निबंधन आदि आरोपित नहीं किया जायेगा—

(1) कोई भी व्यक्ति, जिसे खनन पट्टा या खनन अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि में किसी भी रूप में अधिकार प्राप्त हो, ऐसी भूमि के पट्टा या खनन अनुज्ञापत्र धारक खनन संक्रियाओं पर कोई प्रतिषेध या निर्बंधन आरोपित करने या उपखनिज हटाने के लिये अधिमूल्य (प्रीमियम) या स्वामित्व के रूप में कोई धनराशि मांगने का हकदार न होगा।

प्रतिबंध यह है कि ऐसा व्यक्ति भूमि के धरातल की खनन संक्रियाओं के लिये उपयोग करने हेतु खनन पट्टा या खनन अनुज्ञापत्र के उक्त धारक से ऐसा वार्षिक प्रतिकर पाने का हकदार होगा जो उनके बीच तय हो।

(2) जहां खनन पट्टा या खनन अनुज्ञापत्रधारक और भूमि की सतह के स्वामी वार्षिक प्रतिकर की धनराशि पर सहमत न हो और उसके संबंध में कोई विवाद हो तो जिला अधिकारी द्वारा उसका अवधारण निम्नलिखित रूप से किया जायेगा :—

(क) कृषि योग्य भूमि की दशा में, प्रतिकर की धनराशि उसी प्रकार की भूमि में विगत तीन वर्षों में की गयी खेती से प्राप्त औसत वार्षिक शुद्ध आय के आधार पर निकाली जायेगी, और

(ख) गैर कृषि योग्य भूमि की दशा में, वार्षिक प्रतिकर की धनराशि, उसी प्रकार की भूमि के विगत तीन वर्षों के भाटक मूल्य के आधार पर निकाली जायेगी।

68. विशेष मामलों में नियमों का शिथिल किया जाना—राज्य सरकार किसी भी मामले में यदि उसकी यह राय हो कि खनिज विकास के हित में लिखित आज्ञा द्वारा और उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे ऐसा करना आवश्यक है, इस नियमावली में निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों से भिन्न शर्तों और प्रतिबंधों पर किसी खनिज को लब्ध करने के लिये किसी खनन पट्टे को देने या किसी खान का कार्य करने का प्राधिकार दे सकती है।

⁴⁷68क. खानों को आरक्षित करने की राज्य सरकार की शक्ति :—

(1) इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा किसी सरकारी संगठन अथवा औद्योगिक प्रोत्साहन के हित में किसी व्यक्ति/कम्पनी के पक्ष में, उक्त आदेश में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन खनन संक्रियायें हेतु, किसी क्षेत्र को आरक्षित कर सकती है।

(2) इस प्रकार आरक्षित क्षेत्र के लिये यथास्थिति खनन पट्टा अथवा खनन अनुज्ञापत्र, किसी सरकारी संगठन अथवा औद्योगिक प्रोत्साहन के हित में किसी व्यक्ति/कम्पनी को प्रदान किया जायेगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा यथा विनिश्चित निर्बंधनों और शर्तों के अधीन आरक्षित किया गया हो।

(3) यथास्थिति इस नियम के अधीन यथाविनिश्चित स्वीकृत खनन पट्टा अनाधिक 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया जायेगा।

(4) पट्टेदार, जिसे इस नियम के अधीन कोई पट्टा प्रदान किया गया हो सरकार को, पट्टेधारक द्वारा संदेय समस्त धनराशि और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिश्चित अतिरिक्त प्रभारों का संदाय करेगा।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजनार्थ, सरकारी संगठन का तात्पर्य किसी सरकारी विभाग या किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित किसी निगम या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (45) के अन्तर्गत सरकारी कम्पनी से है और इसके अन्तर्गत केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मौलिक रूप में नियंत्रित राज्य प्राधिकरण या संगठन भी सम्मिलित हैं।

69. स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक ठेकेदार के माध्यम से वसूल किया जा सकता है :

- (1) सरकार, खनन पट्टे के धारकों से स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक ठेकेदार द्वारा वसूल किये जाने का प्रबन्ध कर सकती है और ऐसे धारक, जब राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाये, स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक का भुगतान अपने पट्टे में निर्दिष्ट दरों पर उक्त ठेकेदारों को ऐसी अवधि के भीतर करेंगे जो निदेशित की जाये।
- (2) खनन पट्टे के धारक द्वारा ठेकेदार का यथास्थिति स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक का भुगतान न करने के वही परिणाम होंगे, जो राज्य सरकार को भुगतान करने के होते हैं और उस दशा में राज्य सरकार को पट्टेदार से बकाया की वसूली करने तथा पट्टे को समाप्त करने के संबंध में ऐसे सभी अधिकार होंगे, जो इस नियमावली में व्यवस्थित है।
- (3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति के साथ, जो उपयुक्त समझा जाये, तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये निर्दिष्ट क्षेत्र में खनन पट्टों के धारकों से स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक वसूल करने के लिये नीलाम करके या टेण्डर आमंत्रित करके या किसी अन्य रीति से ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर अनुबन्ध कर सकती है जो उपयुक्त समझे जायें।

48.70. खनिजों के परिवहन पर निर्बन्धन-

- (1) खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा पत्र धारक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, किसी वाहन, पशु या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा उपखनिज का पारेषण (कन्साइनमेंट) कर ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रपत्र एम0एम0 11 अथवा इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की गयी ई-प्रपत्र एम0एम0 11 में पास जारी करेगा। राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से, भुगतान के आधार पर मुद्रित एम0एम0-11 प्रपत्र पुस्तिका की आपूर्ति हेतु व्यवस्था कर सकती है।
- (2) कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर रेल को छोड़कर किसी वाहन, पशु या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा, उपनियम (1) के अधीन जारी प्रपत्र एम0एम0-11/प्रपत्र ई-एम0एम0-11 में और उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 के नियम 7(3) के अधीन जारी विधिमान अभिवहन पास या किसी अन्य राज्य द्वारा जारी समान विधिमान अभिवहन पास के बिना कोई उपखनिज नहीं ले जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार ठेकेदार के माध्यम से स्वामित्व की वसूली करने हेतु अनुबन्ध करती है तो यथास्थिति स्वामित्व(रायल्टी) या शून्य स्वामित्व की रसीद ऐसे ठेकेदार द्वारा जारी की जायेगी और ऐसे मामले में प्रपत्र एम0एम0-11/प्रपत्र ई-एम0एम0-11 के साथ ऐसी रसीद को रखना परिवहन के लिये अज्ञापक होगा।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि अन्य राज्यों से आने वाले खनिजों पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित विनियमन शुल्क अधिरोपित किये जाने के पश्चात् ही खनिज का परिवहन विधिमन्य होगा।

- (3) किसी उपखनिज को ले जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति, नियम 66 के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर उक्त 'पास' को ऐसे अधिकारी को दिखायेगा और उसे उपखनिज की मात्रा के संदर्भ में 'पास' के विवरणों की शुद्धता को सत्यापित करने देगा।
- (4) राज्य सरकार किसी खनन पट्टा या अनुज्ञा पत्र में सम्मिलित किसी क्षेत्र के लिये चेक पोस्ट (जांच चौकी) स्थापित कर सकती है और जब ऐसी चेक पोस्ट (जांच चौकी) स्थापित कर दी जाये तो इस तथ्य की सार्वजनिक सूचना गजट में प्रकाशित करके और ऐसी अन्य रीति से दी जायेगी जैसा कि राज्य सरकार उपयुक्त समझे।
- (5) कोई व्यक्ति, ऐसे उपखनिज का, जिस पर यह नियमावली लागू होती हो, परिवहन ऐसे क्षेत्र से, उस क्षेत्र के लिये स्थापित चेक पोस्ट (जांच चौकी) पर उपखनिज के भार और माप के सत्यापन हेतु उसे प्रस्तुत किये बिना नहीं करेगा।
- (6) कोई व्यक्ति इस नियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करते पाया जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट 25,000 रु0 (पच्चीस हजार) की शास्ति एवं स्वामित्व (रायल्टी) सहित ऐसे उपखनिज के मूल्य की वसूली करेगा। ऊपर उल्लिखित सम्पूर्ण धनराशि को जमा करने के पश्चात् उपखनिज सहित वाहन को छोड़ दिया जायेगा।

71. प्रतिनिधान :- राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य कोई भी अधिकार किन्हीं ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाये, राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किये जा सकते हैं, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जाये।

²⁰⁻²¹ 72

पुनः स्वीकृति के लिये क्षेत्र की उपलब्धता का अधिसूचित किया जाना—(1) यदि कोई क्षेत्र जो अध्याय-2 के अन्तर्गत खनन पट्टा के अधीन धृत था या अधिनियम की धारा-17-क के अधीन आरक्षित था, पुनः खनन पट्टे पर दिये जाने के लिये उपलब्ध हो जाता है तो जिला अधिकारी नोटिस के माध्यम से उस क्षेत्र की उपलब्धता अधिसूचित करेगा जिसमें दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुये, जो नोटिस के दिनांक से तीस दिन पहले का न होगा और ऐसे क्षेत्र का ब्यौरा होगा। खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र आमंत्रित करेगा और ऐसी नोटिस की एक प्रति उसके कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और एक-एक प्रति उस क्षेत्र के तहसीलदार और निदेशक को भी भेजी जायेगी।

(2) उपनियम (2) के अधीन खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र उक्त उप नियम में निर्दिष्ट नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक से सात कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त किये जायेंगे। यदि फिर भी, किसी क्षेत्र के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या तीन से कम हो, तो जिलाधिकारी अवधि को अग्रतर सात कार्य दिवसों के लिये और बढ़ा सकता है और यदि उसके पश्चात भी प्रार्थना पत्र की संख्या तीन से कम रहती है तो जिलाधिकारी उक्त उप नियम के अनुसार नये सिरे से क्षेत्र की उपलब्धता को अधिसूचित करेगा।

(3) ऐसे क्षेत्र का, जो पहले से किसी पट्टा के अधीन धृत है या नियम 23 के उप नियम (1) के अधीन अधिसूचित है या अधिनियम की धारा 17-क के अधीन आरक्षित है और जिसकी उपलब्धता उप नियम (1) के अधीन अधिसूचित नहीं की गयी है खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र समय पूर्व समझा जायेगा और उस पर विचार नहीं किया जायेगा और यदि कोई प्रार्थना पत्र शुल्क दिया गया है तो उसे वापस कर दिया जायेगा।

²⁰73. **विवरणियाँ (रिटर्नस)—**

(1) इस नियमावली के अधीन खनिज परिहार धारक, पूर्ववर्ती त्रैमास के संबंध में प्रत्येक वर्ष जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में प्रपत्र एम0एम0 12 में जिला अधिकारी और निदेशक के क्षेत्रीय कार्यालय को त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

³³(2) जब कभी भी खनिज परिहारधारक उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में विफल होता है तो यह *2000.00 रुपये की शास्ति का भागी होगा।

²⁰74. **अपराधों का संज्ञान—**

(1) कोई न्यायालय, जिला अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद, जिसमें ऐसे अपराध के गठन करने वाले तथ्यों का उल्लेख होगा, के सिवाय, इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(2) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई न्यायालय इस नियमावली के अधीन अपराध का विचार नहीं करेगा।

²⁰75. **अपराधो का शमन—**

(1) इस नियमावली के अधीन—दण्डनीय किसी अपराध का शमन अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात, जिला अधिकारी द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत करे, राज्य सरकार को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर, जैसी ऐसा अधिकारी विनिर्दिष्ट करे, किया जा सकेगा:—

प्रतिबंध यह है कि केवल अर्थ दण्ड से दण्डनीय किसी अपराध की दशा में, ऐसी धनराशि उस अपराध के लिये आरोपित की जा सकने वाली अधिकतम धनराशि से अधिक नहीं होगी।

(2) जहां उपनियम (1) अधीन किसी अपराध का शमन किया जाता है, वहां इस प्रकार शमन किये गये अपराध के संबंध में, अपराधी के विरुद्ध यथास्थिति, कोई कार्यवाही या अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायेगी और अपराधी को, यदि अभिरक्षा में हो, तत्काल उन्मोचित कर दिया जायेगा।

- (3) उपनियम (1) के अधीन अपराध का शमन करने वाला अधिकारी एक रजिस्टर रखेगा जिसमें निम्नलिखित ब्योरों को दर्शाया जायेगा :-
- (क) कम संख्या (वित्तीय वर्ष तक)
- (ख) अपराधी का नाम और पता।
- (ग) दिनांक और अपराध के ब्योरे।
- (घ) शमन धनराशि और उसके भुगतान का दिनांक।
- (ङ) दिनांक और मोहर सहित अधिकारी का हस्ताक्षर।
- ²⁰76. **पुलिस की सहायता**— नियम 66 में अभिदिष्ट अधिकारी इस नियमावली के अधीन अपनी शक्तियों के विधिसम्मत प्रयोग के लिये स्थानीय पुलिस, की सहायता के लिये प्रार्थना कर सकता है, और स्थानीय पुलिस उस अधिकारी को इस नियमावली के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये आवश्यक, सभी सम्भव सहायता देगी।
- ²⁰77. **अपील**— इस नियमावली के अधीन जिला अधिकारी या समिति द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध, ऐसा आदेश क्षुब्ध पक्षकार को संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर, मण्डल आयुक्त के यहां अपील की जायेगी।
- ²⁰78. **पुनरीक्षण**— राज्य सरकार किसी भी समय या तो स्वयं या आदेश की संसूचना के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिये जाने पर जिला अधिकारी, समिति, निदेशक, या मण्डल आयुक्त द्वारा इस नियमावली के अधीन पारित किसी आदेश या की गयी किसी कार्यवाही से संबंधित अभिलेख मांग सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे।
- ²⁰79. **शुल्क**— नियम 77 के अधीन अपील या नियम 78 के अधीन कोई प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम0एम0 13 में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ एक ट्रेजरी रसीद होगी, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि नियम 64 में विनिर्दिष्ट शीर्षक के अन्तर्गत राज्य सरकार के मद में * “पच्चीस सौ रुपये” का शुल्क सरकारी कोष में जमा किया जा चुका है।

CHAPTER- IX

GRANT OF PROSPECTING LICENSE OR MINING LEASE FOR DIASPORE, PYROPHYLITE, FELSPAR, CALCITE, SILICA SAND CHINA CLAY, QUARTZ, ETC.

(40th Ammendment, 29 June 2016)

80. The provisions of this chapter shall be applicable for diaspore, pyrophyllite, dolomite, felspar, calcit silica sand, china clay, quartz and any other minerals notified by the Government of India, by notification no.S.O. 423(E), dated 10-02-2015 as a minor mineral.
81. The provision of chapters 11, IV and VI shall not be applicable to the lease granted under this chapter.
82. **Restriction on the grant of prospecting license or mining lease —**
No mining lease or prospecting license shall be granted to any person who is not an Indian National.
- Explanation** - For the purpose of this rule a person shall be deemed to be an Indian National—
- (a) in the case of a public company as defined in the Companies Act, 2013 only if a majority of the directors of the company are citizens of India and not less than fifty-one percent the share capital thereof is held by persons who are either citizens of India, or Companies as defined in the Companies Act, 2013;
- (b) in the case of a private company as defined in the companies Act, 2013 only if all the members of the company are citizens of India;

(c) in the case of firm or other association of individuals, only if all the partners of the firm or members of the association are citizens of India; and

(d) in the case of an individual, only if he is a citizen of India :

Provided that no mining lease shall be granted unless it is being satisfied that there is evidence to show that the area for which the mining lease is applied for has been prospected earlier or existence of the mineral therein has been otherwise established .

83. Application for grant of prospecting license—

(1) An application in the form MM-15 for grant of prospecting license shall be addressed to the State Government .

(2) The application referred to in sub-rule (1) shall be submitted in quadruplicate to the District Officer or to the officer authorised in this behalf by the State Government. Such officer shall endorse the receipt of the application on all the four copies entering the place, time and date of receipt. One copy shall be returned immediately to the person presenting the application.

(3) The application referred to in sub-rule (1) shall be entered in a register of prospecting license application in form **MM-19**.

84. Application for grant of mining lease—

(1) An application in form MM-16 for, grant of a mining lease or in Form MM-16 (A) for renewal shall be addressed to the State Government.

(2) The application referred to in sub-rule (1) shall be submitted in quadruplicate to the District Officer or to the officer authorised in this behalf by the State Government. Such officer shall endorse the receipt of the application on all the four copies entering the place, time and date of receipt. One copy shall be returned immediately to the person presenting the application.

(3) The application referred to in sub-rule (1) shall be entered in a register of mining lease application in form MM-17.

85. Application fee and deposit for grant of prospecting license—

(1) Every application for grant of prospecting license shall be accompanied by—

(a) a non refundable fee of ten thousand rupees, other than those specified in rule 101;

(b) Four copies of the toposheet map on a scale of 1: 50000 which shows coordinates and corresponding cadastral survey map on which the area applied for is clearly marked or four copies of topographical survey map on a scale of atleast 4"=1 mile, on which the area applied for is accurately marked;

(c) a certificate, issued by District Officer or by such officer as may be authorised by the District Officer in this behalf, showing that no mining dues are outstanding against the applicant :

Provided that such certificate shall not be required where the applicant has furnished an affidavit to the satisfaction of **the** state Government, stating that he does not hold or had not held any mining lease or any other mineral concession in the territory of the state.

(d) a certificate of residence of the applicant;

(e) a character certificate given by the District Officer of the District, where the applicant permanently resides.

(2) If the application is not complete in any respect or is not accompanied by the fee deposit or the documents mentioned in sub rule(1) the District Officer or the officer authorised by the State Government in this behalf, shall, by fifteen days notice require the applicant to complete the application in all respects or, to deposit the fee or furnish the documents within such time as may be specified in the notice and if the applicant fails to do so within the specified time, such application shall not be considered.

86. Application fee and deposit for grant of mining lease—

(1) Every application for grant of mining lease shall be accompanied by—

- (a) a non-refundable fee of twenty five thousand rupees, other than those specified in rule 101; and
- (b) Four copies of the topographical survey map on a scale of 1: 50000 with coordinate and corresponding cadastral survey map on which the area applied for is clearly marked or four copies of topographical survey map on a scale of at least 4"=1 mile, on which the area applied for is accurately marked;
- (c) a certificate, issued by District Officer or by such officer as may be authorised by the District Officer in this behalf, showing that no mining dues are outstanding again.;t the applicant :

Provided that such certificate shall not be required where the applicant has furnished an affidavit to the satisfaction of the state Government, stating that he does not hold or had not held any mining lease or any other mineral concession in the territory of the state;

- (d) certificate of residence of the applicant;
- (e) a character certificate given by the District Officer of the District, where the applicant permanently resides;
- (f) Solvency certificate.

(2) If the application is not complete in any respect or is not accompanied by the fee, deposit or the documents mentioned in sub-rule(1) the District Officer or the officer authorised by the State Government in this behalf, shall, by fifteen days notice require the applicant to complete the application in all respects or, to deposit the fee or furnish the documents within such time as may be specified in the notice and if the applicant fails to do so within the specified time, such application shall not be considered.

87. Application fee etc for renewal of mining lease-

(1) An application for renewal of mining lease may be made atleast six months before **the date** of expiry of the mining lease along with four copies of the map of lease **hold area showing clearly the** area applied for renewal and the provisions of clauses (a) and (c) of sub-rule (1) **of rule 86 shall *mutatis mutantis* apply .**

(2) The State Government may condone the delay cause in making the application for renewal of mining lease after the period specified in sub-rule(1).

88. Enquiry and reports—

The District officer shall, unless he is authorised to grant or renew the mining lease or grant prospecting license cause an enquiry through Senior Mines Officer / Mines Officer / Mines Inspector of the concerned district to be made into all relevant and technical matters and, within two months from the date of receipt of application of mining lease, forward two copies of the application alongwith his report to the State Government or to such other authority as the State Government may authorise in this behalf.

89- Disposal of Application (I) The State Government or the authority authorised by it in the behalf may, subject to the provisions of these rules and after making such further enquiry as it may consider necessary-

- (a) in case of application for grant of a mining lease or prospecting licence ,refuse or grant the mining lease for the whole or part of the area applied for and for such period as it may consider proper.
- (b) in case of application for renewal of a mining lease, refuse or renew the mining lease for the whole or part of the area applied for and for such period, not exceeding the period of the original lease, as it may consider proper :

Provided that where an application for grant or renewal of a mining lease or grant of prospecting license is refused or the area is reduced, reasons therefor shall be recorded

and communicated to the applicant :

Provided further that if the application for the grant of mining lease or prospecting license is not disposed off within 12 months from the date of receipt , it shall be deemed to be refused .

- 90. Preferential right for prospecting licence or mining lease where area has been declared under rule 104 (1)** Where the availability of area/areas are declared by the District Officer for grant of prospecting licence or mining lease under the provisions of rule 104, all the applications received during the period specified in such declaration shall be deemed to be received on the same day and shall be considered simultaneously after taking into consideration matters specified in sub-rule (2) and shall grant the mining lease to such one of the applicants as he/she may deem fit.

(2) The matters referred to in sub-rule (1) are -

- (a) any special knowledge or experience possessed by the applicant.
- (b) an intent to establish any value addition or processing or manufacturing unit.
- (c) The Financial resources of the applicant.
- (d) The nature and quality of the technical staff employed or to be employed by the applicant.
- (e) The conduct of the applicant in carrying out mining operations on the basis of any previous lease or permit and complying with conditions of such lease or permit of the provisions of any law in connection therewith; and
- (f) Such other matters, as may be considered necessary by the State Government.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2) leases for one third of the mining areas of Naxal affected villages as declared by the State Government by general order may be granted to the Self Assistance groups containing the members of the local residents where such leases are situated and such one third areas shall be marked for the purpose by the District Officer of the district, after seeking such approval from the State Government:

Provided that those Self Assistance groups will be entitled for getting preference under sub-rule (3) in which one third members belong to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/members of these casts traditionally engaged in sand mining such as Mallah, Kewat, etc. and are resident of the same village, where the lease areas are situated.

- 91. Preferential right for prospecting license where area is not declared for grant under rule 104 shall be as under :-**

(1) An application which has been received earlier shall have preference over subsequent application .

(2) If the application is received on same day , the preference shall be decided on following matter :

- (a) any special knowledge or experience in prospecting operation and the nature and quality of technical staff employed or to be employed by the applicant ;
- (b) such other matters as may be considered necessary by the State Government.

- 92. Preferential right for mining lease where prospecting licence has been granted in respect of any land:-** Where a prospecting licence has been granted in respect of any land, the licensee shall have a preferential right for obtaining a mining lease in respect of that land over any other person if the State Government is satisfied that the licensee has—

- (a) undertaken prospecting operations to establish mineral resources;
- (b) not committed any breach of, the terms and conditions of the prospecting licence.

- 93. Extent of area for which a mining lease or prospecting licence may be granted —**
- (1) Minimum area for grant of a prospecting licence or mining lease for minerals mentioned in chapter IX shall be five hectare.
- (2) No mining lease shall be granted in respect of any area which is not compact and contiguous or otherwise not suitable to scientific development :
 Provided that in respect of small deposits not suitable to scientific mining in isolated patches a mining lease may be granted for a cluster of such deposits without any division.
- (3) No person shall acquire in respect of minor mineral mentioned in this chapter more than 3 mining lease , covering a total area of four hundred hectare .
- (4) No person shall acquire one or more prospecting licence , covering a total area of five hundred hectare :
 Provided further that if the State Government is of opinion that in the interest of mineral development, it is necessary so to do, it may for reasons to be recorded in writing permit any person to acquire one or more mining leases covering an area in excess of the limits mentioned in this rule .
- Explanation:** For the purposes of these rules, a person acquiring by or in the name of another person a mining lease which is intended for himself shall be deemed to be acquiring, it himself.
- 94. Length and breadth of the area to be leased –** The length of an area under a mining lease shall ordinarily not exceed four times its breadth.
- 95. Period of mining lease and prospecting license –** (1)A mining lease in respect of minerals shall be granted for a period not less than twenty years-and not more than thirty years.
 (2) Prospecting license shall be granted for a fixed period of two years .
- 96. Security deposit (1)** An applicant for a mining lease shall, before the deed referred to in rule 99 is executed and in such manner as the State Government may by order specify deposit as security, for the due observance of the terms and conditions of the lease, a sum equal to twenty five percent of the annual deadrent of the leased area subject to the minimum of Rs. 50,000.00 (fifty thousand rupees) and no interest shall be payable on such security deposit.
 (2) The security deposit for prospecting license shall be Rs. 25,000.00 (twenty five thousand rupees) and no interest shall be payable on such security deposit .
- 97. Prospecting license deed to be executed within three month :-** Where an order has been made for grant of prospecting license , the deed in form MM-3(A) shall be executed within 3 month and the date of commencement of prospecting license shall be effective from the date of execution or within such further period as the District Officer or the Committee, as the case may be, allow in this behalf.
- 98. Every prospecting license granted under these rules be subject to the following condition:-**
- (1) The licensee shall pay a prospecting fee of Rupees 100.00 per hectare of land covered by license for each year or part thereof for which the license is granted subject to minimum of Rupees 5000.00, which can be changed from time to time by the State Government.

- (2) The licensee may win and carry for purposes other than commercial purposes —
- (a) thirty cubic meter of such mineral without any payment ;
 - (b) hundred cubic meter of such mineral on payment of royalty :
- Provided that if any quantity in excess of the quantities mentioned above is won and carried away, the State Government may recover the cost of the excess quantity of minerals mentioned in clause(b) above; won and carried away .
- (3) With the written approval of the State Govt , the licensee may carry away quantities of minerals in excess of the limits specified in sub-rule (2) .
- (4) Save in the case of land in respect of which the licensee is granted a mining lease , the licensee shall , within 90 days from the date of determination of the licence or the date of **abandonment of the** prospecting operations , whichever is earlier , securely plug all bores and fill up or fence all excavations .
- (5) The licensee shall report to the State Government the discovery-of any mineral not specified in the licence within sixty days from the date of such discovery .
- (6) The licensee shall not transfer his licence except with the previous sanction of the State Government.
- (7) The licensee shall restore , to the extent possible , other flora destroyed by prospecting operation .
- (8) The licensee shall pay to the occupier of surface of land such compensation as may become payable under these rules .
- (9) The State Government may impose such further conditions as may be considered necessary in the interest of mineral development .
- (10) In case of breach of any condition imposed on any holder of prospecting licence under these rules , the State Government may , by order in writing , cancel the licence and / or forfeit the security amount deposited by the licensee under rule 96(2) after giving opportunity of hearing .
- (11) Any ,security deposit made under rule 96(2) , if not forfeited under these rules , shall be refunded to the applicant after expiry of the licence.
- (12) Every licensee shall maintain account of all expenses incurred' by him on prospecting operations and also the quantity and other particulars of all minerals obtained during such operations and there dispatch thereof.
- (13) The licensee shall, after the survey and demarcation of the area granted under the licence and before executing the licence deed, at his own expense, erect and at all times maintain and keep in good repair boundary marks and pillars necessary to indicate the demarcation shown in the plan annexed to the licence deed.
- (14) The licensee shall pay such reasonable compensation as may be assessed by the State Government if any damage, injury or disturbance occurs by any act of the licensee.
- (15) The licensee shall allow any officer authorised under rule 66 or by the Central Government or the State Government in that behalf to enter upon the premises including any building, excavation or land comprised in the lease for the purpose of inspecting, examining, surveying and making plans there of, sampling and collecting any data and the licensee shall with suitable person in his employment and

acquainted with the mines and work, properly assist, such officer and his agents, servants and workmen in conducting every such inspection, and shall afford and furnish to them all facilities information, etc..connected with the working of the mines, which they may reasonably require, and shall also conform to and observe all orders and regulations which the Central Government or the State Government, as a result of such inspection or otherwise, may from time to time deem fit to make.

(16) The licensee shall without delay, send to the District Officer a report of any accident, causing death or serious bodily injury or serious injury to property, or seriously affecting or endangering life or property, which may occur in the course or any operations under the licence.

99. Mining Lease deed to be executed within six month:

(1) Where an order has been made for the grant of mining lease, a lease deed in Form MM-3 or in a form as near thereto as the circumstances of each case may require, shall be executed within six months of the communication of the said order or within such - further period as the State Government may allow, in this behalf. If no such deed is executed within the aforesaid period due to any default on the part of the applicant, the State Government may revoke the order granting the lease and in that event the application fee and security amount shall be forfeited to the State Government.

(2) The date of commencement of a mining lease referred to in sub-rule (1) shall be the date on which the deed is executed under the said sub-rule.

100. Restriction on determination of mining lease — No lessee shall determine a mining lease except after giving a notice in writing of not less than six months to the State Government.

101 Survey of the area licenced or leased –

(1) When a mining lease or prospecting licence is granted, arrangement shall be made by the Director for survey and demarcation of the area granted under the lease or licence for which lessees/ licensees shall be charged at the following rates :

For mining leases :- (1) for areas upto 10 hectares Rs. 10, 000.00

(ii) for areas beyond 10 hectares at the rate of Rs. 500.00 per hectare subject to the minimum of Rs. 15,000.00

For prospecting licence (i) for areas upto 10 hectares Rs. 5,000.00

(ii) for areas beyond 10 hectares at the rate of Rs. 250.00 per hectare subject to the minimum of Rs. 10,000.00

(2) The lessee or licensee shall, after the lease or licence is granted to him , pay the demarcation charges through treasury challan and submit a map of the area granted under the lease or licence, certified by the District Officer, to the concerned Mines Officer or to such other officer as may be authorised by the Director in this behalf the Mines Officer or the officer so authorised shall, on receipt of the certified map and satisfying that delimitation charges have been deposited, survey and demarcate the area within thirty days

from the date of such receipt.

(3) The Mines Officer or the officer so authorised may, for the purpose of survey and demarcation of the area, take the help of such officer of the revenue and forest department of the district as he may consider necessary.

(4) If any dispute arises in respect of demarcation of the area, the matter shall be referred to the Director, who shall, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard, decide the matter.

(5) The decision of the Director under sub-rule (4) shall be final.

102 Boundaries below the surface :- The boundaries of the area covered by a mining lease shall run vertically downwards below the surface towards the centre of the earth.

103 Registers : The following registers shall be maintained in the office of the District-Office-

(a) a register of applications for prospecting licence in Form MM-19, and

(b) a register of prospecting licence in Form MM-20,

(c) a register of applications for mining leases in Form MM-17, and

(d) a register of mining leases in Form MM-18 .

104 Availability of area for regrant on prospecting licence or mining 1, to be notified- (I) If

any area, which was held under a mining lease under Chapter - IX or under Mineral Concession Rules, 1960 or reserved under section 17- A of the MMDR Act., becomes available for regrant on prospecting licence or mining, lease, the District Officer shall notify the availability of the area through a notice inviting applications for grant of prospecting license or mining lease specifying a date, which shall not be earlier than thirty days from the date of notice and giving description of such area and a copy of such notice shall be displayed on the notice board of his office and shall also be sent to the Tehsildar of such area and the Director.

(2) The applications for grant of prospecting licence or mining lease under sub-rule (1) shall be received within seven working days from the date specified in the notice referred to in the said sub-rule, if, however, the number of applications received for any area is less than three, the District Officer may further extend the period for seven more working days and if even thereafter, the number of applications remain less than three, the District Officer shall notify the availability of this area a fresh in accordance with the said sub -rule.

(3) An application for grant of prospecting licence or mining lease for such area which is already held under a lease or notified under sub-rule (1) of rule 23 or reserved under section 17-A of the Act and whose availability has not been notified under sub-rule (1) shall be deemed to be premature and shall not be considered.

Government Of Uttar Pradesh

Udyog (Cha) Vibhag

Notification

August 26, 1963

No. 1575-M/XVIII-B-M-96-58 In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act, no. 67 of 1957), the Governor of Uttar Pradesh is pleased to make the following rules, namely:

THE UTTAR PRADESH MINOR MINERALS (CONCESSION) RULES, 1963 .

CHAPTER-1

Preliminary

1. Short title, extent, commencement and application:-

- (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 1963.
- (2) They shall extend to the whole of Uttar Pradesh.
- (3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.
- ²⁰(4) They shall apply to all the minor minerals available in the state.

⁴⁷2. Definitions: In these rules, unless the context otherwise requires

- (a) "Act" means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act No. 67 of 1957):
- (b) **"Captive mines" shall mean the mining lease where more than 50 percent of the entire quantity of mineral extracted from the lease is used in an industry owned by the lessee.**
- (c) "Committee" means the Committee, consisting of the District Officer as Chairman and the representatives of the Director and the Divisional Forest Officer as members, constituted by the State Government Notification No. 4343/18-12-90-601/87, dated August 29, 1990, whom the State Government has delegated its power under rule 71 in respect of reserve forest areas:
- (d) "Director" means the Director of Geology and Mining. Uttar Pradesh
- (e) "District Officer" means the Collector or Deputy Commissioner of the district in which the land is situated.

- (f) "Form" means a form set out in the Third Schedule to these rules:
- (g) "In situ rock deposit" means the mineral found in the form of rock and not displaced from the place of its origin:
- (h) "Mine" and "Owner" shall have the meanings respectively assigned to them in the Mines Act, 1952 (Act No. 35 of 1952);
- (i) "Mining operations" means any operations undertaken for the purpose of winning any minor mineral;
- (j) "Mining permit" means a permit granted under these rules to extract a specified quantity of minor mineral within the period stipulated in the permit:
- (k) "Minor minerals" means building stones, gravel, ordinary clay, ordinary sand other than sand used for prescribed purposes, and any other mineral which the Central Government has declared from time to time or may declare, by notification in the official Gazette, to be a minor mineral, under clause (e) of section 3 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act No. 67 of 1957);
- (l) "Pits mouth value" means the sale price of the minor mineral at the pit head or at the point of production:
- (m) "Railway" and "Railway Administration" shall have the meanings respectively assigned to them in the Indian Railways Act, 1890 (Act NO.9 of 1890);
- (n) "Schedule" means a Schedule appended to these rules:
- (o) "State" and "State Government" respectively mean the State of Uttar Pradesh and Government of Uttar Pradesh.

3. Mining operations to be under a mining lease or mining permit

- (1) No person shall undertake any mining operations in any area within the State of any minor minerals to which these rules are applicable except under and in accordance with the terms and conditions of a mining lease or mining permit granted under these rules:

Provided that nothing shall affect any operations undertaken in accordance with the terms and conditions of mining lease or permit duly granted before the commencement of these rules.

³⁷**Explanation:-** For the purposes of this rule manual digging or manual extraction of ordinary clay, ordinary earth for making bricks and pottery shall not be treated as mining operations :

Provided that pit created by such digging or extraction should not be deeper than two meters.

- (2) No mining lease or mining permit shall be granted otherwise than in accordance with the provisions of these rules.

CHAPTER II
GRANT OF MINING LEASE

4. Restriction on the grant of mining lease

No mining lease shall be granted to any person who is not an Indian national

Explanation: - For the purpose of this rule, a person shall be deemed to be an Indian national-

- (a) in the case of a public company as defined in the Companies Act, 1956, only if a majority of the directors of the company are citizens of India and not less than fifty-one percent of the share capital thereof is held by persons who are either citizens of India, or Companies as defined in the Companies Act, 1956;
- (b) in the case of a private company as defined in the companies Act, 1956 only if all the members of the company are citizens of India:
- (c) in the case of firm or other association of individuals, only if all the partners of the firm or members of the association are citizens of India, and
- (d) in the case of an individual, only if he is a citizen of India.

⁴³5. Application for grant of mining lease-

- (1) An Application in form MM-1 for grant of a mining lease shall be addressed to the State Government.
- (2) The application referred to in sub-rule (1) shall be submitted in quadruplicate to the District Officer or to the officer authorized in this behalf by the State Government. Such officer shall endorse the receipt of the application on all the four copies entering the place, time and date of receipt. One copy shall be returned immediately to the person presenting the application.
- (3) The application referred to in sub-rule (1) shall be entered in a register of mining lease application in form MM-2.

6. Application fee and deposit for grant of mining lease:

- (1) Every application for grant of mining lease shall be accompanied by-
 - ⁶(a) a non refundable fee of Five thousand rupees:
 - (b) a non refundable deposit of ten thousand rupees for meeting the preliminary expenses, other than those specified in Rule 17, and
 - (c) four copies of the cadastral survey map on which the area applied for is clearly marked and in case such area is not covered by cadastral survey, four copies of topographical survey map on a scale of at least 4" = 1 mile, on which the area applied for is accurately marked,
 - (d) a certificate, issued by District Officer or by such officer as may be authorised by the District Officer in this behalf, showing that no mining dues are outstanding against the applicant:

Provided that such certificate shall not be required where the applicant has furnished an affidavit to the satisfaction of the State Government, stating that he does not hold or had not hold any mining lease or any other mineral concession in the territory of the State;

- (e) a certificate of caste and residence of the applicant, where the application is for mining lease of sand or morrum or bajri or boulder or any of these in mixed state;
- (f) a character certificate given by the District Officer of the District, where the applicant permanently resides
- ²⁹(g) in case the area applied for is having annual lease amount or dead rent ,as the case may be, of rupees two lacs or more, then the applicant shall also furnish no objection certificates of the following authorities:-
 - (i) Authorised Officer of the Income Tax Department
 - (ii) Authorised Officer of the Trade Tax Department
 - (iii) District Magistrate of the District, where the applicant permanently resides,
 - (iv) Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police of the district, where the applicant permanently resides.
- (2) If the application is not complete in any respect or is not accompanied by the fee, deposit or the documents mentioned in sub-rule (1) the District Officer or the officer authorised by the State Government in this behalf, shall, by fifteen days notice, require the applicant to complete the application in all respects or, to deposit the fee or furnish the documents within such time as may be specified in the notice and if the applicant fails to do so within the specified time, such application shall not be considered.

6-A. - Omitted by 43rd Amendment

⁴³7- Enquiry and reports-

The District officer shall, unless he is authorised to grant the mining lease cause an enquiry to be made into all relevant matter and, within two months from the date of receipt of application of mining lease, forward two copies of the application alongwith his report to the State Government or to such other authority as the State Government may authorize in this behalf.

⁴³8. Disposal of Application:-

- (1) The State Government or the authority authorised by it in this behalf may approve or reject, subject to the provisions of these rules and after making such further enquiry as it may consider necessary, refuse or grant the application for grant of the mining lease for the whole or part of the area applied for and for such period as it may consider proper.

Provided that where an application for grant of mining lease is refused or the area is reduced, reasons therefore shall be recorded and communicated to the applicant.

9. Preferential right of certain persons

- (1) Where the availability of area/areas are declared by the District Officer for grant of mining lease under the provisions of rule 72, all the applications received during the period specified in such declaration shall be deemed to be received on the same day and shall be considered simultaneously after taking into consideration matters specified in sub-rule(2) and shall grant the mining lease to such one of the applicants as he/she may deem fit.
- (2) The matters referred to in sub-rule (1) are-
 - (a) Any special knowledge or experience in mining operations possessed by the applicant;
 - (b) The Financial resources of the applicant;
 - (c) The nature and quality of the technical staff employed or to be employed by the applicant;
 - (d) The conduct of the applicant in carrying out mining operations on the basis of any previous lease or permit and in complying with conditions of such lease or permit or the provisions of any law in connection therewith; and
 - (e) Such other matters, as may be considered necessary by the State Government.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), (2) leases for one third of the mining areas of Naxal affected villages, as declared by the State Government by general order may be granted to the Self Assistance groups containing the members of the local residents where such leases are situated and such one third areas shall be marked for the purpose by the District Officer of the district, after seeking such approval from the Government.

Provided that those Self Assistance groups will be entitled for getting preference under sub-rule(3) in which one third members belong to Schedule Caste/Schedule Tribe/members of the Castes traditionally engaged in sand mining such as Mallah, Kewat, etc. and are resident of the same village, where the lease areas are situated.

⁴²9A - -Omitted by 42nd amendment

⁴⁷10. Extent of area for which a mining lease may be granted

- (1) Minimum area for grant of a mining lease for sand or morrum or bajri or boulder or any of these in mixed state exclusively found in river bed shall ordinarily be five hectares and mineral found in the form of rock and not displaced from the place of its origin and other minor minerals shall be one hectare.

Provided that in case of non availability of such extent of area, this sub rule does not apply.

- (2) No mining lease shall be granted in respect of any area which is not compact and contiguous or otherwise not suitable to scientific development:

Provided that in respect of small deposits not suitable to scientific mining in isolated patches, a Mining lease may be granted for a cluster of such deposits without any division.

- (3) No person shall acquire in respect of any minor mineral, except sand or morrum or bajari or boulder or any of these in mixed state exclusively found in river-bed, exceeding three mining leases, covering a total area of more than 25 Hectares.

Provided that mining leases in respect of sand or morrum or bajari or boulder or any of these in mixed state, exclusively found in the riverbed exceeding *two in number or total fifty Hectares in area shall not be granted in favour of any person in the State of Uttar Pradesh.*

Provided further that if the State Government is of opinion that in the interest of mineral development, it is necessary so to do, it may for reasons to be recorded in writing permit any person to acquire one or more mining leases covering an area in excess of the limits mentioned above.

Explanation: For the purposes of these rules, a person acquiring by or in the name of another person a mining lease which is intended for himself shall be deemed to be acquiring it himself.

11. Length and breadth of the area to be leased

The length of an area under a mining lease shall ordinarily not exceed four times its breadth.

⁴³12. Period of Mining lease :-

- (1) Except as provided in sub-rule(2), a mining lease in respect of sand or morrum or bajari or boulder or any of these in mixed state exclusively found in the river bed shall be granted for a fixed period of five years and in respect of other minor minerals for a period not less than five years and not more than ten years.
- (2) If the State Government is of opinion that in the interest of mineral development, it is necessary so to do, it may for reasons to be recorded in writing grant a mining lease of minor minerals, except the minerals exclusively found in the river bed, for any period exceeding 10 years but not exceeding 15 years.

³³13. Security deposit

An application for a mining lease shall, before the deed referred to in rule 14 is executed and in such manner as the State Government may by order specify deposit as security, for the due observance of the terms and conditions of the lease, a sum equal to twenty five percent of the annual dead rent or annual lease amount of the leased area subject to the minimum of Rs. 10,000.00 (Rupees ten thousand). No interest shall be payable on such security deposit.

²¹14. Lease deed to be executed within three months-

- (1) Where an order has been made for the grant of mining lease other than a mining lease for sand or morrum or bajari or boulder or any of these in mixed state a lease deed in Form MM-3

or in a form as near thereto as the circumstances of each case may require, shall be executed within three months of the communication of the said order or within such further period as the State Government may allow, in this behalf. If no such deed is executed within the aforesaid period due to any default on the part of the applicant, the State Government may revoke the order granting the lease and in that event the application fee and security amount shall be forfeited to the State Government.

- (2) The date of commencement of a mining lease referred to in sub rule(1) shall be the date on which the deed is executed under the said sub-rule.
- (3) Where an order has been made for the grant of a mining lease for sand or morrum or bajari or boulder or any of these in mixed state, twenty five percent of the annual lease amount shall be deposited within seven days of the order or within such further period as may be allowed by the District Officer not exceeding seven days and a lease deed in form MM-3 or in a Form as near there-to-as the circumstances of each case may require, shall be executed within one month of the communication of the said order or within such further period as the State Government may allow in this behalf. The lease amount shall in respect of sand or morrum be determined on the basis of the average of the amount received during the last three years from that area or the amount received in the preceding year from such area which ever is higher and in respect of sand, bajari, and boulder or any of these in mixed state be determined on the basis of the highest amount received during the last three years. If no lease amount is deposited or no lease deed is executed within the aforesaid period due to any default on the part of applicant, the State Government may revoke the order granting the lease and in that event the application fee and security amount shall be forfeited to the State Government.
- (4) The date of commencement of mining lease referred to in subrule(3) shall be the date on which the deed is executed under the said subrule or the date of actual commencement of mining operation which ever is earlier.
- (5) In case a lease referred to in subrule (3) is granted during the period of an year mentioned in column I of the schedule below, the annual lease amount shall be deposited in respect of the first and subsequent years of the period of lease, in the instalments of such percentage of the annual lease amount and before such dates as are mentioned against each in the respective columns thereof namely:

²¹Schedule of Deposit

Period During which lease is Granted	Percentage of lease amount deposited under subrule (3)	Instalments in the first Year			Instalments in the Subsequent years		
		I	II	III	IV		
		1st	2nd	3rd	1st	2nd	3rd
January to March	25%	25% July, 1	25% Oct., 1	25% Jan., 1	50% April, 1	25% Oct., 1	25% Jan. 1
April to June	25%	25% Oct., 1	50% Jan., 1	- -	25% Oct., 1	25% Jan., 1	50% April, 1
July to September	25%	25% Jan., 1	50% April, 1	- -	25% Oct., 1	25% Jan., 1	50% Apri.1
October to December	25%	50% April, 1	25% July, 1	- -	25% Oct., 1	25% Jan., 1	50% Apri.1

²⁰**15. Refund of fee**

- (1) Where an application for grant or renewal of a mining lease is refused, the fee paid by the applicant under clause (a) of sub-rule (1) of rule 6 or under rule 6-A shall be refunded to him.
- (2) Where the whole or part of the amount deposited under clause (b) of sub-rule (1) of rule 6 has not been expended for the purposes specified in the said clause, it shall be refunded to the applicant:

Provided that in case the amount to be expended for the purposes specified in the said clause (b) is more than the amount deposited under that clause, that applicant shall have to deposit the extra amount as may be determined by the State Government

- (3) Unless the State Government having regard to the facts of a particular case direct otherwise, the application fee shall not be refunded on an application being withdrawn.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), where an application for grant or renewal of a mining lease is refused on account of any lapse on the part of the applicant, the application fee and preliminary expenses shall not be refunded and forfeited to State Government.

²⁰**16. Restriction on determination of mining lease**

No lessee shall determine a mining lease except after giving a notice in writing of not less than six months to the State Government.

⁴⁷**17. Survey of the area leased**

- (1) When a mining lease is granted, arrangement shall be made by the Director for survey and demarcation of the area granted under the lease for which lessees shall be charged at the following rates:
 - (a) in the plains
 - (i) for area up to 10 hectares Rs. 5,000.00
 - (ii) for areas beyond 10 hectares at the rate of Rs. 500.00 per hectare subject to the minimum of Rs. 6,000.00
 - (b) in the hills
 - (i) for areas up to 10 hectares Rs. 8,000.00
 - (ii) for areas beyond 10 hectares at the rate of Rs. 800.00 per hectare subject to the minimum of Rs. 10,000.00
- (2) The lessee shall, after the lease is granted to him, pay the demarcation charges through treasury challan and submit a map of the area granted under the lease, certified by the District Officer, to the concerned Mines Officer or to such other officer as may be authorised by the Director in this behalf. The Mines Officer or the officer so authorised shall, on receipt of the certified map and *upon being satisfied that demarcation charges have been duly deposited, within fifteen days from the date of such receipt, survey and demarcate the area taking as reference atleast two fixed points on the map and denoting the geo-coordinates of all the boundary pillars of the demarcated lease area .*

- (3) The mines officer or the officer so authorised may, for the purpose of survey and demarcation of the area, take the help of such officer of the revenue and forest department of the district as he may consider necessary.
- (4) If any dispute arises in respect of demarcation of the area, the matter shall be referred to the Director, who shall, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard, decide the matter.
- (5) The decision of the Director under sub-rule (4) shall be final

18 Boundaries below the surface:- The boundaries of the area covered by a mining lease shall run vertically downwards below the surface towards the centre of the earth.

²³**19. Transfer of lease** (1) A lessee shall not -

- (a) assign, sublet, mortgage, or in any other manner transfer the mining lease, or any right, title or interest therein; or
- (b) enter into or make any arrangement, contract or understanding whereby the lessee may be directly or indirectly financed to a substantial extent or may be substantially controlled in mining operations by any person or body of persons other than himself:

Provided that a lessee may, with the prior approval of the State Government and subject to such conditions and restrictions, as may be imposed by it, mortgage to a finance corporation owned and controlled by the State Government or to a scheduled Bank as defined in clause (a) of Section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934 or a Bank specified in Column of the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and transfer of undertaking) Act 1970; or, assign to any other person a mining lease or any right, title or interest therein.

- (2) The State Government, may by an order in writing, determine any lease at any time if the lessee has, in the opinion of the State Government assigned, sublet, mortgaged or in any other manner transferred the mining lease or any right, title or interest therein or entered into or made any arrangement, contract or understanding without its prior approval or has committed breach of any condition or restriction specified by the State Government in this behalf:

Provided that no such order shall be made without giving the lessee a reasonable opportunity of stating his case.

²⁰**20. Registers:**

The following registers shall be maintained in the office of the District Officer:

- (a) a register of applications for mining leases in Form MM-2, and
- (b) a register of mining leases in Form MM-4.

CHAPTER-III

PAYMENT OF ROYALTY AND DEADRENT

⁴⁸**21. Royalty** (1) The holder of a mining lease granted on or after the commencement of these rules shall pay royalty in respect of any mineral removed by him from the lease area at the rates for the time being specified in the First Schedule to these rules

- (1-a) Notwithstanding anything to the contrary contained in rule 3, royalty should be payable by concerned brick kiln owner or use of ordinary clay on ordinary earth at the rate, for the time being, specified in First Schedule to these rules.

Provided that the State Government shall take fees to be known as Regulating Fees from brick kiln owners in respect of district categorized, on the basis of payon at such rates as may be notified from time to time by it.

- (2) The State Government may, by notification in the Gazette, amend the First Schedule so as to include therein or exclude there from or enhance or reduce the rate of royalty in respect of any mineral with effect from such date as may be specified in the notification.

Provided that the State Government shall not enhance the rate of royalty in respect of any mineral for more than once during any period of three years and shall not fix the royalty at the rate of more than 20 percent of the pit's mouth value,

- (3) Where the royalty is to be charged on the pit's mouth value of the mineral, the State Government may assess such value at the time of the grant of the lease and the rate of royalty will be mentioned in the lease deed. It shall be open to the State Government to reassess not more than once in a year the pit's mouth value if it considers that an enhancement is necessary.
- (4) Regulating Fees may be determined by the State Government from time to time on minerals entering the State from other States.

²²**22. Dead Rent**

The holder of a mining lease shall, during the terms of the lease, pay advance, in instalments for every year of the lease, such amount as dead rent at the rates mentioned in the second schedule to these rules, as may be specified in the lease deed by the State Government, and if the terms of lease permit the working of more than one mineral in the same area, the said dead rent shall be paid separately for each such minerals.

Provided that the lessee shall in respect of each mineral, pay the dead rent or the royalty, whichever is higher in amount and not the both.

CHAPTER-IV AUCTION LEASE

⁵⁰**23. Declaration of area for e-tender/ e-auction /e-tender -cum-e- auction lease**

- (1) The State Government may by general or special order declare the area or areas with Geo-coordinates which may be leased out by e-tender/ e-auction /e-tender -cum-e- auction.
- (2) Subject to direction issued by the State Government from time to time in this behalf-

- (a) The area or areas for mining leases in respect of sand or morrum or bajari or boulder or any of these in mixed state exclusively found in the river-bed shall be leased out only by e-tender or e-auction or e-tender-cum-e-auction for the fixed period of five years at a time.

Provided that, if for any reason, it is not possible to settle the river bed mining areas for the long term, the areas may be settled through short term mining permit. Short term permit will be granted for a maximum period of 06 months by etender/e-auction, under terms and conditions laid down by the State Government from time to time:

Provided further that in case of grant of mining permit, the permit holder shall make payment of all due amount in advance.

- (b) New area of natural rocks of building stones and earlier leased area/areas, which has/have been treated as redeemed after expiration of period of lease and will not be renewed, may be leased for a maximum period of twenty years only through the process of e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction.

Provided that the earlier lease-holder of the concerned lease area, whose lease had been determined recently, has to be accommodated an opportunity to offer bid of higher amount than the highest bid shorted out for the concerned lease, within one working-day after the finalization of the entire process of e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction

and before issuance of Letter of Intent, before the District Magistrate having territorial jurisdiction over the concerned lease area, however with conditions that:-

- I) The character of the earlier lease-holder bears good conduct;
- II) He has abided fairly all the norms during the course of the entire lease period;
- III) He has no any due amount concerning mineral/mining;
- IV) His name is not mentioned inter alia black list;
- V) He has been a lease – holder of the concerned area or more than that area and has produced certified document/s concerning the same;
- VI) He has participated for bid as per the prescribed process/procedures through e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction with the required proper document/s concerning the e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction.

Provided that the lease holder of more than 02 hectare area will have to install stone crusher within 2 years from execution of lease deed.

- (c) Naturally available rock type such mineral deposit which had been defined earlier as major mineral and that has been declared minor mineral, vide Notification No. 423 Dated 10.02.2015 issued by the Government of India and new mining area containing embedded Granites (sized dimensional) shall be leased out as prospecting license cum mining lease for the maximum period of thirty two (32) years in one term through the proper process of e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction, however out of the above mentioned period of thirty two years, two years period will be reserved for prospecting works and on being proved availability of mineral the lease period shall be for maximum thirty (30) years.

If any area has remained on lease since before or availability of mineral has already been approved within the concerned area then in such cases the mining lease will be approved directly for a maximum period of thirty years :

Provided that the earlier lease-holder of the concerned lease area whose lease had terminated recently has to be accommodated an opportunity to offer bid of higher amount than the highest bid shorted out for the concerned lease, within one working-day after the finalization of the entire process of e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction and before issuance of Letter of Intent, before the District Magistrate having territorial jurisdiction over the concerned lease area however with conditions that:-

- I) The character of the earlier lease-holder bears good conduct;
 - II) He has abided fairly all the norms during the course of the entire lease period;
 - III) He has no any due amount concerning mineral/mining;
 - IV) His name is not mentioned inter alia black list;
 - V) He has been a lease – holder of the concerned area or more than that area and has produced certified document/s concerning the same;
 - VI) He has participated for bid as per the prescribed process/procedures through e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction with the required proper document/s concerning the e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction.
- (d) Naturally available in-situ rock-type mineral found in private land of minimum area one hectare shall be leased out for a maximum period of 10 years through e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction.

Provided that in respective mine area the District Magistrate after confirming the availability of mineral, suitability of area, certificate of land ownership, land owner's affidavit for consent, shall process e-tender/ e-auction/e-tender cum e-auction after determination of quantity and period not exceeding ten years. The land owner/ owners after completion of e-auction process of the area will take cognizance of the highest bid and within seven working days get an opportunity to present an offer higher than the highest bid before the District Magistrate having territorial jurisdiction over the concerned area. If this right of first refusal is not exercised by the land owner/owners,

the lease will be approved in favour of the highest bidder and the land owner/owners will have the right to receive a compensation equal to the amount as decided by the State Government from time to time, which will be in addition to the amount payable to the State Government. Payment to land owner/owners will be mandatory along with the payment to the State Government.

- (e) Private land situated in the river bed of area minimum 01 hectare in which sand or morrum or Bajri or Boulder or any of these in mixed state is available shall be leased out for the maximum period of 06 months through e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction.

Provided that in respective mine area the District Magistrate after confirming the availability of mineral, suitability of area, certificate of land ownership, land owner's affidavit for consent, shall process e-tender/ e-auction/e-tender cum e-auction after determination of quantity and period not exceeding six months. The land owner/owners after completion of e-auction process of the area will take cognizance of the highest bid and within seven working days get an opportunity to present an offer higher than the highest bid before the District Magistrate having territorial jurisdiction over the concerned area. If this right of first refusal is not exercised by the land owner/owners, the lease will be approved in favour of the highest bidder and the land owner/owners will have the right to receive a compensation equal to the amount as decided by the State Government from time to time, which will be in addition to the amount payable to the State Government. Payment to land owner/owners will be mandatory along with the payment to the State Government.

- (3) On the declaration of the area under sub-rule (1) the provisions of chapters II, III, VI and IX except rules 10, 12, 17 and 93 shall not apply to the area or areas in respect of which the declaration has been issued. Such area or areas may be leased out according to the procedure described in this chapter.
- (4) The District Officer shall get the area or areas declared under sub-rule (1), evaluated for quality and quantity of mineral for fixing minimum bid or offer by the Director, Geology and Mining, Uttar Pradesh or by an officer authorised by him before the date fixed for e-tender/ e-auction /e-tender-cum-e- auction

Provided that the District Magistrate, if the need so arises, may, through the technical committee setup by the Government, assess the amount of minor mineral available in the river bed, once in a year, post monsoon. In case of disagreement between parties, the Director, Geology and Mining shall decide the matter and such decision shall be final.

⁴³ **24. Withdrawal of area from e-auction or e-tender or e-auction-Cum-e-tender.**

The State Government may by declaration withdraw any area or areas declared under sub-rule (1) of rule 23 or part thereof from any system of lease referred to therein and from the date of withdrawal specified in the declaration which shall not be the date during the subsistence of a lease granted under this chapter, the provision of chapter II, III and VI of these rules shall become applicable to such area or areas.

⁴³ **25. Register of area or areas declared for for e-tender/ e-auction /e-tender -cum-e- auction lease-**

The District Officer shall cause to be maintained a register of areas declared under sub-rule (1) of rule 23 in Form MM-5.

⁴⁷ **26. Restriction on grant of lease**

No person shall be allowed to bid or take part in *E-Tender/E-Auction/E-Tender cum E-Auction* for a lease-

- (a) Who is not an Indian National
- (b) against whom mining dues are outstanding,
- (c) Who has not obtained a character certificate from the District Magistrate or State Government or the Officer of the District duly authorized by it where he permanently resides, issued on the basis of concerned police verification.
- (d) Who has not produced his Aadhar Card.
- (e) whose name has been mentioned in the Black List.
- (f) In the cases of Firm/Company, which has not produced/furnished its PAN No. and G.S.T. Registration Certificate.
- (g) Who has not submitted solvency certificate or solvency certificate with bank guarantee, of worth not less than 25% of the bid amount.

⁴⁷ **27. Procedure for approval/grant of Lease by E-tender/E-auction/E-tender-cum-E-auction:--**

- (1) Where the granting of lease of e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction is expedient, the District Magistrate or Committee, as the case may be, shall fix the date, time and web portal determined by the State Government for e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction, the procedure of which shall be such as may be determined by the State Government from time to time.
- (2) Lease through e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction shall be granted in the following manner:-
 - (a) The Committee authorized by the District Magistrate or the State Government shall publish public notice at least thirty days earlier to the concerned e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction mentioning inter alia Date, Time and Web-portal determined by the state government for such e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction.
Provided that where e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction, has not been completed due to any reason, whatsoever, such e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction may be completed again after giving short term notice of not less than seven days.
 - (b). The Public Notice of e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction shall be published in the manner given below :-
 - i. copies of the notice shall be displayed/pasted at the notice board of the office of the District Magistrate;
 - ii. copy of the notice shall be displayed on the web portal or website determined by the State Government.
 - iii. The notice shall be published in at least two national newspapers having circulation in the District for the information of general public; and
 - iv. In such other manner as may be directed by the State Government from time to time.
 - (c) The District Magistrate may appoint an officer subordinate to him not below the rank of Additional District Magistrate, as presiding officer, for the purpose of e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction.
 - (d) The details of area or areas and terms and conditions of the lease for e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction shall be mentioned in the notice to be issued.

- (e) Any person, who might be interested in participation with the proceedings concerning e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction, will deposit Rupees Fifteen Thousand as fee which shall be non-refundable as prescribed and provided by the State Government.
 - (f) Every bidder/tenderer desiring to participate in e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction shall deposit such amount as earnest money as specified in the notice.
 - (g) The earnest money deposited by the bidders/tenderers will be returned to them except the successful bidder/tenderer.
- (3) Upon grant of lease, the lease holder of river bed minerals such as sand, morrum, bajri-boulder shall make payment of such amount as mentioned in the fifth schedule and the lease holder of other minerals shall make payment of such amount as mentioned in the fourth schedule.

⁴³ **27A. Omitted**

⁴³ **27B. Omitted**

⁴³ **27C. Omitted**

⁴⁷ **28. Grant of lease** (1) The District Officer or the Committee, as the case may be, shall in the case of e-tender accept the highest offer, in the case of e-auction accept the highest bid and in the case of e-auction-cum-e-tender accept the bid or offer whichever is highest.

(2) The District Magistrate shall declare the highest bid/offer of concerned e-tender/e-auction/e-tender-cum-e-auction and a letter of intent shall be issued to the person whose bid or offer is accepted which shall include:-

- (i) The successful bidder shall immediately deposit 25 percent of the amount of bid as security for execution of the lease deed and due observance of the terms and conditions of the lease and an equal amount as first installment of royalty within two working days. The amount of earnest money will be adjusted into the first installment amount.
 - (ii) *The amount payable for the first year will be determined by multiplying Mineral quantity mentioned in the environment clearance certificate with the rate obtained in the e-tender/e-auction.*
 - (iii) For the subsequent years the amount payable will be increased at the rate of ten percent on the preceding year's payable amount.
 - (iv) **The amount of e-tender/e-auction shall be determined for river bed mineral such as sand, morrum, bajri-boulder as mentioned in the fifth schedule and for other mineral as mentioned in the fourth schedule.**
 - (v) Demarcation of an area granted under lease shall be done in accordance with the provisions of rule-17 and boundary-pillars shall be fixed in accordance with rule 35 and maintenance thereof shall be done in accordance with the said rule.
 - (vi) The conditions of lease shall be mentioned.
- (3) If any bid or offer in e-tender/e-auction/e-tender-cum-e-auction is not satisfactory in the opinion of the District Magistrate, he may reject all the bids and offers in e-tender/e-auction/e-tender-cum-e-auction and order for fresh e-auction or e-tender or e-tender cum e-auction after recording reasons therefore.

⁴³**29. Execution of lease deed** (1) The successful bidder/tenderer after receiving letter of intent of concerned e-tender/e-auction/e-tender cum e-auction shall produce, approved Mining Plan and clean Environment Certificate prescribed as per rule, and a lease deed concerning the same will be executed in form MM-6 or in similar format. The registration of the said

executed lease deed will be registered within three month period. The period of lease will be counted from the date of execution of the concerned lease deed. If due to fault on the part of lease holder, registration of said executed lease deed is not registered within three months, then the said lease deed will be treated as null and void and the amount of security will be seized by the District Magistrate.

(2) Omitted

(3) A copy of the lease deed together with the map of the area shall be sent by the District Officer or the Committee, as the case may be, to the Director Geology and mining, Uttar Pradesh, within fifteen days from the date of execution thereof.

⁴⁷29A Surrender of Mining Lease:-

(1) Lease holder, on the intended day of surrender, shall submit over and above security deposit, an amount equivalent to 25% of the annual instalment of that year and apply for surrender along with the following documents:-

- (a) No objection for transfer of Environment Clearance Certificate obtained for the concerned lease area in favour of the State Government or subsequent proponent.
- (b) Certificate of money deposited for difference between quantity mentioned in Environment Clearance and mined out quantity or in case of no difference, a Certificate in this regard for the concerned lease issued by Mines Officer/Mines Inspector.

In accordance with the above, lease holder will be prohibited from carrying out mining activities from the date of application for surrender of lease and the area will be deemed to be vacant.

¹⁷30. Register of lease

A register of mining lease shall be maintained in the office of the District Officer in Form MM-7 and a copy there of shall be sent by the District Officer to the Director, Geology and Mining, Uttar Pradesh.

CHAPTER - V

CONDITIONS OF A MINING LEASE

⁴³31. Conditions mentioned in this Chapter to apply to all leases-

Every mining lease shall be subject to the conditions mentioned in this chapter which shall be deemed to be incorporated in every mining lease granted under these rules.

32. Discovery of other minerals

- (1) The lessee shall report to the State Government the discovery in the leased area of any minerals not specified in the lease, within thirty days of such discovery.
- (2) If any mineral not specified in the lease is discovered in the leased area the lessee shall not win and dispose of such mineral unless a separate lease is obtained therefore.

33. Foreign national not to be employed:

Except with the prior approval of the State Government, the lessee shall not employ in connection with the mining operations any person who is not an Indian national.

⁴⁷ **34. Mining operations to commence within six months -**

- (1) The 'Selected Applicant' before the execution of mining lease deed under the provision of chapter II, IV and IX or issuing a mining permit under chapter VI of these rules, shall get prepared a mining plan by the person, recognized and registered by the Director, having the qualification and experience namely:-
 - (i) a degree in Mining Engineering or post-graduate degree in Geology granted by university established or incorporated by or under Central Act or a Provincial Act or a State Act, including any institution recognized by the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956; and
 - (ii) Professional Experience of 05 years of working in a Supervisory Capacity in the field of mining after obtaining the degree.
- (2) The Selected applicant shall, within one month of issuance of letter of intent, submit the mining plan for approval to the Officer authorized by notification in this behalf by the State Government, who may within thirty days from the date of receipt of mining plan approve, modify or reject it positively. The project proponent shall, within one month of approval of mining plan, submit the application for grant of Environment Clearance to the competent authority.
- (3) The mining plan once approved shall be valid for entire duration of the mining lease/permit or for five years whichever is earlier. If the lease period is more than five years, then in that case the lease holder will resubmit mining plan before the Officer authorized by notification in this behalf by the State Government.
- (4) Mining operations shall in respect of all minor mineral be undertaken in accordance with the mining plan, detailing yearly development schemes, aspect of reclamation and rehabilitation of mined out areas including progressive mine closure scheme duly approved by the Officer authorized by notification in this behalf by the State Government.

Provided that the lessee shall start the mining operation after obtaining environmental clearance if required under the provisions of Environment Impact Assessment Notification, dated September 14, 2006 issued by the Ministry of Environment, Forest and climate change, Government of India as amended from time to time. During the process of grant of Environment clearance, the proponent shall be bound to complete all desired formalities to resolve the objections raised by the competent authority within the required time frame.

Provided further that an application seeking prior environmental clearance in all cases shall be made by the project proponent or end-user agency as the case may be, in as provided in Paragraph 06 of the Environment Impact Assessment Notification, dated September 14, 2006 as Amended from time to time.

- (5) The mining lease deed will be executed only after approval of mining plan by the Officer authorized by notification in this behalf by the State Government *and within one month from the date of issuance of environment clearance certificate in favour of the proponent*. Mining operation shall commence, immediately for the lessee of river bed mineral, within 03 (three) months from the date of the execution of the lease deed by the lessee of other minor minerals and the lessee shall thereafter conduct such operations without deliberate intermission in a proper, skillful in work-man like manner.
- (6) Financial assurance has to be furnished by every lease holder. The amount of financial assurance shall be Rupees Twenty five thousand for insitu-rock deposit and Rupees Fifteen thousand for sand or morrum or bajari or boulder or any of these in mixed state exclusively found in the river bed mines per acres of the mining lease area put to use for mining and allied activities. However, the minimum amount of financial assurance to be furnished in any of the forms referred to in sub-rule (7) shall be Rupees Two Lacs for each category of mines be respective of area.

Provided that a lease holder shall be required to enhance the amount of financial assurance with the increase in the area of mining and allied activities.

Provided further that where a leaseholder undertakes reclamation and rehabilitation measures as part of the progressive closure of mine, the amount so spent shall be reckoned as sum of the financial assurance already spent by the leaseholder and the total amount of financial assurance, to be furnished by the lessee, shall be reduced to that extent.

- (7) The Financial assurance shall be submitted by the lessee before the execution of lease deed in one of the following forms to the District officer or the officer authorised by the State Government in this behalf, as the case may be, or any amendment to it.
 - (a) Letter of Credit from any Scheduled Bank;
 - (b) Performance or surety bond;
 - (c) any other form of security or any other guarantees acceptable to the competent authority.
- (8) Release of Financial assurance shall be effective upon the notice given by the lessee for the satisfactory compliance of the provisions contained in the mine closure scheme and certified by the District Officer or the Officer authorised by the State Government in this behalf, as the case may be.
- (9) If the district Officer or the Officer authorised by the State Government in this behalf, has reasonable grounds for believing that the protective, reclamation and rehabilitation measures as envisaged in the approved 'mine closure scheme' as given in mining plan in respect of which financial assurance was given has not been or will not be carried out in accordance with the 'mine closure scheme' either fully or partially, the District Officer or the Officer authorized by the State Government in this behalf shall give the lessee a written notice of his intention to issue the orders for forfeiting the sum assured at least thirty days prior to the date of the order to be issued.
- (10) Within the thirty days of the receipt of notice referred in sub-rule (9), if no satisfactory reply has been received in writing from the lessee, the District Officer or the Officer authorised by the State Government in this behalf, as the case may be, shall pass an order for forfeiting the surety amount and a copy of such order shall be endorsed to the State Government.
- (11) Upon the issuance or order by the District Officer or the officer authorised by the State Government in this behalf, the State Government may realise any letter of credit or bond or any other surety, guarantee provided or obtained as financial assurance for the purpose of performance of protective reclamation, rehabilitation measures and shall carry out those measures, or appoint an agent to do so.

Explanation: for the purpose of this rule mining operations shall include the erection of machinery, use of machine laying of a tramway or construction of road in connection with the working of the mines.

43 35. Demarcation of leased area, erection of boundary marks, determination of coordinates and their maintenance:-

- (1) At the time of the survey and demarcation of the area granted under the lease the coordinates will be marked on the demarcating map of the concerned mining lease area and earlier to the execution of lease deed, lessee at his own expense, erect and at all times maintain and keep in good repair boundary marks and pillars necessary to indicate the demarcation shown in the plan annexed to the lease deed.
- (2) The mining lease holder whose mining lease area is more than five hectare, will construct, at his own expenses, check Post/gate for observations of the vehicles transportation with accommodations/installation of four C.C.T.V. Camera capable of recording visuals at the 360 degree angle. The lease holder will also keep R.F.I.D. Scanner at the said check post/gate to facilitate read and save data of bar code scribed over e-form M.M. – 11 issued against each and every vehicles used for transportation of the concerned mining leased area

and will care properly and maintain in working condition at all point of time. The lease holder shall preserve the entire recordings done by the said C.C.T.V. Cameras and R.F.I.D. Scanners at least for the thirty days and will produce the said recordings before the authorized officer as provided under the provisions of rule 66.

36. Maintenance of correct accounts of minerals

The lessee shall keep correct accounts showing the quantity and other particulars of all minerals obtained and dispatched from the mine, giving mode of transport registration number of vehicle, person incharge of vehicle or animal and nature and quantity of minerals carried, the prices and all other particulars of all sales of mineral, the number and nationality of persons employed therein, and complete plans of the mine, and shall allow any officer authorised by the Central or the State Government in this behalf to examine at any time any accounts, plans and records maintained by him and shall furnish to the Central or the State Government or any officer authorised by either in this behalf, may require.

37. Maintenance of record of trenches, pits, etc

The lessee shall keep accurate records of all trenches, pits and drilling made by him in the course of mining operations carried on by him under the lease, and shall allow any officer authorised by the Central or the State Government to inspect the same. Such records shall contains the following particulars, namely:

- (a) The sub-soil and strata through which such trenches, pits or drilling pass:
- (b) Any mineral encountered
- (c) Such other particulars as the Central or the State Government may, from time to time, require.

38. Lessee to strengthen, support, etc.

The lessee shall strengther and support to the satisfaction of the Railway Administration concerned or the State Government, as case may be, any part of the mine which in the opinion of such administration or Government requires such strengthening or support for the safety of any railway, reservoir, canal, road or any other public works or buildings.

39. Right of pre-emption

- (1) The State Government shall at all times have the right of pre-emption of the minerals or products of minerals won from the land in respect of which the lease has been granted, the price to be paid being the fair market price prevailing at the time of pre-emption.
- (2) In order to assist in arriving at the said price the lessee shall, if so required furnish to the State Government for its confidential information, the description and prices of such minerals or products thereof sold to other customers and of charters entered in to of freight for carriage of the same.

⁴⁷40. Liberties, powers and Privileges of the lessee- Subject to the restrictions and conditions mentioned in rule 41 and the directions issued from time to time, by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change of Government of India, a person holding a

mining lease under these rules may have the liberty, power and privilege which are as under:-

- (a) to enter upon the lands mentioned in the lease and to search for mine, bore, dig, drill or win, work, dress, process, convert, carry away and dispose of the mineral for which the lease is held;
- (b) to make in the said lands any pits, shafts, inclines, levels, waterways or other works;
- (c) The lessee may quarry with the help of machine except in the stream of water, and may also use machine for loading and unloading as per the condition specified in the Environmental Clearance certificate. With prior approval from the District Magistrate the lessee may erect and construct on the land any machinery, plant, dressing, floors, furnaces, brick kiln, workshop, storehouse and other buildings of like nature.
- (d) to make any roads and other ways over the said lands and use and pass over the same;
- (e) to quarry and get stone gravel and other building and road materials and clay and to use the same and to manufacture such clay into bricks or tiles and to use such bricks or tiles but not to sell any such materials, bricks or tiles.
- (f) to use a sufficient part of the surface of the said lands for the purpose of storing or depositing any produce of the mines or works carried on and any tools, equipment, earth and materials and substances dug or raised; and
- (g) subject to the existing rights of others and save as provided in clause (d) or rule 41 to clear undergrowth and brushwood and to fell and utilize any tress or timber standing or found on the said lands, provided that the lessee may be asked by the District Officer to pay for any trees or timber felled and utilized by him at the rates to be determined, having regard to their market value, by the District Officer.
- (h) In the event of disruption of mining operation in the lease area owing to any special circumstances, the District Magistrate with the prior approval of the State Government shall adjust the amount equivalent to the instalment payable during the disrupted period, online against the forthcoming instalment.

⁴⁷41. Restrictions and conditions as to exercise of the liberties, powers and privileges of :

The holder of a lease shall the liberties, power and privileges mentioned in Rule 40 subject to the following restrictions and conditions:

- a. Nothing shall be erected or setup and no surface operations shall be-
 - (1) in or upon any public pleasure ground, burning or burial ground, or any place held (sacred) by class of persons, or house or village site, public road and or other place which may be declared by the District Officer as public place, and
 - (2) In such a manner as to injure or prejudicially affect any building work, property or rights of other persons;
- b. No land shall be used for surface operations by persons, which is already occupied by persons, other than the State Government, for works or purposes not included in the lease;
- c. no right of way, well or tank shall be interfered with;
- d. no entry shall be made on any reserved, protected or vested forest without the previous sanction in writing of the Divisional Forest Officer nor shall any trees or timber be felled, cut or used without obtaining the sanction in writing of that Officer nor otherwise than in accordance with such conditions as the State Government may impose in this behalf;
- e. no mining operation shall be carried on at or to any point within a distance 50 metres from any railway line except with the previous written permission of the Railway Administration concern, or from any reservoir, canal or other public works, such as public roads and buildings or inhabited site except with *the* previous written permission of the District Officer or any other officer authorised by the State Government in this

behalf and otherwise than in accordance with such instructions and conditions either general or special, which may be attached to such permission. The said distance of 50 metres shall be measured in case of railway, reservoir, canal or road horizontally from the outer toe of the Bank or the outer edge of the cutting, as the case may be, and in case of a building horizontally from plinth thereof; Provided that the distance in the case of a village road shall be 10 metres from the outer edge of the cutting; and

Explanation: For the purpose of this sub-rule, the expression 'public road', shall mean a road which has been constructed after being artificially surfaced as distinct from a track resulting from repeated use, and 'village road' will include any track shown in the revenue record as village road;

- f. the existing and future holders of Government lease or permit in respect of any land which is comprised in or adjoins or is reached by the land held by the lease shall be allowed reasonable facilities of the access thereto. In case any loss or damage is caused by such lease or permit-holders by exercise of this liberty a fair compensation (as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the State Government) shall be payable there for by such lease or permit-holder to the lessee;
- g. the lessee is bound to keep vigilance for not polluting the environment of the lease-hold area and nearby area in connection with mining operation and also maintain ecological balance of the area. If at any time it is found that the mining operation are leading to environment pollution or imbalance of ecology, then after giving an opportunity of being heard, the lease may be prematurely terminated.
- h. (1) The lessee shall not do any mining operation beyond the depth of three meters or water level whichever is less in the river bed and no mining shall be carried out in the safety zone so worked out by the District Officer.
Provided that no mining shall be carried out into the water stream with the help of suction machine or the lifter etc.

(2) Lessee/permit holder will display the rate of sale price at the place where e MM-11/MM-11 is issued:

Provided that if in the opinion of the State Government the maximum rate of sale price is to be fixed, it may be directed to the concession holder

- i The lessee shall be bound to undertake the loading of minerals in his approved lease area in accordance with the norms laid down by the Government of India.

42. Lessee to indemnify Government against all claims:

The lessee shall guarantee the payment and pay such reasonable compensation as may be assessed by the State Government for all damage, injury or disturbance which may be done by him in exercise of the powers granted by the lease and shall indemnify and keep indemnified fully and completely the State Government from and against all claims, suits and demands which may be made or brought by any person or persons in respect of any such damage injury or disturbance and all costs and expenses in connection therewith.

43. Lessee to secure and keep in good condition pits, shafts, etc.:

The lessee shall during the subsistence of the lease sufficiently secure and keep open with timber or other durable means all pits, shafts and working that may be made or used in the land and make and maintain sufficient fences to the satisfaction of the State Government, round every such pit, shaft or working, whether the same is abandoned or not, and shall during the same period, keep all working in the land, except such as may be abandoned, accessible and free from water and foul air, as far as possible.

44. Lessee to allow inspection of working:

The lessee shall allow any officer authorised by the Central Government or the State Government in that behalf to enter upon the premises including any building, excavation or land comprised in the lease for the purpose of inspecting, examining, surveying and *making* plans thereof, sampling and collecting any data and the lessee shall with suitable person in his employ and acquainted with the mines and work, properly assist, such officer and his agents, servants and workmen in conducting every such inspection, and shall afford and furnish to them all facilities information, etc. connected with the working of the mines, which they may reasonably require, and shall also conform to and observe all orders and regulations, which the Central Government or the State Government, as a result of such inspection or otherwise, may from time to time see fit to make.

45. Lessee to report accident:

The lessee shall without delay, send to the District Officer a report of any accident, causing death or serious bodily injury or serious injury to property, or seriously affecting or endangering life or property, which may occur in the course or any operations under the lease.

46. Omitted by 20th Amendemnt

47. Omitted by 20th Amendemnt

48. Lessee shall deposit any additional amount necessary:

Whenever the security deposit or any part thereof or any further sum deposited with the State Government in replenishment thereof is forfeited or applied by the State Government pursuant to the power given by these rules, the lessee shall deposit with the State Government such further sum as may be necessary to make good, the deficiency caused by such forfeiture or application.

49. Recovery of expenses incurred by the Government:

If any of the works or matters which, in accordance with these rules, are to be carried out or performed by the lessee be not so carried out or performed within the time specified in that behalf, the State Government may cause the same to be carried out or performed and the lessee shall pay to the State Government on demand all expenses incurred by the State Government in connection therewith. The decision of the State Government as to such expenses shall be final.

50. Refund of security deposits:

After the determination of a mining lease the amount of the security lying in deposit with the State Government and not required to be applied to any of the purposes mentioned in these rules shall be refunded to the lessee ordinarily within a period of six months from the date of the determination of the lease

CHAPTER-VI

MINING PERMIT

51. Restrictions on grant of mining permit:

No mining permit shall be granted to a person who is not an Indian national and for a period of more than six months.

52. Application for grant of mining permit:

An application for the grant of a mining permit shall be submitted in form MM-8, in triplicate, to the District Officer or to such other authority who may be authorised by the State Government to grant such permit. It shall be accompanied by:

- (i) A fee of Rs. 2,000, and
- (ii) Two copies of a cadastral survey map or in case of area not covered by such survey two copies of a topographical survey map, on a scale of at least 4" = 1 mile, on which the area applied for is clearly marked.
- (iii) A character certificate given by the District Magistrate of the district, where the applicant permanently resides.
- ³³(iv) An earnest money in the form of Bank draft, payable in favour of District Officer to the concerned District, equivalent to amount of ten percent of the amount of royalty due on minerals proposed to be mining at the rate prescribed in the second schedule of this rule.

Provided that when mining permit is granted earnest money to be adjusted in the amount of royalty and in other hand if the application of mining permit is rejected the amount of earnest money is returned to the applicant hence forth.

Provided further that if the applicant fail to deposit the amount of royalty within the granted period or fail to execute the mining permit ,then the amount of earnest money is forfeited in the favour of State Government.

⁴⁷52A. Procedure for Grant of Mining Permit on Agricultural Land :

- (1) Notwithstanding anything contained in Rule 72, the bhumidhar of agricultural land may apply for grant of mining permit for removal of *sand or morrum or Bajri or Boulder or any of these in mixed state* accumulated due to flood on his agricultural land in Form MM-8, in triplicate to the District Officer, accompanied by a fee of Rs. 2,000/- (Rupees two thousand) Only, and two copies of a cadastral Survey map on which the area, applied for, is clearly marked.
- (2) The District Officer shall cause an enquiry, if deemed necessary, through concerned Tahsildar and Mines Officer/Mines Inspector on the following points-
 - (a) Whether the *sand or morrum or Bajri or Boulder or any of these in mixed state* have been accumulated on the applied land due to floods;
 - (b) Whether the name of the applicant/applicants is/are recorded as bhumidhars on the applied area;
 - (c) Whether due to accumulation of *sand or morrum or Bajri or Boulder or any of these in mixed state*, the applicant/ applicants is/are suffering loss on account of non utilization of such applied land;
 - (d) Whether such land was utilized for agricultural purposes in the past 05 years;

- (e) Whether the quantity of the minor mineral, applied by the applicant, is available on the applied area;
 - (f) Whether the applied area for mining permit is suitable for mining.
- (3) In the light of aforementioned point wise report submitted by the Tahsilder/Mines Officer or Mines Inspector, as the case may be, the District Officer may grant the mining permit for a period not more than three months in a Fasli year in favour of the bhumidhar, after realizing double the amount of royalty in advance.
- (4) Except above mentioned provisions, the other provisions of these rules will apply mutatis mutandis to the mining permit granted under this rule.

⁴⁹52B. Procedure for grant of permit for mineral found in the process of construction of Building/Development Projects :

- (1) Notwithstanding anything contained in these rules, where any mineral found in the process of construction of any building or a development project has to be extracted in the process of execution of such project, the same shall be disposed off or consumed on a permit issued by the District Magistrate.
- (2) Upon receipt of the application, the District Magistrate may accept or reject the same within one month after site inspection and assessment of the available mineral by the District Mines officer/Mines Inspector.
- (3) The said permit may be granted upon payment of the royalty applicable as prescribed in Schedule-1 of the Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rule 1963.

Provided that non commercial private residential buildings shall be exempted from the above.

Provided further that if the application is not disposed off within the said period, the permit shall be deemed to have been issued upon payment of the amount of royalty of the assessed quantity.

- 53. Disposal of application:** The officer authorised to grant the permit may after making such enquiries as may be deemed necessary, refuse to grant the permit or by an order grant it for the whole or a part of the area applied for and subject to such terms and conditions as the said officer may consider necessary.

Provided that an application for the grant of mining permit for such area which is already held under a lease or mining permit shall be deemed to be premature and shall be refused and the application fee thereon if paid shall be refunded.

²⁶53A. Omitted by 26th amendment.

- ²⁰54. Deposit of royalty** -(1) When an order granting a mining permit has been made under rule 53, the applicant shall, within fifteen days of the communication of the order, deposit the royalty for the total quantity of the mineral permitted in the said order at the rate of the time being specified in the first Schedule to these rules and, if the holder of the permit, due to any reason attributable on his part, could not remove the mineral within the permitted time, any amount deposited as royalty shall not be refunded.

(2) If the applicant fails to deposit the royalty within the period mentioned in sub rule (1) or within such further period, as may be allowed by the officer granting the permit, the order granting the permit shall stand revoked and the fee mentioned in clause (1) of the rule 52 shall be forfeited to the State Government.

²⁰55. Issue of mining permit:

A mining permit in form MM-10 with such additional terms and conditions subject to which the order is made under rule 53 shall be issued to the applicant within fifteen days of the deposit of the royalty in accordance with sub-rule (1) of rule 54 and the permit so issued shall be valid until the date of expiry of the period specified in the permit or till such date when the permitted quantity of the mineral is removed, whichever is earlier.

56. Register of mining permits:

A register of all applications for mining permits, with details of permits issued, shall be maintained in Form MM-9, in the office of District Officer or the officer authorised to grant mining permits.

20th amendment dated 27.08.1994
26th amendment dated 22.08.2004
49th Amendment dated 18.03.2020

CHAPTER VII

CONTRAVENTIONS, OFFENCES AND PENALTIES

⁴²57. **Penalty for unauthorized mining-**

whoever contravenes the provisions of rule 3 shall on conviction be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend up to five years or with fine which shall not be less than of 2 lacs Rupees per hectare and which may extend to five Lacs rupees per hectare of the area, or with both.

⁴⁷58. **Consequences of non-payment of royalty rent or other dues-**

- (1) The State Government or any officer authorised by it in this behalf may **terminate** the mining lease after serving a notice on the lessee to pay within thirty days of the receipt of the notice any amount due or dead rent under the lease including the royalty due to the State Government if it was not paid within fifteen days next after the date fixed for such payment. This right shall be in addition to and without prejudice to the right of the State Government to realise such dues from the lessee as arrears of land revenue.
- (2) Without prejudice to the provisions of these rules, simple interest at the rate of 18 percent per annum may be charged on any rent, royalty, demarcation fee and any other dues under these rules, due to the State Government after the expiry of the period of notice under sub-rule (1).

Provided that the District Magistrate, after adjusting the security money against the total amount due, shall issue recovery certificate for recovery of the outstanding amount.

⁴⁷59. **Consequences of contravention of certain conditions: -**

- (1) The proponent who has received letter of intent however has not produced mining plan or has not applied for grant of Environment Clearance within the stipulated period of one month as per the provisions mentioned in rule-34 shall be liable for penalty of Rs. Ten thousand per day. On failure to deposit the amount of penalty, the same shall be deducted by the District Magistrate from the security money deposited against the concerned lease. *In case the proponent fails to execute the lease deed within one month of obtaining environment clearance certificate, the District Magistrate shall, subsequent to cancelling the letter of intent, forfeit the first installment and security money deposited by the proponent in favour of the State Government.*
- (2) The lessee who does mining works contravening the terms and conditions mentioned in the approved mining plan and clean environment certificate issued as per the provisions provided under rule-34, then he will be liable for penalty at the rate of Rs. 50,000/- per occasion of default that shall be recovered by the District Magistrate.
- (3) If the lease holder disobeys the provisions of rule-35 then penalty at the rate of rupees twenty five thousand per day for each and every default shall be levied by the concerned District Magistrate. In case of default on deposit of such levied penalty the concerned District Magistrate will deduct the said amount from the amount of security deposited against the said mining lease.
- (4) According to the provisions provided under rule 41-H mining work through suction machine/lifter into the water stream will be prohibited. If any lessee is found contravening the provisions of the said rule then he will be liable for penalty at the rate of Rs. five lakh per occasion of contravening act, which will be recovered on the order of District Magistrate or Director, Geology and Mining. On failure to deposit of the above mentioned amount of penalty the same shall be deducted by the District Magistrate from the security money deposited against the concerned lease.

- (5) Any lessee holding a mining lease who commits a breach of any of the conditions provided in rule 44 shall be liable for levy/penalty of Rs. fifty thousand. On failure to deposit the said amount of penalty the same shall be deducted by the District Magistrate from the security money deposited against the concerned lease.
- (6) Where the lease holder fails to conform to the prescribed loading norms, penalty of Rs. 25,000.00 per occasion of default shall be imposed by the District Magistrate. Upon failure to deposit the said penalty, the same shall be deducted by the District Magistrate from the security money deposited against the concerned lease.
- (7) Where the proponent fails to complete all desired formalities for obtaining Environment Clearance as required by the competent authority within the stipulated time frame, District Magistrate may cancel the letter of intent issued in his favour.

⁴⁷**60. Consequences of contravention of rules and conditions of lease generally-**

- (1) In case of any breach or contravention by a lessee of any of these rules or conditions and covenants contained or deemed to be contained in the lease except those relating to payment of royalty, rent or other sums due to the State Government, the State Government may, after giving the lessee a reasonable opportunity to State his case, terminate the lease. The right shall be in addition to and without prejudice to the provisions of rule 59
- (2) If a lease is terminated under sub-rule(1) or rule 58, the lessee may be black listed by the District Officer for such period, not exceeding two years, as he may consider proper which shall be uploaded on the website of the department and during the said period no mineral concession under these rules shall be granted to him. An entry in this regard shall be made in the remarks column of the registers of mining lease or the auction lease, as the case may be.
- (3) If any person other than the mining lease holder or entity held is convicted for the charge of illegal mining/ transportation, then beside the penalty/punishment, name of such person or entity will be listed into the black-list by the State Government and will be uploaded and displayed on the website of the department and no mining lease under this rules shall be granted within such period in favour of the said person or entity.

CHAPTER VIII

MISCELLANEOUS

61. Power to rectify apparent mistakes:

Any clerical or arithmetical mistake in any order passed under these rules by the State Government or any other competent authority or officer may be corrected by the State Government, authority or officer, as the case may be.

Provided that no order prejudicial to any person shall be passed unless he has been given a reasonable opportunity for stating his case.

²³**62. Register to be open to inspection:**

- (1) All registers prescribed to be maintained by these rules shall be open to inspection on payment of a fee of twenty rupees for an entry.

- (2) Certified copy of an entry of the registers referred to in sub-rule (1) and the orders passed by the District officer on any application may be obtained by any person on payment of a fee of -
- (a) Rs. 100.00 for obtaining the copy within seven days, and
- (b) Rs. 200.00 for obtaining the copy within twenty four hours.

Explanation 1: 'An entry' means all entries in respect of one permit or mining lease or auction lease, as the case may be.

Explanation II : The fee shall be paid in the manner prescribed under Rule 64 and the treasury challan shall be accompanied with the application for inspection or for certified copies, as the case may be.

47 63. Change of name, nationality etc.:

- (1) An applicant for or the holder of a mining lease shall intimate to the State Government within sixty days any change that may take place in his name, nationality or other particulars mentioned in the relevant Forms.
- (2) In the case of the death of an applicant / leaseholder, application of the mining lease / executed mining lease will be considered in favour of his legal heir. In this regard, after proper examination, order will be issued by the District Magistrate.

64. Mode of payment of fees and deposit:

Any amount payable under these rules shall be paid in such manner as the State Government may specify in this behalf

65. Facilities for training of students

- (1) Every *owner* agent or manager of a mine shall permit students of mining and geological institutions approved by the State Government to acquire practical training of the mines and plants operated by them and provide all necessary facilities required for the training of such students.
- (2) Applications for training from students of institution teaching mining or Geology should be forwarded to the owner, agent or manager of a mine through the Principal or Head of the institutions. Cases of refusal to provide facilities for practical training by any owner, agent or manager of a mine should be referred to the Director of Geology and Mining, Uttar Pradesh.

66. Power of assessment, entry and inspection

- (1) For the purpose of assessment of royalty and for ascertaining the position of the working, actual or prospective, of any mine or abandoned mine or for any purposes connected with these rules, the District officer or the officer of the Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, not below the rank of Mines inspectors appointed for such purposes by the Director or any other officer authorised in this behalf by the State Government by general or special order may
- (a) enter and inspect any mine
- (b) survey and take measurement in any such mine.
- (c) weigh, measure or take measurement of the stock of mineral laying at any mine.

- (d) examine any document, book, register or record in the possession or power of any person having the control of, or connected with any mine and place marks of identifications thereon and take extracts from or make copies of such document, book, register or records:
- (e) summon or order the production of any such document, book, register or record as is referred to in clause (d)
- (f) summon or examine any person having the control of, or connected with any mine; and
- (g) call for such information or return as may be considered necessary

(2) Every person authorised by the State Government under sub-rule (1) shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code and every person to whom an order or summons is issued by virtue of power conferred by clause (e) or clause (f) of the said sub-rule shall be legally bound to comply with such order or summons, as the case may be.

67. No restriction etc. to be imposed by owner of land on mining operation except demand of compensation:

(1) No person, who has right in any capacity on the land covered by a mining lease or mining permit, shall be entitled to impose any prohibition or restriction on the mining operations by the holder of such lease or permit of such land or to demand any sum by way of premium or royalty for the removal of minor mineral.

Provided that such person shall be entitled to get annual compensation from the said holder of mining lease or permit for the use of surface of the land for mining operations, as may be agreed upon between them.

(2) Where the holder of a mining lease or permit and the owner of the surface of the land could not agree upon the amount of annual compensation and a dispute arises in respect thereof, it shall be determined by the District Officer in such manner that:

(a) in the case of agricultural land, the amount of annual compensation shall be worked out on the basis of the average annual net income from the cultivation of similar land for the past three years, and

(b) In the case of non-agricultural land, the amount of annual compensation shall be worked out on the basis of average annual letting value of similar land for the previous three years:

68. Relaxation of rules in special cases:

The State Government may, if it is of opinion that in the interest of mineral development it is necessary so to do, by order in writing and for reasons to be recorded, authorise in any case the grant of any mining lease or the working of any mine for the purpose of winning any mineral on terms and conditions different from those laid down in these rules.

⁴⁷68A Power of State Government to reserve mines-

(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules, the State Government may, by a written order, reserve any area to a Government organization or any

person/company in the interest of industrial promotion, for mining operation subject to such terms and conditions as may be specified in the said order.

- (2) Upon such reservation, mining lease or mining permit as the case may be for the area so reserved, shall be granted to the Government organization or any person/company in the interest of industrial promotion, in whose favour the reservation has been made subject to such terms and conditions as may be decided by the State Government.
- (3) The mining lease for a period not exceeding 10 years may be granted under this rule, as may be decided by the State Government.
- (4) The Lessee, to whom a lease has been granted under this rule, shall pay to the Government all amount payable by a lessee under these rules and such additional charges as may be decided by the State Government from time to time.

Explanation:- For the purposes of this rule, "Government organization" shall mean a Government department or corporation established under any Central or State Act or a Government company within the meaning of clause (45) of section-2 of the companies Act, 2013 and includes State authorities or organization controlled substantially by Central or State Government.

69. Royalty or dead rent may be collected through a contractor:

- (1) The Government may arrange to collect the royalty or dead rent from the holders of mining leases through a contractor, and such holders when directed by the State Government to do so, shall pay the royalty or dead rent to such contractors at the rates specified in their lease during such period as may be directed.
- (2) The consequences of non-payment to the contractor of royalty or dead rent, as the case may be, by the holders of mining leases shall be the same as on default of payment to the State Government, and the State Government shall in that case, have all the powers for the recovery of the arrears from the lessee and in respect of determination of the lease as provided in these rules.
- (3) The State Government may enter into agreement with any person who is considered suitable, whether by holding an auction or by inviting tenders or in any other manner to collect royalty or dead rent of the holders of mining leases in a specified area during a period not exceeding three years on such terms and conditions as are considered suitable.

⁴⁸ **70. Restriction on transport of the Minerals-** (1) The holder of a mining lease or permit or a person authorised by him in this behalf shall issue a pass in Form MM-11 or Form e- MM – 11 prepared through electronic process to every person carrying, a consignment of minor mineral by a vehicle, animal or any other mode of transport, the State Government may, through the District Officer, make arrangements for the supply of printed MM-11 Form books on payment basis.

- (2) No person shall carry, within the State a minor mineral by a vehicle, animal or any other mode of transport, excepting Railway, without carrying a pass *in Form MM-11/ Form e-MM-11 issued under sub rule (1), valid transit pass issued under rule 7(3) of Uttar Pradesh Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and storage) Rules 2018 or similar valid transit pass issued by any other State.;*

Provided that if the State Government enters into an agreement to collect the Royalty through contractor, receipt of royalty or zero receipt as the case may be shall be issued by such contractor and in such cases carrying out such receipt with Form MM-11/ form e-MM-11 will be mandatory for transportation.

Provided further that the transportation of the mineral will be valid only after the State Government has determined the regulation fees imposed from time to time on the mineral coming from other State.

- (3) Every person carrying any minor mineral shall, on demand by any officer authorised under Rule 66 or such officer as may be authorised by the State Government in this behalf, show the said pass to such officer and allow him verify the correctness of the particulars of the pass with references to the quantity of the Minor Mineral.
- (4) The State Government may establish a check post for any area included in any mining lease or permit and when a check post is so established public notice shall be given to this fact by publication in the Gazette and in such other manner as may be considered suitable by the State Government.
- (5) No person shall transport a minor mineral for which these rules apply from such area without first presenting the mineral at the check post established for that area for verification of the Weight or measurement of the mineral.
- (6) Any person found to have contravened any provision of this rule then the district magistrate will recover penalty of Rs. 25, 000/- (twenty five thousands) and the price of such minor mineral including royalty. After deposit of the entire amount mentioned above the vehicle etc including minor mineral will be released.

71. Delegation:

The State Government may, by notification in the Gazette, direct that any power exercisable by it under these rules, may in relation to such matters and subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification, be exercisable also by such officer or authority subordinate to the State Government as may be specified in the notification.

72. Availability of area for regrant on mining lease to be notified

- (1) If any area, which was held under a mining lease under chapter-II or reserved under section 17-A of the Act, becomes available for regrant on mining lease, the District officer shall notify the availability of the area through a notice inviting for applications for grant of mining lease specifying a date, which shall not be earlier than thirty days from the date of notice and giving description of such area and a copy of such notice shall be displayed on the notice board of his office and shall also be sent to the Tehsildar of such area and the Director.
- (2) The applications for grant of mining lease under sub-rule (1) shall be received within seven working days from the date specified in the notice referred to in the said sub-rule, if, however, the number of applications received for any area is less than three, the District officer may further extend the period for seven more working days and if even thereafter, the number of applications remain less than three, the District officer shall notify the availability of the area a fresh in accordance with the said sub-rule.
- (3) An application for grant of mining lease for such area, which is already held under a lease or notified under sub-rule (1) or rule 23 or reserved under section-17A of the Act and

whose availability has not been notified under sub-rule (1) shall be deemed to be premature and shall not be considered and the application fee thereon if paid shall be refunded.

73. Returns:

- (1) The holder of a mineral concession under these rules, shall submit quarterly return in respect of the preceding quarter in Form MM-12 to the District officer and to the Regional office of the Director, in the second week of July, October, January and April every year.
- (2) Whenever any holder of mineral concession fails to submit the return within the time specified in sub-rule (1) he shall be liable to a penalty of Rs. 2,000.00.

74. Cognizance of offences

- (1) No court shall take cognizance of any offence punishable under these rules except on a complaint in writing of the fact constituting such offence by the District Officer or by any officer authorised by him in this behalf.
- (2) No court inferior to that of a magistrate of the first class, shall try any offence under these rules.

75. Compounding of offence

- (1) Any offence punishable under these rules may, either before or after the institution of the prosecution be compounded by the District officer or by such officer as the State Government may by general or special order authorise in this behalf on payment to the State Government of such sum as such officer may specify.
Provided that in the case of an offence punishable with fine only, no such sum shall exceed the maximum amount of fine, which may be imposed for that offence.
- (2) Where an offence is compounded under sub-rule (1), no proceeding or further proceeding, as the case may be, shall be taken against the offender in respect of the offence so compounded and the offender if in custody, shall be released forthwith.
- (3) The officer compounding the offence under sub-rule (1) shall maintain a register showing the following details:
 - (a) Serial number (by financial year)
 - (b) Name and address of the offender,
 - (c) Date and details of offence.
 - (d) Sum of compounding amount and date of its payment.
 - (e) Signature of the officer with date and seal.

76. Assistance of Police:

The Officer referred to in rule 66 may request for the help of the local police for lawful exercise of his powers under these rules and the local Police shall render all possible assistance, as may be necessary to enable the officer to exercise the powers under these rules.

77. Appeal:

An appeal against an order passed under these rules by the District officer or the Committee shall lie to the Divisional Commissioner within a period of sixty days from the date of communication of such order to the party aggrieved.

78. Revision:

The State Government may, either *suo moto* at any time or on an application made within ninety days from the date of communication of the order, call for the examine the record relating to any order passed or proceeding taken by the District officer, committee, Director or the Divisional Commissioner under these rules and pass such orders as it may think fit.

79. Fees:

The appeal under rule 77 or an application under rule 78 shall be presented in form MM-13 in duplicate and be accompanied with a treasury receipt showing that a fee of twenty five

hundred rupees has been paid in Government treasury to the credit of the State Government under the head specified under rule 64.

CHAPTER- IX

GRANT OF PROSPECTING LICENSE OR MINING LEASE FOR DIASPORE, PYROPHYLITE, FELSPAR, CALCITE, SILICA SAND, CHINA CLAY, QUARTZ, ETC.

(40th Ammendment, 29 June 2016)

80. The provisions of this chapter shall be applicable for diaspore, pyrophyllite, dolomite, felspar, calcite silica sand, china clay, quartz and any other minerals notified by the Government of India, by notification no.S.O. 423(E), dated 10-02-2015 as a minor mineral.

81. The provision of chapters II, IV and VI shall not be applicable to the lease granted under this chapter.

82. Restriction on the grant of prospecting license or mining lease —

No mining lease or prospecting license shall be granted to any person who is not an Indian National.

Explanation - For the purpose of this rule a person shall be deemed to be an Indian National—

(a) in the case of a public company as defined in the Companies Act, 2013 only if a majority of the directors of the company are citizens of India and not less than fifty-one percent the share capital thereof is held by persons who are either citizens of India, or Companies as defined in the Companies Act, 2013;

(b) in the case of a private company as defined in the companies Act, 2013 only if all the members of the company are citizens of India;

(c) in the case of firm or other association of individuals, only if all the partners of the firm or members of the association are citizens of India; and

(d) in the case of an individual, only if he is a citizen of India :

Provided that no mining lease shall be granted unless it is being satisfied that there is evidence to show that the area for which the mining lease is applied for has been prospected earlier or existence of the mineral therein has been otherwise established .

83. Application for grant of prospecting license—

(1) An application in the form MM-15 for grant of prospecting license shall be addressed to the State Government .

(2) The application referred to in sub-rule (1) shall be submitted in quadruplicate to the District Officer or to the officer authorised in this behalf by the State Government. Such officer shall endorse the receipt of the application on all the four copies entering the place, time and date of receipt. One copy shall be returned immediately to the person presenting the application.

(3) The application referred to in sub-rule (1) shall be entered in a register of prospecting license application in form **MM-19**.

84. Application for grant of mining lease—

- (1) An application in form MM-16 for, grant of a mining lease or in Form MM-16 (A) for renewal shall be addressed to the State Government.
- (2) The application referred to in sub-rule (1) shall be submitted in quadruplicate to the District Officer or to the officer authorised in this behalf by the State Government. Such officer shall endorse the receipt of the application on all the four copies entering the place, time and date of receipt. One copy shall be returned immediately to the person presenting the application.
- (3) The application referred to in sub-rule (1) shall be entered in a register of mining lease application in form MM-17.

85. Application fee and deposit for grant of prospecting license—

(1) Every application for grant of prospecting license shall be accompanied by—

- (a) a non refundable fee of ten thousand rupees, other than those specified in rule 101;
- (b) Four copies of the toposheet map on a scale of 1: 50000 which shows coordinates and corresponding cadastral survey map on which the area applied for is clearly marked or four copies of topographical survey map on a scale of at least 4"=1 mile, on which the area applied for is accurately marked;
- (c) a certificate, issued by District Officer or by such officer as may be authorised by the District Officer in this behalf, showing that no mining dues are outstanding against the applicant :

Provided that such certificate shall not be required where the applicant has furnished an affidavit to the satisfaction of **the** state Government, stating that he does not hold or had not held any mining lease of any other mineral concession in the territory of the state.

- (d) a certificate of residence of the applicant;
 - (e) a character certificate given by the District officer of the district, where the applicant permanently resides.
- (2) If the application is not complete in any respect or is not accompanied by the fee deposit or the documents mentioned in sub rule(1) the District Officer or the officer authorised by the State Government in this behalf, shall, by fifteen days notice require the applicant to complete the application in all respects or, to deposit the fee or furnish the documents within such time as may be specified in the notice and if the applicant fails to do so within the specified time, such application shall not be considered.

86. Application fee and deposit for grant of mining lease—

(1) Every application for grant of mining lease shall be accompanied by—

- (a) a non-refundable fee of twenty five thousand rupees, other than those specified in rule 101; and
- (b) Four copies of the topographical survey map on a scale of 1: 50000 with coordinate and corresponding cadastral survey map on which the area applied for is clearly marked or four copies of topographical survey map on a scale of at least 4"=1 mile, on which the area applied for is accurately marked;
- (c) a certificate, issued by District officer or by such officer as may be authorised by the District officer in this behalf, showing that no mining dues are outstanding against the

applicant :

Provided that such certificate shall not be required where the applicant has furnished an affidavit to the satisfaction of the state Government, stating that he does not hold or had not held any mining lease or any other mineral concession in the territory of the state;

(d) certificate of residence of the applicant;

(e) a character certificate given by the District officer of the district, where the applicant permanently resides;

(f) Solvency certificate.

(2) If the application is not complete in any respect or is not accompanied by the fee, deposit or the documents mentioned in sub-rule(1) the District officer or the officer authorised by the State Government in this behalf, shall, by fifteen days notice require the applicant to complete the application in all respects or to deposit the fee or furnish the documents within such time as may be specified in the notice and if the applicant fails to do so within the specified time, such application shall not be considered.

87. Application fee etc for renewal of mining lease-

(1) An application for renewal of mining lease may be made at least six months before **the date** of expiry of the mining lease along with four copies of the map of lease **hold area showing clearly the** area applied for renewal and the provisions of clauses (a) and (c) of sub-rule (1) **of rule 86 shall** *mutatis mutantis* apply .

(2) The State Government may condone the delay cause in making the application for renewal of mining lease after the period specified in sub-rule(1).

88. Enquiry and reports—

The District officer shall, unless he is authorised to grant or renew the mining lease or grant prospecting license cause an enquiry through Senior Mines Officer / Mines Officer / Mines Inspector of the concerned district to be made into all relevant and technical matters and, within two months from the date of receipt of application of mining lease, forward two copies of the application alongwith his report to the State Government or to such other authority as the State Government may authorise in this behalf.

89- Disposal of Application (I) The State Government or the authority authorised by it in the behalf may, subject to the provisions of these rules and after making such further enquiry as it may consider necessary-

(a) in case of application for grant of a mining lease or prospecting licence ,refuse or grant the mining lease for the whole or part of the area applied for and for such period as it may consider proper.

(b) in case of application for renewal of a mining lease, refuse or renew the mining lease for the whole or part of the area applied for and for such period, not exceeding the period of the original lease, as it may consider proper :

Provided that where an application for grant or renewal of a mining lease or grant of prospecting license is refused or the area is reduced, reasons thereof shall be recorded and communicated to the applicant :

Provided further that if the application for the grant of mining lease or prospecting license is not disposed off within 12 months from the date of receipt , it shall be deemed to be refused .

90. Preferential right for prospecting licence or mining lease where area has been declared under rule 104 (1) Where the availability of area/areas are declared by the District Officer for grant of prospecting licence or mining lease under the provisions of rule 104, all the applications received during the period specified in such declaration shall be deemed to be received on the same day and shall be considered simultaneously after taking into consideration matters specified in sub-rule (2) and shall grant the mining lease to such one of the applicants as he/she may deem fit.

(2) The matters referred to in sub-rule (1) are -

- (a) any special knowledge or experience possessed by the applicant.
- (b) an intent to establish any value addition or processing or manufacturing unit.
- (c) The Financial resources of the applicant.
- (d) The nature and quality of the technical staff employed or to be employed by the applicant.
- (e) The conduct of the applicant in carrying out mining operations on the basis of any previous lease or permit and complying with conditions of such lease or permit of the provisions of any law in connection there with; and
- (f) Such other matters, as may be considered necessary by the State Government.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2) leases for one third of the mining areas of Naxal affected villages as declared by the State Government by general order may be granted to the Self Assistance groups containing the members of the local residents where such leases are situated and such one third areas shall be marked for the purpose by the District officer of the district, after seeking such approval from the State Government:

Provided that those Self Assistance groups will be entitled for getting preference under sub-rule (3) in which one third members belong to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/members of the caste traditionally engaged in sand mining such as Mallah, Kewat, etc. and are resident of the same village, where the lease areas are situated.

91. Preferential right for prospecting license where area is not declared for grant under rule 104 shall be as under :-

(1) An application which has been received earlier shall have preference over subsequent application .

(2) If the application is received on same day , the preference shall be decided on following matter :

- (a) any special knowledge or experience in prospecting operation and the nature and quality of technical staff employed or to be employed by the applicant ;
- (b) such other matters as may be considered necessary by the State Government.

92. Preferential right for mining lease where prospecting licence has been granted in respect of any land:- Where a prospecting licence has been granted in respect of any land, the licensee shall have a preferential right for obtaining a mining lease in respect of that land over any other person if the State Government is satisfied that the licensee has—

- (a) undertaken prospecting operations to establish mineral resources;
- (b) not committed any breach of the terms and conditions of the prospecting licence.

93. Extent of area for which a mining lease or prospecting licence may be granted —

(1) Minimum area for grant of a prospecting licence or mining lease for minerals mentioned in chapter IX shall be five hectare.

(2) No mining lease shall be granted in respect of any area which is not compact and contiguous or otherwise not suitable to scientific development :

Provided that in respect of small deposits not suitable to scientific mining in isolated

- patches a mining lease may be granted for a cluster of such deposits without any division.
- (3) No person shall acquire in respect of minor mineral mentioned in this chapter more than 3 mining lease , covering a total area of four hundred hectare .
 - (4) No person shall acquire one or more prospecting licence , covering a total area of five hundred hectare :

Provided further that if the State Government is of opinion that in the interest of mineral development, it is necessary so to do, it may for reasons to be recorded in writing permit any person to acquire one or more mining leases covering an area in excess of the limits mentioned in this rule .

Explanation: For the purposes of these rules, a person acquiring by or in the name of another person a mining lease which is intended for himself shall be deemed to be acquiring, it himself.

94. **Length and breadth of the area to be leased** – The length of an area under a mining lease shall ordinarily not exceed four times its breadth.
95. **Period of mining lease and prospecting license** – (1)A mining lease in respect of minerals shall be granted for a period not less than twenty years and not more than thirty years.

(2) Prospecting license shall be granted for a fixed period of two years .
96. **Security deposit** (1) An applicant for a mining lease shall, before the deed referred to in rule 99 is executed and in such manner as the State Government may by order specify deposit as security, for the due observance of the terms and conditions of the lease, a sum equal to twenty five percent of the annual deadrent of the leased area subject to the minimum of Rs. 50,000.00 (fifty thousand rupees) and no interest shall be payable on such security deposit.

(2) The security deposit for prospecting license shall be Rs. 25,000.00 (twenty five thousand rupees) and no interest shall be payable on such security deposit .
97. **Prospecting license deed to be executed within three month** :- Where an order has been made for grant of prospecting license , the deed in Form MM-3(A) shall be executed within 3 months and the date of commencement of prospecting license shall be effective from the date of execution or within such further period as the District officer or the Committee, as the case may be, allow in this behalf.
98. **Every prospecting license granted under these rules be subject to the following condition:-**
 - (1) The licensee shall pay a prospecting fee of Rupees 100.00 per hectare of land covered by license for each year or part thereof for which the license is granted subject to minimum of Rupees 5000.00, which can be changed from time to time by the State Government.
 - (2) The licensee may win and carry for purposes other than commercial purposes —
 - (a) thirty cubic meter of such mineral without any payment ;
 - (b) hundred cubic meter of such mineral on payment of royalty :Provided that if any quantity in excess of the quantities mentioned above is won and carried away, the State Government may recover the cost of the excess quantity of minerals mentioned in clause(b) above, won and carried away .
 - (3) With the written approval of the State Government, the licensee may carry away quantities of minerals in excess of the limits specified in sub-rule (2) .
 - (4) Save in the case of land in respect of which the licensee is granted a mining lease , the

licensee shall , within 90 days from the date of determination of the licence or the date of **abandonment of the** prospecting operations , whichever is earlier , securely plug all bores and fill up or fence all excavations .

- (5) The licensee shall report to the State Government the discovery-of any mineral not specified in the licence within sixty days from the date of such discovery .
- (6) The licensee shall not transfer his licence except with the previous sanction of the State Government.
- (7) The licensee shall restore , to the extent possible , other flora destroyed by prospecting operation .
- (8) The licensee shall pay to the occupier of surface of land such compensation as may become payable under these rules .
- (9) The State Government may impose such further conditions as may be considered necessary in the interest of mineral development .
- (10) In case of breach of any condition imposed on any holder of prospecting licence under these rules , the State Government may , by order in writing , cancel the licence and / or forfeit the security amount deposited by the licensee under rule 96(2) after giving opportunity of hearing .
- (11) Any security deposit made under rule 96(2) , if not forfeited under these rules , shall be refunded to the applicant after expiry of the licence.
- (12) Every licensee shall maintain account of all expenses incurred by him on prospecting operations and also the quantity and other particulars of all minerals obtained during such operations and their dispatch thereof.
- (13) The licensee shall, after the survey and demarcation of the area granted under the licence and before executing the licence deed, at his own expense, erect and at all times maintain and keep in good repair boundary marks and pillars necessary to indicate the demarcation shown in the plan annexed to the licence deed.
- (14) The licensee shall pay such reasonable compensation as may be assessed by the State Government if any damage, injury or disturbance occurs by any action of the licensee.
- (15) The licensee shall allow any officer authorised under rule 66 or by the Central Government or the State Government in that behalf to enter upon the premises including any building, excavation or land comprised in the lease for the purpose of inspecting, examining, surveying and making plans there of, sampling and collecting any data and the licensee shall with suitable person in his employment and acquainted with the mines and work, properly assist, such officer and his agents, servants and workmen in conducting every such inspection, and shall afford and furnish to them all facilities information, etc..connected with the working of the mines, which they may reasonably require, and shall also conform to and observe all orders and regulations, which the Central Government or the State Government, as a result of such inspection or otherwise, may from time to time deem fit to make.
- (16) The licensee shall without delay, send to the District officer a report of any accident, causing death or serious bodily injury or serious injury to property, or seriously affecting or endangering life or property, which may occur in the course or any operations under the licence.

99. Mining Lease deed to be executed within six month:

- (1) Where an order has been made for the grant of mining lease, a lease deed in Form MM-3 or in a form as near thereto as the circumstances of each case may require, shall be executed within six months of the communication of the said order or within such - further period as the State Government may allow, in this behalf. If no such deed is executed within the aforesaid period due to any default on the part of the applicant, the State Government may revoke the order granting the lease and in that event the application fee and security amount shall be forfeited to the State Government.
- (2) The date of commencement of a mining lease referred to in sub-rule (1) shall be the

date on which the deed is executed under the said sub-rule.

100. Restriction on determination of mining lease — No lessee shall determine a mining lease except after giving a notice in writing of not less than six months to the State Government.

101 Survey of the area licenced or leased –

(1) When a mining lease or prospecting licence is granted, arrangement shall be made by the Director for survey and demarcation of the area granted under the lease or licence for which lessees/ licensees shall be charged at the following rates :

For mining leases :- (1) for areas upto 10 hectares Rs. 10, 000.00

(ii) for areas beyond 10 hectares at the rate of Rs. 500.00 per hectare subject to the minimum of Rs. 15,000.00

For prospecting licence (i) for areas upto 10 hectares Rs. 5,000.00

(ii) for areas beyond 10 hectares at the rate of Rs. 250.00 per hectare subject to the minimum of Rs. 10,000.00

(2) The lessee or licensee shall, after the lease or licence is granted to him , pay the demarcation charges through treasury challan and submit a map of the area granted under the lease or licence, certified by the District Officer, to the concerned Mines officer or to such other officer as may be authorised by the Director in this behalf the Mines officer or the officer so authorised shall, on receipt of the certified map and satisfying that demarcation charges have been deposited, survey and demarcate the area within thirty days from the date of such receipt.

(3) The Mines officer or the officer so authorised may, for the purpose of survey and demarcation of the area, take the help of such officer of the revenue and forest department of the district as he may consider necessary.

(4) If any dispute arises in respect of demarcation of the area, the matter shall be referred to the Director, who shall, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard, decide the matter.

(5) The decision of the Director under sub-rule (4) shall be final.

102 Boundaries below the surface :- The boundaries of the area covered by a mining lease shall run vertically downwards below the surface towards the centre of the earth.

103 Registers : The following registers shall be maintained in the office of the District-office-

a register of applications for prospecting licence in Form MM-19, and

a register of prospecting licence in Form MM-20,

a register of applications for mining leases in Form MM-17, and

a register of mining leases in Form MM-18 .

104 Availability of area for regrant on prospecting licence or mining lease, to be notified- (1) If any area, which was held under a mining lease under Chapter - IX or under Mineral Concession Rules, 1960 or reserved under section 17- A of the MMDR Act., becomes available for regrant on prospecting licence or mining, lease, the District officer shall notify the availability of the area through a notice inviting applications for grant of prospecting license or mining lease specifying a date, which shall not be earlier than thirty days from the date of notice and giving description of such area and a copy of such notice shall be displayed on the notice board of his office and shall also be sent to the Tehsildar of such area and the Director.

(2) The applications for grant of prospecting licence or mining lease under sub-rule (1) shall be received within seven working days from the date specified in the notice referred to in the said sub-rule, if, however, the number of applications received for any area is less than three, the District officer may further extend the period for seven more working days and if even thereafter, the number of applications remain less than three, the District Officer shall notify the availability of this area a fresh in accordance with the said sub -rule.

(3) An application for grant of prospecting licence or mining lease for such area which is already held under a lease or notified under sub-rule (1) of rule 23 or reserved under section 17-A of the Act and whose availability has not been notified under sub-rule (1) shall be deemed to be premature and shall not be considered.